सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

19 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 19 मार्च, 2025 ई॰
चतुर्दश सत्र — 28 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए न, आप भी जानते हैं क्या होता है, बैठिए, बैठिए ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आरा)

(मुद्रित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल, बिहटा में जाम से मुक्ति हेतु निम्नांकित कार्य किए जा रहे हैं:–

(1) विशुनपुरा बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर से किया जा रहा है तथा RHS Carriageway एवं LHS Carriageway का कार्य 30.03.2025 तक पूरा कर दिया जायेगा ।

(2) बिहटा चौराहा पर चौड़ीकरण का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है, जिससे यातायात में सुगमता आई है ।

(3) बिहटा चौराहा से परेव के बीच का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, यद्यपि उक्त पथांश में ट्रैफिक का परिचालन सामान्य बनाये रखने हेतु जगह–जगह पर सर्विस रोड का निर्माण तथा Crash Barrier लगाकर Existing Carriageway को बांटा गया है ।

(4) साथ ही साथ विशुनपुरा से परेव तक के क्षेत्र में जहॉ भी कार्य प्रगति पर है वहां डायभर्सन की उचित व्यवस्था की गई है एवं सूचना बोर्ड का प्रावधान भी IRC मानक के अनुरूप किया गया है ।

(5) बिहटा चौक पर अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया है ।

(6) दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत मनभावन चौक पर Grade Seperator Flyover के निर्माण हेतु DPR Consultant का चयन प्रक्रियाधीन है ।

(7) दानापुर–बिहटा एलिवेटेड पथ का निर्माण कार्य के अन्तर्गत बिहटा चौक पर ऐलिवेटेड पथ एवं तीन तरफ Supplimentary Road का निर्माण होना है ।

इसके अतिरिक्त बिहटा चौक पर लगने वाले जाम को दूर करने हेतु सरकार के स्तर से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । इसी क्रम में वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु नगहर (NH–139) से कैनाल बैंक होते हुए बिहटा चौक के पास NH–922 को जोड़ने वाली पथांश का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है । तदोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर तो आया है और इसमें...

अध्यक्ष : और विस्तार से आया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है लेकिन यह जाम अंतहीन है उसका सिलसिला और जो उत्तर है उस उत्तर में यह है कि वह दीर्घकालिक योजनाएं हैं समय के साथ, वे जब पूरी होंगी तब जाम खत्म होगा इसलिए मैं चाहता हूं कि जाम से मुक्ति दिलाने का काम जो प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है इसलिए मेरा कुछ सुझाव भी है प्रश्न भी है, आपकी अनुमति चाहते हैं ।

अध्यक्ष : हां बोलिए न, पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : जी, सुझाव के साथ है पूरक सर ।

अध्यक्ष : सुझाव तो आप दे देते...

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : हमारा यह है कि कतारबद्ध वाहनों को खड़ा करना...

अध्यक्ष : एक काम करिए न अमरेन्द्र बाबू, सुन लीजिए न । सुझाव आप लिखकर दे दीजिए चूंकि आपकी बात बहुत मानते हैं पथ निर्माण मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : मंत्री जी तो हमारी बात...

अध्यक्ष : इसीलिए आप लिखकर सुझाव दे दीजिए और पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : वे योग्य मंत्री हैं उनसे बहुत कुछ आशा है उम्मीद है । इसमें कहां दो मत है, काम भी करते हैं । जो कतारबद्ध वाहनों को खड़ा करना वहां पर होता है...

अध्यक्ष : माइक पर बोलिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : यह प्रशासन का काम है और वह 3–3, 4–4 के लाइन में खड़ी हो जाती हैं ट्रकें, भारी वाहन, इसके कारण जाम की समस्या बढ़ जाती है और ये जानते हैं यह पुलिस करवाती है तो उस पुलिस को ठीक करना प्रशासन का काम है और शीर्ष के जो अधिकारी हैं वे वहां पर नजर रखें और वहां पर जाएं । ये जो डेड लोड है यानी जो लदी हुई गाड़ियां हैं भरा वाहन ट्रक, वह पुल पर, कोइलवर पुल इतना करोड़ों रुपया का पुल बना है उस पुल पर खड़ी रहती हैं । यह बिल्कुल बंद होना

चाहिए नहीं तो पुल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, सर जानते हैं आप भी तो रहे हैं तो पुल को बचाने के लिए जरूरी है कि उस पर कम से कम डेड लोड न रहे । संबंधित थानों के एस0एच0ओ0 की जवाबदेही तय हो, पटना में भी है, आरा में भी है और अरवल के तरफ भी है, उन पर जवाबदेही तय करके क्या पुलिस कार्रवाई करना चाहेगी नंबर एक हुआ । महोदय, अगर जाम लगता है तो उनके ऊपर सीधे कार्रवाई हो । यह अगर होता है तो जाम से...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : मुक्ति मिलने में बहुत भारी मदद होगी । महोदय ऐसा होता है कि...

अध्यक्ष : हो गया आपका ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि आरा, पटना, सारण और अरवल जिले के आपसी तालमेल के अभाव में जाम की स्थिति बद से बदतर हो जाती है । सारण के तरफ जो पुल बना है उसमें जाम न हो और वह रास्ता भी क्लियर रहे तो उसका उपाय भी सरकार को ढूंढ़ना चाहिए और तालमेल के अभाव के कारण जो अक्सर जाम रहता है उसके कारण ये तीनों जिलों में स्थिति खराब हो जाती है...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : छपरा की ओर से नदी पार कर जाने वाला वाहन 3 जिलों में खड़ा होकर पटना, आरा, अरवल मार्ग को अवरूद्ध कर देते हैं तो क्या सरकार प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा सतत् मॉनिटरिंग कर जाम से राहत दिलाने का विचार रखती है महोदय, यह हमारा प्रश्न है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, अंतिम एक सवाल । पटना जिला में कोइलवर पुल से जो बांध मनेर की तरफ जाता है उसमें 4 बड़ा–बड़ा बेरियर लगा हुआ था, वह सब बेरियर को तोड़ दिया गया है और उसमें बेरियर लगा दिया जाय और उस बांध के सड़क को चौड़ा कर दिया जाय तो एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा । इस प्रकार से हम अभी तत्काल यह कर सकते हैं । हम यह अखबारों का यह देखिए...

अध्यक्ष : नहीं, अखबार मत पढ़िए न । अखबार पढ़े हैं मंत्री जी, हम भी पढ़े हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : 5 जनवरी का है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । बैठिएगा तब न कुछ कहेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : यह हिन्दुस्तान का है महोदय, रोज निकलता है...

अध्यक्ष : आप बैठिएगा तब न कहेंगे मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : 5–5 किलोमीटर तक जाम लगा रहता है...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : इसलिए दीर्घकालिक योजनाएं हैं, सरकार सचेष्ट है लेकिन हम इनका भी चाहते हैं...

अध्यक्ष : सरकार को नहीं बोलने देना है, बैठिएगा तब न मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : तात्कालिक समाधान हो ।

अध्यक्ष : वैसे मैं जानता हूं कि आपकी सारी बात माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से सुना है। माननीय मंत्री जी ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, सरकार के पास भी कई स्तर से इसकी जानकारी है इसलिए हमलोगों ने एक टीम भी चीफ सेक्रेटरी भी इसमें गए थे खुद भी और हमारे डिपार्टमेंट के भी ए0सी0एस0 और बाकी लोग और एन0एच0 के भी अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा हुई । जो बातें हमलोगों ने जवाब में पहले भी दिया है कि जो वैकल्पिक भी है और जो एन0एच0 का काम चल रहा है उसको भी निदेशित किया गया है कि आपको वैकल्पिक मार्ग निकालकर उसको आगे बढ़ाना है । साथ ही साथ जो जिला प्रशासन और प्रशासन की बात कहा है माननीय सदस्य ने जिला प्रशासन को भी इससे संबंधित जानकारी दिया गया है । जिला प्रशासन भी इसके परिवहन विभाग के दृष्टि से दोनों की मॉनिटरिंग कर रही है । जो एक बहुत बड़ा सुझाव माननीय सदस्य ने दिया मैं उसकी भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हमलोगों ने विभाग को यह निर्देशित किया है कि बिहार में किसी भी ब्रिज पर बड़े वाहन को रोकने की व्यवस्था न हो उससे ब्रिज की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आती है तो हमलोगों ने ऑलरेडी विभाग को इसके लिए निर्देशित कर दिया है चाहे वह छपरा–कोइलवर ब्रिज हो चाहे आरा–कोइलवर ब्रिज हो, दोनों ही ब्रिज पर जगह–जगह पर जो बड़े वाहन रूकते हैं उसको अब बंद किया जाएगा और उसके लिए स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग दोनों को आग्रह किया गया है । साथ ही साथ जो दीर्घकालीन योजनाओं की इसमें चर्चा हुई है कि ये बड़े समय के हैं, निश्चित रूप से हमलोगों ने इसमें यह भी विषय रखा है कि जो वैकल्पिक मार्ग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में बिहटा से दानापुर–बिहटा फोरलेन जो पुराना एलाइनमेंट है वह स्वीकृत हो गया है । उसके काम होने से फोरलेन से भी ये जाम की समस्या का निजात होगा । साथ ही साथ जे0पी0 गंगा पथ का जो एलाइनमेंट कोइलवर की तरफ जा रहा है वह भी अपने आप में एक बड़ा वैकल्पिक मार्ग है । इसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, बहुत जल्द उसमें भी हमलोग काम लगायेंगे । इसके अतिरिक्त जो वहां पर जल संसाधन विभाग का एक केनाल है उसमें भी 23 किलोमीटर की योजना है, लंबा स्ट्रेच है उसको भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में हमलोग यूज करने जा रहे हैं । उसके लिए भी जल संसाधन विभाग ने एक प्राक्कलन बनाया है उसमें भी

बहुत जल्दी हमलोग आगे बढ़ेंगे तो ये 3–4 निर्णय जो लंबे समय के लिए हैं और जो तात्कालिक निर्णय लिए गए हैं जो चीजों को प्रशासन को अवगत कराने से लेकर बाकी चीजों पर और जो अल्टरनेट स्ट्रेच बनना चाहिए वैकल्पिक मार्ग का, उसके लिए एन0एच0 को भी कहा गया है और हमलोगों के जो चीफ सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर की जो टीम गई थी उनलोगों ने भी एक रिपोर्ट दिया है, उस पर भी हमलोग काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

अब इसमें क्या होगा ?

(व्यवधान)

अब इसमें क्या होगा, बोलिए ।

(व्यवधान)

बैठिए, बैठिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा संजय तिवारी जी का...

अध्यक्ष : आप अपना बोलिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : सबका वही रास्ता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । थोड़ा सा तो भूमिका बनता है न...

अध्यक्ष : नहीं थोड़ा, इधर–उधर नहीं सीधा पूरक पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : पूरक ही मैं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : और लोगों का भी प्रश्न है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी बक्सर जिला के प्रभारी मंत्री हैं, यह अलग बात है कि...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न ।

श्री अजीत कुमार सिंह : स्कॉट से जाते होंगे...

अध्यक्ष : देखिए मेरी बात सुनिए, अल्पसूचित का समय सीमित है, कई लोगों के प्रश्न हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जाम की समस्या से सरकार भी अवगत है, 6–6 घंटे लगे हैं जाने में...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : बालू लदे हुए ट्रकों से एक तरफ का पूरा लेन जाम कोइलवर से लेकर बक्सर तक रहता है जिसकी वजह से एक ही लेन में चलने की वजह से गाड़ियों के चलते दुर्घटना भी होती है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष : आप नहीं पूछ रहे हैं तो...

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा पूरक सुन लीजिए...

अध्यक्ष : आप नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो बालू लदे हुए ट्रक अनियंत्रित तरीके से खड़े होते हैं उसके जिम्मेदार या तो बालू के ट्रक हैं या प्रशासन है तो जिम्मेदार लोगों पर प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई किया ?

अध्यक्ष : संजय जी बोलिए ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, जाम की समस्या तो है ही एक अल्टरनेट रोड है । कल मैंने विधान सभा में अपने डिबेट के दौरान सभापति महोदय बैठे थे आपके आसन पर, मैंने यह मांग किया था कि जासो–डुमरांव पथ ऐसा एक लिंक रोड है जो कि लाखों लोग उस रास्ते से आते हैं और माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आपके आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह सड़क बन जाती है और निश्चित रूप से...

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : जाम से निजात मिलने का काम डुमरांव और बक्सर के लोगों को हो...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । महा नन्द बाबू बोलिए ।

श्री महा नन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल में तो और जाम से परेशान रहते हैं लोग तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या अरवल में 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक नो इंट्री, बालू वाला कम से कम नो इंट्री लगाने पर विचार रखती है सरकार ?

अध्यक्ष : अभी अरवल आपके इस प्रश्न में नहीं है, शायद जवाब नहीं होगा उनके पास लेकिन माननीय मंत्री जी लोगों की चिन्ता जो है वह आपकी भी चिन्ता है, सरकार की भी चिन्ता है...

(व्यवधान)

बैठिए न, बैठिए महा नन्द बाबू ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए न । सबकी चिन्ता है और आपने जो अपना जवाब दिया है उसमें आपने अपनी चिन्ता को कैसे दूर करेंगे, लोगों की चिन्ता को इसका भी समावेश किया है लेकिन इस चिन्ता से पूरा प्रदेश परेशान है, आप भी परेशान हैं । आप और सकारात्मक ढंग से उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए । आप बैठिए । आप कहां खड़े हो गए ।

टर्न–2 / सुरज / 19.03.2025

अल्पसूचित प्रश्न सं0–13 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, नवीनगर)

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । इसका ऑनलाइन जवाब हमलोगों को अभी नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : कहां ट्रांसफर किया है ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, योजना एवं विकास विभाग में ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : अगली बार आयेगा । श्री देवेश कान्त सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–14 (श्री देवेश कान्त सिंह, गोरेयाकोठी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब तारांकित प्रश्न लिये जाएंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–''क'' 666 (श्री दिलीप राय, सुरसंड)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–''ख'' 840 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)

श्री प्रणव कुमार : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, यह स्थानांतरित हो गया है ।

अध्यक्ष : यह ट्रांसफर हुआ है, अगली बार आयेगा आपका ।

तारांकित प्रश्न सं0–1417 (श्री जनक सिंह, तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थति यह है कि प्रश्नगत पथ दिघवारा–भेल्दी अमनौर–तरैया सिमरी बाँध पथ (एस0एच0 104) है, जिसकी कुल लम्बाई 54.00 कि0मी0 है । वर्तमान में

इस पथ का संधारण OPRMC के तहत किया जा रहा है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

इस पथ का पोखरेरा (चैनेज 42.00 कि0मी0) से डुमरसन गोलम्बर (चैनेज 54.00 कि0मी0) तक कुल लम्बाई 12 कि0मी0 में पथ परत की चौड़ाई 3.75 मी0 है । शेष पथांश में पथ परत की चौड़ाई 7.00 मी0 है ।

तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त 12 कि0मी0 पथांश के चौड़ीकरण कार्य पर विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस0एच0–104 दिघवारा–भेल्दी, अमनौर–तरैया और सिमरी 2005 के पहले...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : यह सड़क, सड़क में रोड की, रोड में गड्ढा वाली कहानी को आपने ही जब पथ निर्माण मंत्री थे...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : तो आप ही के द्वारा इस रोड को स्वीकृत किया गया, जिसमें 54 किलोमीटर यह पथ है । 12 किलोमीटर सिंगल लाईन में रह गया । तरैया में जब बाहर के ट्रक जो आते हैं या भारी वाहन आते हैं तो उसका...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, वही कह रहे हैं 15 किलोमीटर में 3 किलोमीटर तक चौड़ाई हो गया । अब यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर चाहे पश्चिमी चंपारण, चाहे पूर्वी चंपारण या गोपलगंज, सिवान के जब ट्रक जाते हैं तो पूरा जाम लग जाता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : मैं यह चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दो विषय लिखा है, एक तो लिखे हैं कि रोड की स्थिति अच्छी है । संवेदक द्वारा उस रोड का रख–रखाव सही रूप से नहीं होता है तो उस संवेदक पर या पदाधिकारी पर कौन–सा कार्रवाई करना चाहते हैं ?

दूसरा, हम पांच वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण, 12 किलोमीटर का चौड़ीकरण हो जाना चाहिये, चूंकि इस रोड पर थाना है, ब्लॉक है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : इसलिये यह 12 किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण कब तक कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : तीसरा पूरक भी पूछना है क्या ? दो पूरक हो गया तीसरा भी पूछना है ? माननीय मंत्री जी ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सड़क की स्थिति अभी अच्छी नहीं है तो मैं कल ही फ्लाईंग स्कॉट से इसकी जांच करा लेता हूं जो रिपोर्ट आया है वह रिपोर्ट तो सही कहा है लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है तो कल ही हम फ्लाईंग स्कॉट भेजकर इसकी जांच करा लेते हैं । जो 12 किलोमीटर स्ट्रेच की बात है, हमने कहा ही अपने जवाब में की हमलोग प्राक्कलन तैयार करा रहे हैं और संसाधन को देखते हुये निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में इसको कराने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : तीसरा पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्राक्कलन की बात कही । सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके इनके विभाग में महीनों से लंबित है इसलिये हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि क्या जो एक माह के अंदर में प्राक्कलन आया पुनः मंगायेंगे क्या या उसी रोड पर चौड़ीकरण करने के लिये अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा ही है कि अगले वित्तीय वर्ष में संसाधन के आधार पर हमलोग करेंगे, हमने तो कहा ही है यह बात ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1418 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, जहानाबाद)</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, उत्तर नहीं देख पाये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नरेगा सॉफ्ट डैप त्मचवतज से प्राप्त विवरण के अनुसार योजना संख्या 0520018/FP/20373565, 0520018/FP/20373566 एवं 0520018 /FP/20392172 की स्थिति Ongoing योजना के रूप में प्रदर्शित हो रही है, जिसकी स्वीकृति देने में निर्धारित मानदंडों, प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। योजनाओं की स्वीकृति में कोई हेराफेरी एवं गबन नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, इसमें पूरा उसकी योजना संख्या और पत्रांक, दिनांक के माध्यम से सवाल पूछा गया है...

अध्यक्ष : जवाब भी मंत्री जी ने उसी के हिसाब से दिया है । पूरक पूछिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जब सारा चीज दिया दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि उत्तर अस्वीकारात्मक है । यह जो हमलोग जांच कराने की मांग किये हैं तो सरकार अगर इस तरह करेगी तो लोकल स्तर पर जो अधिकारी हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न क्या चाहते हैं ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : हम वही चाहते हैं कि इसको फिर से जांच कराकर के दोषी पर कार्रवाई की जाए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो तीन योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं पर अभी काम ही चल रहा है । यह पहली जो योजना है वह रजनीकांत कामत के खेत से हटनी सीमा तक तटबंध की मरम्मती का काम है । 9 लाख 11 हजार 766 रुपये का प्राक्कलन है । 7 लाख 19 हजार 479 रुपया अभी इसमें व्यय किया गया है और 2 हजार 976 मानव दिवस श्रृजन किया गया है और कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति है तो अभी तो कार्य ही चल रहा है ।

दूसरी भी योजना है राजेन्द्र कामत के घर से पश्चिमी जीवत कामत के खेत तक तटबंधी की मरम्मती का है । 9 लाख 54 हजार 017 रुपये की यह हमारी योजना है और इसमें व्यय 2 लाख 23 हजार 943 रुपया किया गया है । 2 हजार 109 मानव दिवस श्रृजन किया गया है और पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी है ।

तीसरी जो योजना है वार्ड नंबर–8 परशुराम यादव पोखर से रेलवे तक तटबंध की मरम्मती है । 9 लाख 49 हजार 989 हजार की योजना है, प्राक्कलित राशि है । 01 लाख 64 हजार 671 इसमें अभी तक व्यय किया गया है और मानव दिवस 689 श्रृजित किया गया है । ये भी पंचायत समिति की योजना है और ये तीनों योजना 2024–25 की है तो इसमें अभी गबन का और प्रक्रिया का इधर–उधर का कोई सवाल नहीं है । माननीय सदस्य को तो संतुष्ट होना चाहिये कि इतना स्पष्ट उत्तर हमने दिया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1419 (श्री लखेंद्र कुमार रौशन, पातेपुर)</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : (लिखित उत्तर) अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पातेपुर प्रखंड के पंचायत राघोपुर नरसंडा अंतर्गत शिव मंदिर से अहरा टोला होते हुए शहीद मौजे सहनी के घर से राजकिशोर मिश्र के घर तक पथ की लम्बाई 0.800 कि0मी0 है, जिसमें पंचायत द्वारा ईंटीकरण (210 मीटर) एवं PCC कार्य कराया गया है। राजकिशोर मिश्र के घर को PMGSY मालपुर से असमा नीरपुर अजीजपुर चाँदे होते हुए अमथामा सीमान तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है।

प्रश्नाधीन पथ का पथांश शिव मंदिर से अहरा टोला होते हुए शहीद मौजे सहनी के घर से मिडिल स्कूल नरसंडा पथ का प्राक्कलन सुरेन्द्र राय के घर से

मिडिल स्कूल नरसंडा पथ के नाम से MMGSY (AWSESH) अन्तर्गत तैयार किया गया है, जिसकी लम्बाई 1.50 कि0मी0 है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है लेकिन वही उत्तर प्राप्त है जो पिछली बार भी हमने प्रश्न किया था । इसी प्रकार एक उत्तर आया था लेकिन यथावत वही उत्तर आज भी है । मेरा है कि पातेपुर प्रखंड के राघोपुर नरसंडा पंचायत अंतर्गत शिव मंदिर से शहीद मौजे सहनी के घर तक । महोदय पाक युद्ध में शहीद मौजे सहनी जी शहीद हुये थे लेकिन आज भी उनके घर तक का सड़क बनने का इंतजार कर रही है और पिछले दो बार मेरा क्वेश्चन हुआ है। माननीय मंत्री जी का जवाब यह है कि इसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं चूंकि शहीद का परिवार आज भी इंतजार कर रहा है उस सड़क का...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : यह सड़क, यह स्वीकृति की प्रक्रिया कब तक पूर्ण होकर वह शहीद मौजे सहनी जी के घर तक सड़क बन जायेगी ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह 1.5 किलोमीटर की सड़क है और डी0पी0आर0 तैयार पड़ा हुआ है और हमलोग स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं जैसे ही स्वीकृति होगी इसको बना दिया जायेगा ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, हमने कहा कि पिछली बार भी हमने प्रश्न किया था, उसका आंसर सामने है । उस समय भी यही जवाब आया था कि स्वीकृति की प्रक्रिया में है, प्राक्कलन तैयार कर ली गयी है । आज भी महोदय...

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं कि गलत जवाब आ जाये, जवाब तो सही ही न आयेगा ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, आपका संरक्षण चाहिये । आज भी उस शहीद के टोले तक सड़क नहीं बनी जबकि यह सच्चाई है कि बगल का सारा सड़क बन गया । हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, यह एन0डी0ए0 की सरकार है पूरी सड़क बन गयी है लेकिन यह शहीद के टोले तक जो सड़क नहीं बनी । मंत्री जी यह जवाब दे रहे हैं कि प्राक्कलन तैयार हो गयी है । क्या यह सड़क इसी वित्तीय वर्ष में बन जायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दे दीजिये ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : ठीक है महोदय ।

टर्न–3 / राहुल / 19.03.2025

अध्यक्ष : हो गया । श्री ऋषि कुमार ।

(व्यवधान)

यहां से निर्देश देने का अधिकार है मुझे । यह जानकारी पूछ लीजिये अवध विहारी बाबू से ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, हम माननीय मंत्री जी को और आपको धन्यवाद देते हैं । माननीय मंत्री जी इसी सत्र में बना देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–1420 (श्री ऋषि कुमार, ओबरा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत फॉल सोनवर्षा वितरणी के 25.76 आर0डी0 से निसृत सागरपुर जलवाहा के 1.50 आर0डी0 पर अवस्थित है। वर्त्तमान में फॉल तथा इसे अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में नहर के दोनों बांध में आंशिक मरम्मति की आवश्यकता है। इसके लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महोदय, जवाब यही है कि माननीय सदस्य का कहना सही है जो ओबरा में कलेन पर फॉल है उसमें मरम्मती की आवश्यकता है जैसा कि आपने प्रश्न में कहा है । हम उसका प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में जो मात्र आज से 12 दिन के बाद प्रारंभ हो रहा है उसमें इस काम को करा दिया जायेगा ।

श्री ऋषि कुमार : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–1421 (श्री सुधांशु शेखर, हरलाखी)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन योजना का कार्य प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, बिहारशरीफ प्रखंड के दीपनगर, नवीनगर, उमेदनगर, जोरारपुर, डुमरावं, गोलापुर से सिंचाई पईन पूरी तरह गाद से भरी हुई है जिसकी सिंचाई कार्य हेतु सफाई की आवश्यकता है । इन गांवों में नाला का पानी घरों में घुस जाता है । कभी–कभी सड़क पर नाले का पानी भी आ जाता है...

अध्यक्ष : सुधांशु जी पूरक पूछिये ।

श्री सुधांशु शेखर : यह कब तक हो जायेगा समय–सीमा निर्धारित की जाय ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका सर्वेक्षण करा लिया गया है और प्राथमिकता के आधार पर निधि की उपलब्धता में अगले वित्तीय वर्ष में इसको करा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1422 (श्रीमती अरूणा देवी, वारिसलीगंज)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, वारिसलीगंज प्रखंड के झौर मोड़ से कोचगॉव पी0डब्लू0डी0 पथ की लम्बाई 2.40 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.05 मी0 है । वर्तमान में यह पथ OPRMC अन्तर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण के साथ नाला निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये अरूणा जी ।

श्रीमती अरूणा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वारिसलीगंज प्रखंड में जो झौर मोड़ से कोचगांव तक 5 किलोमीटर पी0डब्लू0डी0 की सड़क है और वहां नाला सहित चौड़ीकरण होना है तो यह कब तक मंत्री जी करवायेंगे ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि हम इसका प्राक्कलन तैयार कराते हैं और जो संसाधन की उपलब्धता रहेगी उसके आधार पर प्राथमिकता देते हुए करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1423 (श्रीमती नीतु कुमारी, हिसुआ)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, हिसुआ–नवादा पथ (हिसुआ–नवादा–पकरीबरावॉ पथ (SH&8)) जिसकी लम्बाई 45. 30 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7.00 मी0 है। यह पथ OPRMC अन्तर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये नीतु जी ।

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, मेरा पूरक यही है कि यह जो रोड के बारे में जवाब मिला है कि संसाधन उपलब्ध रहेगा तो बनेगा । मैं मंत्री जी से आग्रह कर रही हूं यह रोड बहुत जरूरी है और मात्र 12 किलोमीटर रोड है, हमेशा जाम रहता है और दोनों तरफ फोर लेन सड़क बनी हुई है एक्सीडेंट भी होता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती नीतु कुमारी : इसलिए इसको देखते हुए बना दिया जाय तो जनता का कल्याण हो जायेगा । कब तक बना दिया जायेगा ? प्रगति यात्रा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं आवेदन दी थी कि यह रोड बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने चूंकि अभी ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत संभावित सड़क है ऑलरेडी सड़क की स्थिति अच्छी है हां यह जरूर है, माननीय सदस्या ने कहा कि चौड़ीकरण करने के लिए, उसके लिए प्राक्कलन हम मंगवाते हैं उसके आधार पर निर्णय करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1424 (श्री बीरेन्द्र सिंह, वजीरगंज)</u>

अध्यक्ष : श्री बीरेन्द्र सिंह, पूरक पूछिये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : आपने देखा नहीं होगा ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : महोदय देखे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन जवाब पढ़ दीजिये । क्योंकि जब मेरे पास आ गया तो आपके पास कैसे नहीं आयेगा ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के निकटवर्त्ती प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता के पद हेतु अपेक्षित कलावधि पूरी नहीं करते है। इस कारण लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के कार्यपालक अभियंता, जो अपेक्षित कलावधि पूरी करते है, को लघु सिंचाई अंचल, गया के अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अभी जो जवाब पढ़े हैं यह जवाब सही नहीं है और...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गया में पहले से जो अभी अधीक्षण अभियंता बनाये गये हैं, 2019–2023 तक चार साल गया में कार्यपालक अभियंता रह चुके हैं । दूसरा है अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर में इनके ऊपर गबन का आरोप भी है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उसके बाद भी इनको, और प्रमोशन भी इनको नहीं मिला है, इनके बैच के सारे पदाधिकारी को लेकिन उसके बाद भी मंत्री महोदय क्या जवाब देना चाहेंगे कि कब तक इनकी जगह पर दूसरे पदाधिकारी की वहां पोस्टिंग की जायेगी ? अभी इन पर गबन का आरोप है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि आप निकटवर्ती किसी कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता क्यों नहीं बनाये जैसे गया उन्होंने उदाहरणस्वरूप बोला लेकिन अनुभव के आधार पर जिनके बारे में यह प्रश्न कर रहे हैं, 2008 की उनकी नियुक्ति है और 17 वर्ष उनको हो चुके हैं । अभी हमारे विभाग में अधीक्षण अभियंता के टोटल पद 17 हैं जिसमें 9 लोग कार्यरत हैं और 9 में एक जो गया खाली था तो जो सबसे अनुभवी व्यक्ति थे उनको वहां पर अधीक्षण अभियंता के रूप में प्रभार दिया गया है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सवाल किया उनके बारे में गया के जो कार्यपालक अभियंता हैं उनको 5 साल अभी हुए हैं, 2014 बैच के वे हैं और स्केल 9 से 11 में आने के लिए 5 वर्ष चाहिए और 11 से 13 में 10 वर्ष चाहिए और जिनकी नियुक्ति की गयी है उनका 17 वर्ष किया गया है तो नियमानुकूल नियुक्ति की गयी है । जहां तक आरोप की बात है तो आरोप पर विभाग में विभागीय कार्रवाई चलती रहती है और विभागीय कार्रवाई के अनुरूप उनको दंडित भी किया जाता है । महोदय, वह अलग मामला है । यह मामला नियुक्ति का है जो नियमसंगत की गयी है और विभागीय आदेश के आलोक में की गयी है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । इनका प्रमोशन भी नहीं हुआ है ये कार्यपालक अभियंता में पोस्टेड थे और उसके बाद भी इन पर गबन का आरोप है और उसके बाद...

अध्यक्ष : आपने उसके बारे में प्रश्न नहीं किया है । आपने केवल...

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या गबन के आरोप की जांच कराकर आरोप सिद्ध हो गया है और उसके बाद भी अधीक्षण अभियंता के पद पर गया में ही 6 महीने के अंदर कार्यपालक अभियंता के बाद 6 महीने के अंदर में गया में ही इनकी क्यों पोस्टिंग की गयी । क्यों की गयी क्या मंत्री महोदय इसका जवाब दे सकते हैं ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया से पटना नजदीक होता है इस कारण से और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जहां तक गबन की बात कर रहे हैं वह जांच का विषय है और उन पर गबन का आरोप सिद्ध होगा तो निश्चित तौर पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी । इसमें प्रतिनियुक्ति का कोई मामला नहीं है।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सिद्ध हो गया है अध्यक्ष महोदय । गबन का आरोप ।

अध्यक्ष : बैठिये न । श्री भीम कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–1425 (श्री भीम कुमार सिंह, गोह)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत पचरूखिया देवहरा मुख्य पथ से कोईलवां, चनहर होते हुए पौथू तक सड़क, पथ प्रमंडल सं0–1, औरंगाबाद के अधीन है ।

गया कोईलवां पथ भाया परैया, गुरारू, रफीगंज, पौथु पथ तक की 49.213 कि0मी0 से 70.725 कि0मी0 की कुल लम्बाई 21.037 कि0मी0 एवं चौड़ाई 5.50 मी0 है । इस पथ का निर्माण RCPLWE. योजनान्तर्गत कराया गया है, जो वर्तमान में Maintenance में होने के कारण पथ की मरम्मति समय–समय पर हो रही है, जिसके गुणवत्ता की जॉच समय–समय पर State Quality Monitoring, National Quality Monitoring दल द्वारा किया जाता है।

200 मी0 लम्बाई में नाला का निर्माण कराया गया है। शेष स्थानों पर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नाला का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, यहां पांच साल पहले टेंडर हुआ था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भीम जी पूरक पूछिये ।

श्री भीम कुमार सिंह : माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । महोदय, समय–समय पर जांच की गयी है तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि किस पदाधिकारी द्वारा, कब–कब जांच की गयी तथा किस पत्रांक, दिनांक से जांच कमेटी बनायी गयी । महोदय, नाला बनाने की जो बात है, जमीन वहां उपलब्ध है परंतु सरकार के जवाब में आया है कि जमीन नहीं है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करा लें और जमीन वहां उपलब्ध है, अगर वहां जमीन उपलब्ध है तो वहां नाला बनवाया जाय ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जांच की बात की है तो स्टेट क्वालिटी मॉनिटर और नेशनल मॉनिटर दोनों द्वारा, चूंकि RCPLWE की यह योजना है तो दोनों ही संस्थानों द्वारा इसकी जांच करायी गयी है, जांच की रिपोर्ट भी हमारे पास है । दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है कि नाले का निर्माण तो उस समय जमीन की उपलब्धता नहीं का जवाब आया था अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जमीन उपलब्ध है तो राशि इसमें शेष है हम माननीय सदस्य से जानकारी लेते हुए वहां नाला का निर्माण कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1426 (श्री निरंजन कुमार मेहता, बिहारीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि माली साढ़ बराज पैमार नदी बेसिन में स्थित है जिससे निःसृत बायां मुख्य नहर एवं दायां मुख्य नहर से इस्लापुर, राजगीर एवं वेन प्रखंड के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । वर्तमान में पैमार सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है जिनके अंतर्गत माली साढ़ बराज के 500 मी0 अपस्ट्रीम में गाद निकालने का प्रावधान है जो कार्य प्रगति पर है जिसे जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : श्री निरंजन कुमार मेहता, पूरक पूछिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें भी प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने जो कहा है माली साढ़ बराज के अप स्ट्रीम में गाद जमी है, सफाई होनी चाहिए । हमने प्राक्कलन तैयार करा लिया है और इसी वर्ष जून महीने से पहले यानी बरसात शुरू होने से पहले गाद सफाई करा दी जायेगी ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0–1427 (श्री ललन कुमार, पीरपैंती)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1428 (श्रीमती ज्योति देवी, बाराचट्टी)

अध्यक्ष : आपका प्रश्न वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में ट्रांसफर हुआ है । अगली बार आयेगा ।

श्रीमती ज्योति देवी : ठीक है महोदय ।

टर्न–4 / मुकुल / 19.03.2025

तारांकित प्रश्न संख्या–1429 (श्रीमती गायत्री देवी, परिहार)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथांश NH–77 का Left Out Portion (Old Alignment) है, जिसकी कुल लम्बाई 8.70 कि0मी0 है तथा चौड़ाई 5.50 मी0 है । तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : गायत्री जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि सड़क की लंबाई 8.70 किलोमीटर है और चौड़ाई 5.5 मीटर है । वहां पर लम्बाई से कोई मतलब नहीं है और सिर्फ चौड़ाई से मतलब है । सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड का बड़ा बाजार है, रोड के दोनों तरफ नाला है, सिर्फ 5.5 मीटर में क्रॉस नाला बनाना है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, आपका सब रोड बनाया हुआ है, जब आप मंत्री थे उसी समय का रोड है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका जो प्रश्न है, क्या आपका 30 फीट में केवल नाला बनाना है ?

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, नाला और जो बचा हुआ है जो क्रॉस है, मैं मंत्री जी से पूछती हूं कि सोनबरसा एन0एच0–77, ओल्ड एलायमेंट में कब तक क्रॉस नाला का निर्माण करवा देंगे । अध्यक्ष महोदय, वह बना हुआ है और जो बाकी है उसी को बनाना है ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने क्रॉस ड्रेन की जो बात की है उसको अगले वित्तीय वर्ष में हम करवा देंगे । साथ ही साथ जो इसका एप्रोच नाला है, जो आउटफॉल होना चाहिए, उस आउटफॉल को लेकर तकनीकी रिपोर्ट हमलोग मंगा लेंगे, यह 30 फीट का जो क्रॉस ड्रेन है वह हम अगले वित्तीय वर्ष में करवा देंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इसे इसी वित्तीय वर्ष में बनवा दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उन्होंने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में करवा देंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, चुनाव का भी समय आ गया है, थोड़ी सी भी बारिश आती है तो बहुत परेशानी होती है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1430 (श्री मुकेश कुमार रौशन, महुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–3466, दिनांक– 11.06.2013 द्वारा जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य तथा पंचायत समिति, प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्यों को पूर्व में स्वीकृत नियत (मासिक) भत्ता को विभागीय संकल्प संख्या–2517, दिनांक–05.05.2015 तथा मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को विभागीय संकल्प संख्या– 479, दिनांक–15.01.2024 द्वारा वृद्धि की गयी है :–

क्र०	जनप्रतिनिधियों का पदनाम	वर्तमान नियत (मासिक) भत्ता

1.	जिला परिषद् अध्यक्ष	₹ 12,000.00
2.	जिला परिषद् उपाध्यक्ष	₹ 10,000.00
3.	जिला परिषद् सदस्य	₹ 1000.00
4.	पंचायत समिति प्रमुख	₹ 10,000.00
5.	पंचायत समिति उप प्रमुख	₹ 5,000.00
6.	पंचायत समिति सदस्य	₹ 1000.00
7.	ग्राम पंचायत मुखिया	₹ 5,000.00
8.	ग्राम पंचायत उप–मुखिया	₹ 2,500.00
9.	ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य)	₹ 800.00
10.	ग्राम कचहरी सरपंच	₹ 5,000.00
11.	ग्राम कचहरी उप–सरपंच	₹ 2,500.00
12.	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	₹ 800.00

वर्तमान में मानदेय बढ़ाये जाने संबंधित कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि जो वर्तमान में बिहार राज्य के पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का मानदेय है वह काफी कम है । महंगाई को देखते हुए क्या सरकार जिला परिषद्, अध्यक्ष का मानदेय 25,000, जिला परिषद्, सदस्य का मानदेय 20,000, प्रमुख को 18,000, मुखिया को 15,000, पंचायत समिति के सदस्य को 12,000, सरपंच को 10,000 एवं पंच/वार्ड के सदस्य को 8,000 मानदेय का वृद्धि का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–3466, दिनांक–11.06.2013.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने जवाब तो दे ही दिया है इनको । माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है उसका जवाब दीजिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, यह राशि बहुत कम है, इस राशि को....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पूरक प्रश्न तो पूछ ही लिया है, अब माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए । आप पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं, उसका जवाब अब माननीय मंत्री जी को देने दीजिए । आप सुनते ही नहीं हैं बात को ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आप ही हमें उठा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गलतबयानी मत कीजिए, बात को सुना कीजिए । मैंने माननीय मंत्री जी को कहा ये उत्तर तो आप दिये हुए हैं, पूरक प्रश्न का जवाब दीजिए, इसमें क्या गलत है बताइये । माननीय सदस्य, अब आप बैठिए, ऐसा मत कीजिए। विधान सभा का स्तर बनाये रखिए, आप सब सम्मानित सदस्य है । माननीय मंत्री जी आप बताइये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जिला परिषद् अध्यक्ष–12,000, जिला परिषद् उपाध्यक्ष को 10,000, जिला परिषद् सदस्य को 1000, पंचायत समिति प्रमुख को 10,000, पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000, पंचायत समिति सदस्य को 1000, ग्राम पंचायत मुखिया को 5,000, ग्राम पंचायत उप–मुखिया को 2,500, ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) को 800, ग्राम कचहरी सरपंच को 5,000, ग्राम कचहरी उप–सरपंच को 2,500 और ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को 800 रुपया मिल रहा है । वर्तमान में नियत भत्ता बढ़ाये जाने संबंधित कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, आज जनप्रतिनिधियों की स्थिति....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न ही है । जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदत्तर है और यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी सैलरी की तरह, लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक राशि निश्चित रूप से उनको दी जानी चाहिए और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए । क्या इस पर सरकार पुनर्विचार करने के लिए तैयार है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष में हमलोगों ने बढ़ाने का काम किया था, आगे हमलोग इसपर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये, अब आप नहीं बोल सकते हैं, आपका हो गया, आपके माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछ लिया ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नियम के तहत अभी तक जब से 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूरक प्रश्न पूछना हो तो पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, पहली बार दिया गया, इसमें कभी बढ़ोतरी हुई ही नहीं है तो निश्चित तौर पर कब तक बढ़ोतरी करने का....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1431 (श्री सुर्यकान्त पासवान, बखरी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका सवाल ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर हो गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या–1432 (श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राघोपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल, जढुआ से बिदुपुर का पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–122बी0 (जढुआ–महनार–मोहिद्दीन–बछवाड़ा) पथ के अन्तर्गत पड़ता है, जिसमें Two lane with paved shoulder का उन्नयन कार्य दो भागों में यथा प्रथम भाग 0.00 कि0मी0 से 29.730 कि0मी0 (जढुआ–महनार) एवं द्वितीय भाग 29.730 कि0मी0 से 72.348 कि0मी0 (महनार–बछवाड़ा) में स्वीकृत है । जढुआ–बिदुपुर महनार पथ का एकरारनामा हो चुका है । कार्य समाप्ति की तिथि 28.02.2026 है । कार्य प्रगति पर है एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

उक्त पथांश को संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार पथ की मरम्मती कर यातायात योग्य बनाया जाता है ।

अध्यक्ष : आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने जवाब दिया है कि दो फेज में जो है सड़क का काम पूरा किया जायेगा, पहला जो फेज है वह जढुआ से लेकर के महनार तक और फिर उसके बाद महनार से लेकर बछवाड़ा तक और एक साल में बोला गया है कि इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा और हम अभी वस्तुस्थिति बताना चाहेंगे कि ये महागठबंधन की सरकार में जो द्वितीय चरण हमलोगों का था उसी समय उन्नयन का, इसकी स्वीकृति हमलोगों ने दिया था और इसका इकरारनामा जो है 14 मई, 2024 को हुआ और प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि जो है 27.02.2024 को हुई थी। अभी भी हम लगातार इस सड़क पर, क्योंकि यह मेरा क्षेत्र है तो हर दूसरा या तीसरा दिन इस सड़क पर हमको जाना होता है और हम जाते भी हैं लेकिन अभी तक यहां कोई काम जो है इसकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तक हम माननीय मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि यूटिलिटी जो सिफ्टिंग होता है, मैटेरियल का रखना साइट पर, उसकी भी शुरुआत नहीं हो पायी है तो हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो पहला फेज है उसका कार्य कब तक पूर्ण होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद विभाग के मंत्री रहे हैं, जब मॉनिटरिंग होती है तो निश्चित रूप से और स्पीड रहती है । जहां तक 14.05.2024 का इकरारनामा है और फिर बरसात का सीजन रहती है । हमलोगों ने इस काम की जो पूरी एग्रीमेंट की तिथि है वह 28.02.2026 है अभी करीब 10 परसेंट वर्क हुआ है जिसमें जी0एस0पी0 और डब्ल्यू0एम0एम0 का काम शुरू हो गया है जो यूटिलिटी सिफ्टिंग का काम है, यूटिलिटी सिफ्टिंग का काम ऑन प्रोसेस चलता रहता है, अध्यक्ष महोदय, आप भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं । निश्चित रूप से जो माननीय नेता प्रतिपक्ष की जो चिंता है उसको भी हमलोग देखेंगे और इस योजना को और गति प्रदान करने के लिए खुद मॉनिटरिंग करेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से हम चाहेंगे, मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि ज्यादा दूर भी नहीं है, हाजीपुर ज्यादा दूर नहीं है, एक बार ये खुद जाकर देख भी लेंगे 10 परसेंट, हमको पता नहीं है कि कितना हुआ नहीं हुआ, इनके जवाब में है कि 10 परसेंट वर्क हुआ है जो ये बता रहे है लेकिन अभी तक यूटिलिटी सिफ्टिंग जो शुरुआत जढुआ जो है वहीं से इसकी शुरुआती कुछ नहीं हुई है तो हम चाहेंगे कि इसको आप अपने स्तर पर इस काम को तेजी से दिखवाने का काम करें और कम से कम पहला चरण जो है उसको पहले करवा दिया जाय, यानी दो चरण में है तो 12 महीना लगेगा तो फर्स्ट फेज जो है वह कम से कम 6 महीना में हो जाना चाहिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सेकंड फेज जो है वह मई में आपका समाप्त हो जायेगा, इसी वित्तीय वर्ष में ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ध्यान देंगे तब यह होगा, नहीं तो नहीं होगा ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : हम ध्यान देंगे, आप भी एक बार क्षेत्र में चलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का केवल पटना में ही ध्यान रहता है ।

अध्यक्ष : अच्छी बात है इनका ध्यान पटना में ही रहता है । कहीं उधर चल जायेंगे तो उधर से ही जाकर लड़ने लगेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हाजीपुर जढुआ सड़क ठीक रहेगी तब न लोग पटना में घुस पायेंगे ।

अध्यक्ष : बिल्कुल, बिल्कुल ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1433 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, चिरैया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : (क) वस्तुस्थिति यह है कि चिरैया प्रखंड के परेवा फॉर्म हाउस से सगरदीना होते हुए नुरूल्लाहपुर तक पथ की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है ।

इस आरेखन में परेवा फॉर्म हाउस से सगरदीना तक पथ की लम्बाई 0.80 कि0मी0 है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एव प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पथ के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–RRSMP-06/2024-25 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि–26.03.2025 है।

नुरूल्लाहपुर को नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत निर्मित रसुलपुर से बेला पथ से सम्पर्कता प्राप्त है ।

सगरदीना से नुरूल्लाहपुर लम्बाई 1.20 कि0मी0 के आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं होने के कारण यह किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है ।

अतः उक्त पथांश के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि इस पथ से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, यह पथ सिकारगंज बाजार होते हुए पकड़ीदयाल अनुमंडल को जोड़ता है, इसके बन जाने से लाखों आबादी को इसका फायदा होगा । मंत्री जी कहते हैं कि यह रोड नेटवर्क में नहीं है तो मैं मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसी रोड में 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बन रहा है और 2 किलोमीटर छुट जा रहा है तो हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको नेटवर्क में जोड़वा करके और इस रोड को बनवाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

टर्न–5 / यानपति / 19.03.2025

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम इसको दिखवा लेते हैं लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रखंड के और जिस जिले के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, 2024–25 में पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 656.831 कि0मी0 कुल लागत 735 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रश्नागत प्रखंड चिरैया में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 39 पथ लंबाई 70.90 कि0मी0 कुल लागत 96.45 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : आपने जो कहा है, मंत्री जी ने कहा कि हम दिखवा लेंगे ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : एक मिनट सर, उसी रूट में डेढ़ कि0मी0 बन रहा है तो दो कि0मी0 जो बाकी रह जा रहा है वह माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि वह दो कि0मी0 को भी नेटवर्क में जुड़वाकर उसका काम पूरा कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा उसको हम दिखवा लेंगे । बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1434 (श्री राम सिंह, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत कालीघाट, गोरियापट्टी, दीनदयाल नगर, पारस नगर, रतनमाला, कैलाशनगर, पुअर हाउस वाल्मीकिनगर बराज के निम्न प्रवाह में गंडक नदी के बायें तट पर अवस्थित है, जहां कोई बांध निर्मित नहीं है, अपितु बगहा शहर के अंतर्गत कालीघाट से पुअर हाउस तक लगभग 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में बगहा शहर के सुरक्षार्थ विभिन्न चरणों में कटाव निरोधक कार्य कराया गया है, जो काफी प्रभावी रहा है ।

पूर्व में शास्त्रीनगर स्थल के समीप कराया गया कार्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ । बाढ़ 2024 पूर्व 30 अदद बोल्डर बेडवार का निर्माण कराकर उक्त स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है, जो अभी प्रभावी है ।

वर्तमान में प्रश्नगत स्थल सुरक्षित है ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बगहा नगर परिषद क्षेत्र गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है और आज उसकी लंबाई माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, मैं यह जानना चाहता हूं 2007 से उस शहर की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह थी इसमें एन0एच0 रोड भी कट रहा था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वह बचा, आंशिक जो बांध बनाया गया है, मैं चाहता हूं कालीघाट से लेकर पुअर हाउस तक पक्का बांध निर्माण करके और बायपास, उसमें रोड भी निकल जाय जिससे आवागमन में सुविधा होगी और शहर का बचाव, नगर परिषद क्षेत्र का बचाव भी होगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य तो सही कह रहे हैं कि यह बगहा शहर का सुरक्षा तटबंध है और प्रश्न इन्होंने किया है कि इस तटबंध को गोल्डन पिचिंग से सुरक्षित कर लिया जाय और जवाब माननीय सदस्य ने देखा है कि हमने यही मानकर, यह तो तटबंध के बोल्डर पिचिंग की बात कर रहे थे हमने उसमें पूरे लंबाई में 30 जो बोल्डर का है बेडवार बना दिया है, मतलब हम पानी की धारा को उस बांध तक भी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं क्योंकि पहुंचता है तब कटाव या जो भी बचाव का काम किया रहता है उसमें इरोजन की संभावना रहती है और जब बेडवार

बनाया जाता है और बेडवार भी हमने बोल्डर का बनाया है इसलिए कि नदी की धारा जो बगहा शहर का सुरक्षा तटबंध है उससे थोड़ी दूरी पर ही बहे जिससे कि इस तटबंध सहित बगहा शहर सुरक्षित रहे । इसलिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और जो हमने किया है असर दोनों का बराबर है ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वीकार किए हैं, शास्त्रीनगर जो बांध बना है वह आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ है, अभी इन्होंने उत्तर दिया है कि अभी सुरक्षित है, अभी पानी का कोई मौसम ही नहीं है कि सुरक्षित नहीं होगा । जब ये वाल्मीकिनगर बराज से 5 लाख 6 लाख...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राम सिंह : तो वह पानी शहर में प्रवेश कर जाता है इसलिए मैं चाहता हूं कि बांध का निर्माण हो और उच्चीकरण हो ताकि पानी की थोड़ी भी धार आए...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो विस्तार से बताया ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमने तो कहा ही है कि पिछले बाढ़ से पूर्व यानी 2024 में जून से पूर्व बेडवार बनाया गया था । 2024 के बाढ़ में पूरा सदन अवगत है कि वह ऐतिहासिक रूप से अप्रत्याशित बाढ़ था उसमें थोड़ी–बहुत दिक्कत आई है उसको हमलोग अगले बाढ़ से पहले दुरुस्त करा देंगे ।

श्री राम सिंह : धन्यवाद है मंत्री जी को ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1435 (श्री रामवृक्ष सदा, अलौली)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत माननीय प्रभारी मंत्री, खगड़िया जिले की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति, खगड़िया द्वारा अनुशंसा के आलोक में निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक–07 पर अंकित है ।

प्राथमिकतानुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति के उपरांत निविदा के माध्यम से प्रश्नाधीन पुल निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : रामवृक्ष जी, पूरक पूछिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है उसमें माननीय मंत्री जी जवाब में दिए हैं कि जिला संचालन समिति प्राथमिकता सूची सातवें नंबर पर पुल है और वहां के हजारों–हजार जनता, लोहा का क्षतिग्रस्त पुल है, कभी–भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : पूरक यही है महोदय कि माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि मंत्री जी उस पुल को आर0सी0सी0 पुल बनवाने का विचार रखते हैं प्राथमिकता के आधार पर या नहीं और कब तक ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था पहले भी कि 9 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत इस वित्तीय वर्ष में शुरुआत माननीय नेता ने की है और इस वित्तीय वर्ष में 600 पुल को और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल को लेने का सरकार ने निर्णय किया है और पूरे राज्य से जो जिला संचालन समिति से पुलों की संख्या आई है वह 5495 आई है और मात्र खगड़िया से 49 पुलों की संचालन समिति से आई और संचालन समिति में यह सातवें नंबर पर है और हमने कहा है कि प्राथमिकता निधि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति के उपरांत निविदा करके इस पुल का निर्माण कराया जायेगा । तो अभी हमलोग इसको देख रहे हैं कि कौन–कौन से पुल हैं क्योंकि इन्हीं के खगड़िया से 49 पुल आया है इसमें यह लोग खुद मेंबर हैं, अगर कम पुल वहां से भेजते तो हमलोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती लेकिन पुल आया हुआ है अभी 600 लेना है, प्राथमिकता के आधार पर 600 पुल लेंगे तो उसमें प्रयास करेंगे कि इसको लिया जाय ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, एक पूरक और है, माननीय मंत्री जी पूरे बिहार का गिना दिए, हमको सिर्फ अलौली विधान सभा के हथपर पंचायत गड़बनी पुल से मतलब है जो जनता के हित में बहुत जरूरी है और प्राथमिकता सूची के आधार पर उनको एक नंबर में लाकर क्या विचार रखते हैं बनाने का और नहीं रखते हैं तो क्यों ? यह जनता की मांग है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो स्पष्ट दे दिए हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, हम तो कह ही चुके हैं ।

अध्यक्ष : जब बता दिए कि करेंगे उसको ।

(व्यवधान)

आप कहां से आ गए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, सवाल यह है कि वह पुल जर्जर है, प्राथमिकता की सूची का इंतजार वह जर्जर पुल करेगा, अगर वह जर्जर है, एक्सीडेंट होने का खतरा है तो यही है कि प्राथमिकता की सूची में उसको ऊपर लाया जा सकता है कि नहीं?

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, प्राथमिकता सूची में परिवर्तन कैसे हो सकता है, बताइये । रामवृक्ष जी, बैठ जाइये ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी प्रखंड में पुल जर्जर है । 9 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से हर जगह समस्याएं हैं, पुल के लिए बहुत डिमांड है तभी तो, हमें 1

हजार पुल 2 वित्तीय वर्ष में लेना है और टोटल जिला संचालन समिति से 5495 पुल आया है तो सभी पुल प्राथमिकता में है । सभी पुल माननीय विधायकों के द्वारा ही लाया गया है तो सरकार की जो निधि की उपलब्धता है उसके द्वारा प्रायोरिटी देकर पुल का निर्माण करेगी । हम तो कह ही रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लाया गया है एसेंबली में, प्रयास करेंगे कि इनका पुल हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन जी ।

(व्यवधान)

अब क्या है, नहीं बैठिए । अब बैठिए ।

(व्यवधान)

मंत्री जी ने तो बताया कि ध्यान रखेंगे । अपने प्रश्न की खीज यहां मत उतारिए । आप बताइये क्या करना चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता सूची नहीं लिया जा रहा है । मंत्री, प्रभारी मंत्री...

अध्यक्ष : जनरल करना है तो अलग से प्रश्न करिए ।

श्री ललित कुमार यादव : केवल भाजपा, जदयू का लेते हैं ।

अध्यक्ष : गलत बात, जनरल के लिए अलग से प्रश्न करिए । श्री आलोक रंजन जी, बोलिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1436 (श्री आलोक रंजन, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1, स्वीकारात्मक है । वस्तुतः इसमें दो पथ है (1) एन0एच0107 से जवाहर नवोदय विद्यालय बरियाही जिसकी लंबाई 0.900 कि0मी0 तथा (2) नवोदय विद्यालय से बनगांव कलावती फिल्ड जिसकी लंबाई 1.220 कि0मी0 है ।

खंड–2, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा अभियंता प्रमुख को पथ हस्तांतरण के लिए प्रपत्र में भरकर समर्पित किया गया था ।

खंड–3, अस्वीकारात्मक है । ग्रामीण कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या–11/अ0प्र0–13–14/2022 2613, दिनांक–06.03.2025 से इस पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है ।

खंड–4, स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन पथ, पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

वस्तुस्थिति उपरोक्त खंड '3' में स्पष्ट कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : आलोक जी, आप पूरक पूछिए ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि प्रश्न पूछने के बाद इसको हस्तांतरित कर दिए हैं । 20 में तय हुआ था और 22 में प्रशासनिक स्वीकृति हो गई ।

अध्यक्ष : पूरक पूछना है या नहीं ।

श्री आलोक रंजन : इसके लिए धन्यवाद देते हैं, चूंकि जवाब में दे दिए हैं कि हम कर दिए हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये । श्री आफाक आलम ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1437 (श्री आफाक आलम, कसबा)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि श्रीनगर प्रखंड के बलुआ गांव के बलुआ धार (परमाना घाट) पर पुल का निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला संचालन समिति के द्वारा निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक–104 पर अंकित है । स्वीकृति के उपरांत इसका निर्माण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : आफाक जी, पूरक पूछिए ।

श्री आफाक आलम : महोदय, श्री नगर प्रखंड में बलवा गांव से सवज्जा जाने वाला दो प्रखंड को जोड़ता है और वहां दोनों तरफ पक्की सड़क बन गया है और उस पुल का बनना बहुत ही जरूरी है तो माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उसको जितना जल्द हो उस पुल को बनवा दें, कब तक बनवा देंगे ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अगले वित्तीय वर्ष में बना दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में ।

श्री आफाक आलम : महोदय, वित्तीय वर्ष की समय–सीमा क्या है ?

अध्यक्ष : एक अप्रील से शुरू होता है वित्तीय वर्ष ।

श्री आफाक आलम : अगर अप्रील में बन जाता है तो माननीय मंत्री जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद ।

टर्न–6 / अंजली / 19.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–1438 (श्री अजीत कुमार सिंह, डुमरांव)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित पथांश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है । कृष्णाब्रह्म एवं नया भोजपुर में रोड क्रॉसिंग पर सुरक्षित आवागमन हेतु सर्विस रोड सहित अंडरपास निर्मित है । प्रताप सागर में IRC Guideline के अनुसार median cut दिया गया है ।

वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग–922 पर–

(i) बिहियॉ, शाहपुर, नुऑव, दलसागर, परेव एवं गजराजगंज में सर्विस रोड।

(ii) कायमनगर में फुट ओवर ब्रिज एवं

(iii) बक्सर ब्रिज और सोन ब्रिज (कोईलवर ब्रिज) पर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान – हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । आवश्यकतानुसार सर्विस रोड हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसे पूर्ण होने के पश्चात कार्य चालू करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, अजीत जी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन0एच0 पटना टू बक्सर 922 जो बना है उसमें लगातार कई सारे गांव में जिसका मैंने सवाल किया है, कृष्णाब्रह्म एवं नया भोजपुर, प्रताप सागर, नुऑव और कई सारे आबादी वाले ऐसे गांव है जो सड़क पर हैं और वहां सर्विस लेन नहीं होने की वजह से लोग डायरेक्ट सड़क पर उतर जाते हैं जिससे उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है । कुछ दिन पहले एक बहुत मासूम बच्ची की मौत प्रताप सागर में हो गई ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, पूरक पूछ रहा हूं । बहुत बड़ी घटना है । प्रताप सागर दुर्घटनाओं का जोन बना हुआ है, पूरे बक्सर में सभी लोग जानते हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, जो जवाब हमको दिया गया है, जवाब में लिखा गया है कि सुरक्षित आवागमन के लिए प्रताप सागर में गाइडलाइन के अनुसार median cut दिया गया है । महोदय, median cut का सवाल मैंने नहीं किया, मैंने किया है प्रताप सागर में सर्विस लेन है कि नहीं है ? सवाल मैंने सर्विस लेन का किया है और जवाब median cut का दिया जा रहा है, यह तो जवाब उल्टा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, पूरक यही है कि प्रताप सागर में जहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं वहां सर्विस लेन सरकार बनाने का विचार रखती है अथवा नहीं ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कृष्णाब्रह्म, नया भोजपुर और प्रताप सागर, मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कृष्णाब्रह्म, नया भोजपुर में रोड क्रॉसिंग सहित सुरक्षित आवागमन हेतु सर्विस रोड सहित अंडरपास निर्मित है । दूसरा, प्रताप सागर में मैंने कहा है कि आई0आर0सी0 गाइडलाइन के अनुसार median cut दिया गया है, तो जो दोनों पहले सवाल था उसका जवाब है । साथ ही साथ, मैंने यह भी उनको कहा है कि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग 922 में बिहियां, शाहपुर, नुऑव, दलसागर, परेव एवं गजराजगंज में सर्विस रोड के निर्माण के लिए लैंड एक्यूजीशन का काम शुरू हो गया है । कायमनगर में फुट ओवर ब्रिज का

निर्माण भी निविदा की प्रक्रिया में है और बक्सर ब्रिज और सोन ब्रिज (कोईवलर ब्रिज) पर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान भी इसी योजना के प्राक्कलन में है और इसके हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिया जा चुका है और सर्विस रोड हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है । पूरा स्पष्ट जवाब तों इसमें दिया गया है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैंने median cut पूछा ही नहीं सवाल में । आप सवाल पढ़ सकते हैं, मिडियन कट लिखा ही नहीं है कहीं । मैंने पूछा सर्विस लेन मुझे चाहिए और जमीन की कोई दिक्कत नहीं है । महोदय, पूरे एन0एच0 के किनारे पर्याप्त जमीन है, कोई जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है, ये अधिकारियों ने गलतबयानी की है । पूरा है महोदय । प्रताप सागर में बहुत जरूरी है, जिनका जवाब दिया गया है पांच–छह गांवों का नाम जहां काम करना है उसमें इन्होंने नहीं लिखा है कि प्रताप सागर में भी बनाया जाएगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहला सवाल तो यह है कि जब एन0एच0 बना, मैं यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि उस एन0एच0 में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और जितना सर्विस लेन बना, कई सारे गांव में जैसे नुऑव में, दलसागर में सर्विस लेन बना लेकिन सर्विस लेन अधूरा है, उसको पूरा नहीं किया गया है, इस पर एजेंसी पर एक्शन होना चाहिए था जो नहीं हुआ । महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से कि जब कोई एन0एच0 का प्रोजेक्ट बनता है तो सर्विस लेन फुट ओवर ब्रिज तो उसी प्रोजेक्ट के साथ एस्टीमेट बनता है, तो यह एस्टीमेट उस समय इन तमाम जगहों पर सर्विस लेन का था कि नहीं था, यदि था तो क्यों नहीं बनाया गया और नहीं बनाने वाले पर कोई कार्रवाई सरकार करना चाहती है कि नहीं ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरे योजना के पार्ट में पूरी निविदा का जो डिटेल है, हमने यह कहा कि इसका प्रावधान अभी है और इसके जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जमीन उपलब्ध है तो ठीक ही है, तब तो उसमें काम ऐसे भी हो सकता है और तीनों पार्ट की योजना का, प्रताप सागर की बात कर रहे हैं वहां पर अभी अंडरपास का प्रोविजन नहीं है । उसमें आई0आर0सी0 के माध्यम से गाइडलाइन के आधार पर मिडियन कट किया गया है फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि...

अध्यक्ष : उनका कहना है प्रताप सागर में सर्विस लेन बन सकता है जगह उपलब्ध है एक बार दिखवा लीजिए उसको ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : हम दिखवा लेते हैं । विकल्प होगा तो किया जाएगा ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एक पूरक मेरा है । महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : हो गया । आपके समर्थन में ही तो बोल रहे हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, जरूर, आपके बिना समर्थन के हम खड़ा भी नहीं हो सकते हैं ।

अध्यक्ष : अंतिम प्रश्न पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एक अंतिम प्रश्न है । इन्होंने लिखा है, जो जवाब इन्होंने दिया है बहुत लंबा–चौड़ा व्यापक जवाब है लेकिन इस जवाब में सच्चाई नहीं है । मैं यह मांग करता हूं, अब मांग ही कर रहा हूं सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि प्रताप सागर में सर्विस लेन की आवश्यकता है वहां सर्विस लेन बना दिया जाय, जहां अधूरा सर्विस लेन है, नुऑव में, दलसागर में, उसको पूरा कराया जाय और तीसरा जो आपने फुट ओवर ब्रिज कायमनगर में दिया है, एक ओवर ब्रिज नया भोजपुर में भी देने का कष्ट करें, यह हमारी मांग है, इससे वहां यातायात में सुविधा होगी और दुर्घटनाओं पर रोक लग सकती है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1439 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनिहारी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड में लखनपुर पंचायत अंतर्गत हटकोला स्कूल से बड़ा लखनपुर मध्य टोला तक 400 मीटर की लंबाई में बाढ़ 2023 पूर्व कटाव निरोधक कार्य कराया स्थल को सुरक्षित किया गया है ।

प्रश्नगत स्थल रूस्तम हाजी के घर एवं नूर इस्लाम चाय दुकान महानंदा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जिसकी वर्तमान में नदी तट से न्यूनतम दूरी लगभग 200 मीटर है । इन स्थलों के पास एन०एस०एल० नीचा होने के कारण महानंदा नदी में अत्यधिक जलश्राव प्रवाहित होने की स्थिति में नदी के पानी का फैलाव एन०एस०एल० पर होता है । नदी के जलश्राव में कमी होने पर पानी स्वतः नदी में वापस हो जाता है । इन स्थलों के पास वर्तमान में कोई कटाव नहीं है ।

प्रश्नगत अन्य स्थल झुमरा टोला में अबीदुर का घर एवं फैजुल मास्टर का घर महानंदा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है । इन स्थलों के समीप वर्तमान में कटाव नहीं है । नदी तट से बसावटों की न्यूनतम दूरी लगभग 200 मीटर है एवं स्थल पूर्णतः सुरक्षित है ।

बाढ़ अवधि 2025 के दौरान कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, मनोहर बाबू जी का प्रश्न है । उत्तर नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है । उत्तर नहीं मिला है ?

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : नहीं महोदय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें इन्होंने कटाव निरोधी कार्य कराने की बात कही है और कुछ दूर छोड़ने की, तो जहां कटाव निरोधी कार्य की आवश्यकता है...

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वहां करा दिया गया है और जो छोड़ा गया है वहां कटाव निरोधक कार्य की आवश्यकता नहीं है, वहां पर नदी का लेवल और एन0एस0एल0 जो कहते हैं, नेचुरल स्वाईल लेवल जो सामान्य सतह होती है जमीन की वह लगभग बराबर है, पानी बढ़ता है तो उसके ऊपर से पानी जाता है, वहां कटाव नहीं होता है, इसलिए उसको छोड़ा गया है और जहां पर आपने कहा है कि वहां कार्य हुआ है कुछ दूर छोड़ा गया है, इसलिए छोड़ा गया है कि वहां कटाव नहीं होता है, वहां एन0एस0एल0 के ऊपर पानी चढ़ता है और जब नदी का पानी घटता है तो वह पानी वापस चला जाता है, कटाव जहां होता है वहीं कटाव निरोधक कार्य कराया जाता है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, उस प्रश्न में ही लिखा हुआ है झुमरा टोला अबीदुर के घर से फैजुल मास्टर के घर तक कटाव है और मैं कह रहा हूं कि वहां कटाव है और अगर वहां कटाव नहीं रोका गया तो जो काम पहले कराया गया है वह काम भी व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि कटकर सीधे गांव में पानी घुस जाएगा, क्या सरकार उसमें उस कटाव को रोकना चाहती है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा कि जहां कटाव संभावित है या कटाव के लक्षण दिखते हैं वहां कटाव निरोधी कार्य कराया जाता है और माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं कि कहीं कटाव हो रहा है और काम नहीं हुआ है वह आज ही लिखकर दे दें हम अभियंताओं को भेज देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1440 (श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, रक्सौल)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 0.600 किलोमीटर है, जो कच्ची है । इस पथ पर कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । प्रश्न में वर्णित बसावट सिवानटोला को MMGSY (NDB) अन्तर्गत ICP बाउण्ड्री से सिवान टोला पथ से सम्पर्कता प्राप्त है ।

सम्प्रति दोहरी सम्पर्कता का मामला होने के कारण प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, प्रमोद जी । माईक पर बोलिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, मेरा पूरक यह है वर्णित सड़क आई0सी0पी0 एन0एच0 नया भवन हरैया थाना के बगल से सिवान टोला तक सटे भारत–नेपाल सीमा का इंटीग्रेटेड जो पोस्ट है और पार्किंग है, इस सड़क से जुड़े कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी हैं, गाड़ियों के आवागमन के लिए और एस0एस0बी0 कैंप के लिए कोई प्रॉपर सड़क नहीं है । महोदय, हमलोग तीन किलोमीटर रोड़ मनरेगा से बनाये हैं मिट्टी से, 40 फीट चौड़ा है, उस रोड से इस रोड से जवाब आया है कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग कर रहा हूं यह बहुत इंपोर्टेंट रोड है, इस रोड को जितनी जल्दी हो सके बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह दोहरी संपर्कता का मामला है और जहां पर माननीय सदस्य रोड मांग रहे हैं वहां पर पहले से ऑलरेडी संपर्कता प्राप्त है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम इसको दिखवा लेते हैं और अगर इसमें संपर्कता, जिसकी चर्चा ये कह रहे हैं हम दिखवा लेते हैं अगले वित्तीय वर्ष में इसको कराने का काम करेंगे लेकिन हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि सरकार सड़क बनाने के लिए माननीय नेता के नेतृत्व में जो नई योजना का निर्माण किया है उसमें इनके जिले में 656 पथ जिसकी लंबाई 956.831 किलोमीटर है और 780.35 करोड़ रुपए से सरकार ने इसको स्वीकृति प्रदान की है और जिस प्रखंड रक्सौल की चर्चा कर रहे हैं वहां 22 पथ हैं जिसको 27.666 किलोमीटर, कुल लागत 22.55 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है । हमलोग संवेदनशील हैं, आने वाला वर्ष चुनाव का है और उसके पहले सभी सड़कों को हम ठीक कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय...

अध्यक्ष : हो गया । माननीय मंत्री जी ने इतना बढ़िया जवाब दे दिया है, अब क्या दिक्कत है ? श्री शिव प्रकाश रंजन ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1441 (श्री शिव प्रकाश रंजन, अगिआंव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित हैः–

(क) सेमरांव गाँव से इंग्लिशपुर तकः– उक्त पथ टी01 से इंग्लिशपुर तक पथ के नाम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत स्वीकृत एवं निविदा की प्रक्रिया में है ।

(ख) इंग्लिशपुर से इंग्लिशपुर अहीर पट्टी तक पथः–उक्त पथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत स्वीकृत एवं निविदा की प्रक्रिया में है।

(ग) इंग्लिशपुर अहीर पट्टी से बहरी गाँवः–उक्त पथ आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । सम्प्रति इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बहरी गाँव को शीर्ष एम0आर0 3054 अन्तर्गत मरम्मत किये गये एल088 गड़हनी बागर पथ से बहरी पथ से सम्पर्कता प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । पूरक है कोई ?

श्री शिव प्रकाश रंजन : महोदय, उत्तर प्राप्त है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इंग्लिशपुर अहीर पट्टी से बहरी गांव तक अगर यह रास्ता बन जाता है तो कई गांव का मुख्य पथ पर दूरी घट जाएगी और कई टोले–मोहल्ले हैं जिनको सहूलियत हो जाएगी, तो मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इंग्लिशपुर पट्टी से अहीर टोली होते हुए बहरी तक जो रास्ता है उसको बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका आग्रह माननीय मंत्री जी ने सुन लिया । श्री विनय बिहारी।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1442 (श्री विनय बिहारी, लौरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नेपाल से आने वाली नदियों के बहाव के साथ अत्यधिक गाद का निक्षेपण होता है ।

गंगा नदी एवं इसके सहायक नदियों से गाद हटाने के लिए राष्ट्रीय गाद नीति बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है ।

पश्चिम चम्पारण जिला के विभिन्न नदियों में कतिपय चयनित गाद स्थलों से गाद निकासी हेतु खान एवं भूतत्व विभाग एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण से जिलान्तर्गत विभिन्न नदियों में कतिपय चयनित गाद निक्षेप वाले स्थलों के नियमानुसार निलामी हेतु अनुरोध किया गया है ।

साथ ही, अन्य विभाग के कार्यों यथा सड़क निर्माण आदि में गादों के उपयोग करने निमित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आती है बाढ़, विस्थापित होते हैं परिवार...

श्री सत्यदेव राम : महादेय, माननीय सदस्य ने आग्रह किया तो माननीय मंत्री जी को बोलकर आश्वासन देना चाहिए न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सुना । आग्रह पर जवाब होता है क्या ? आप तो पुराने सदस्य हैं आग्रह पर जवाब होता है ? प्रश्न पूछना चाहिए ।

(व्यवधान)

विनय जी बोलिए । पूरक पूछिये विनय जी, समय नहीं है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, आती है बाढ़, विस्थापित होते हैं परिवार, माहौल गंगीन हो जाता है, हमारी नदियों का मीठा पानी समुद्र में जाकर नमकीन हो जाता है । इसलिए मैं कहता हूं सरकार से, सरकार से जानना चाहता हूं...

अध्यक्ष : समय हो गया है ।

श्री विनय बिहारी : कि आगे के लिए वायदा क्या है और बाढ़ का पानी बर्बाद हो रहा है इससे फायदा क्या है ?

अध्यक्ष : पूरक पूछना है कि नहीं ? समय समाप्त हो गया ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, मैं पूरक बोल रहा हूं कि नदियों का गाद कैसे साफ होगा ताकि नदियों का पानी नदियों में रहेगा, जल संचय होगा, सेव वाटर होगा, सरकार से यही जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–19 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं–

1. श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0, श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0, श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0, श्री विजय कुमार, स0वि0स0 एवं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0 ।

(क्रमश :)

टर्न–7 / आजाद / 19.03.2025

.... क्रमशः ....

अध्यक्ष : 2. श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0 एवं डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0 ।

3. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 19 मार्च, 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–172(3) एवं नियम–47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, महोदय, इसको पढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष : श्री अमरजीत कुशवाहा । छोटा–छोटा दिया कीजिए, बहुत लम्बा हो जाता है । बोलिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, बहुप्रचारित राम जनकी पथ के तहत सिवान जिले के मेहरोना से मलमलिया तक के क्षेत्र में घनी बसी आबादी को कृषि भूमि के रूप में दिखाकर अधिग्रहण किया जाना है । भारत माला परियोजना के तहत फतुआ के भेड़गांवां, वाजितपुर, सैदनपुर, रबियाचक एवं अन्य इलाकों तथा पश्चिम चम्पारण के सिकटा में इन्डो–नेपाल सड़क निर्माण में व्यवसायी और आवासीय भूमि का कृषि भूमि के रूप में मूल्यांकन कर आधा–अधूरा मुआवजा दिया जा रहा है । नवादा के नादरीगंज में दो गांवों में किसानों की जमीन बिना मुआवजा के अधिग्रहित कर ली गई है, बक्सर के चौसा में किसानों को मुआवजा के बजाय पुलिस की लाठियां मिली, रोहतास में ग्रीड फील्ड परियोजना सहित पूरे राज्य में या तो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है या कम दाम पर भूमि अधिग्रहित हो रही है अथवा व्यवसायिक भूमि का कृषि भूमि के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है ।

बिहार में भूमि अधिग्रहण के दौरान 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का घोर उल्लंघन है, जिसमें कृषि योग्य भूमि के लिए मुआवजा चार गुना निर्धारित किया गया है ।

भूमि अधिग्रहण में 2013 के कानून का सही ढंग से पालन कराने के अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर बहस की मांग करता हूँ ।

महोदय, ...

अध्यक्ष : हो गया । श्रीमती प्रतिमा कुमारी । तय यही हुआ है कि पढ़ कर बैठ जाना है । तय यही है, फिर शुरू कीजियेगा तो पढ़ाना कठिन होगा । प्रतिमा जी, बोलिए । प्रतिमा जी का बोलना बंद किया जाय ? बैठ जाईए ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माानीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के सबसे बड़ा सर्राफा बाजार, बाकरगंज, पटना में जहां सोने–चॉदी समेत अन्य कीमती धातुओं के आभूषण की खरीद–बिक्री

की जाती है । कारोबार के लिहाज से बाकरगंज बिहार की सबसे बड़ी मंडी है । यहां पर लगभग 450 दुकानें हैं ।

देश के 10 बड़े सर्राफा बाजारों में इसका स्थान है । ट्राफिक जाम एवं अतिक्रमण के कारण सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल है । सी0सी0टी0वी0 नहीं होने के कारण आभूषण कारोबारी स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं ।

अतः आज दिनांक 19 मार्च को विधान सभा के चलते सत्र में कार्य को स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ''आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य सरकार से रोजगार एवं शिक्षा के लिए हो रहे युवाओं के पलायन पर रोक लगाये जाने के उपायों पर चर्चा हो ।''

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार राज्य में रोजगार के अवसरों की भारी कमी एवं शैक्षणिक वातावरण ध्वस्त रहने के कारण राज्य के निवासी चाहे वह मजदूर हों, पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, कोई अन्य प्रोफेशनल हो या दसवीं कक्षा पास विद्यार्थी हो, सभी लोग राज्य से बाहर जा रहे हैं । राज्य में निवेश के लिए बार–बार सरकार बिजनेस मीट करती है परंतु उसका भी बहुत कारगर फल सामने नहीं आ रहा है और रोजगार के लिए पलायन बदस्तूर जारी है । शिक्षा के लिए बच्चे दसवीं कक्षा पास करते ही कोटा, पूणे, विशाखापट्टनम सहित देश के अन्य स्थानों में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं । एक–एक विद्यार्थी पर प्रति वर्ष लाखों रूपये फीस एवं रहने खाने पर खर्च होता है । राज्य के युवा रोजगार एवं शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं जिसके कारण वे उन राज्यों में हजारों करोड़ रूपये प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं । इससे उस राज्य की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हो रही है परंतु बिहार की इकोनॉमी चरमरा रही है । राज्य से पलायन के ही कारण राज्य के सभी स्टेशनों से चलने वाली गाड़ियों में सालो भर वेटिंग रहता है और पटना–दरभंगा से हवाई सेवा देश में सबसे महंगी है ।

अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य से रोजगार एवं शिक्षा के लिए हो रहे युवाओं के पलायन पर रोक लगाये जाने के उपायों पर चर्चा हो ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री राणा रणधीर ।

शून्य–काल

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्राी आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए जॉब कार्ड की अनिवार्यता से प्रक्रिया धीमी हो रही है, जिससे पात्र लाभार्थी वंचित हो रहे हैं ।

अतः सरकार से मांग करता हूॅ कि जॉब कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाय तथा नाम जोड़ने की समय सीमा बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करें।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, सत्याग्रह के चम्पारण के पुराना मुख्यालय मोतिहारी के एकमात्र श्री कृष्ण सिंह महिला महाविद्यालय 9 एकड़ भूमि में 1959 ई0 में स्थापित हुआ, जो जीर्ण–शीर्ण है ।

अतः सरकार से मांग करता हूॅ कि एकमात्र महिला महाविद्यालय के हॉस्टल एवं सभी विभागों के साथ आधुनिक तकनीक से विकसित करावें ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत रजवाड़ा से दलकावा सड़क के बीच पिछले बाढ़ में पुल ध्वस्त हो गया था, आवागमन में कठिनाई होती है ।

अतः सोनबरसा प्रखंड के रजवाड़ा से दलकावा के बीच बाढ़ से ध्वस्त पुल के निर्माण की मांग सरकार से करती हूॅ ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन ग्राम पंचायत महेश बथना मात्र 20 मीटर दूर है । ग्राम सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया गया तो पूरा गांव ही नदी में विलीन हो जायेगा ।

अतः समय पूर्व काम करवाकर गांव को नदी में विलीन होने से बचाने की मांग करता हूॅ ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखंड–डोभी के ग्राम पंचायत–घोड़ाघाट के ग्राम–गोसाईडीह नेशनल हाईवे से ग्राम–रानीचक होते हुए बेसिक स्कूल तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूॅ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के महादलितों के उत्थान तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में लगे विकास मित्रों तथा कमजोर वर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने के अभियान में शामिल टोला सेवक/तालीमी मरकज के मानदेय में वृद्धि करने एवं बकाया का भुगतान राज्य सरकार करे ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अन्तर्गत प्रखंड–बाराचट्टी में पुराना जी0टी0 रोड–02 गजरागढ़ में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा है । बड़ा बाजार भी है । एक कि0मी0 सड़क बिल्कुल जर्जर है । यात्रियों के लिए कोई सुविधा भी नहीं है । सड़क निर्माण सहित यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सदन से मांग करती हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के रामनगर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड रामनगर के 18 पंचायत एवं प्रखंड गौनाहा के 18 पंचायतों में जॉचोपरान्त बंद पड़े नल–जल योजना के हजगह पर पुनः चापाकल बहाल करने को सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड में निर्माणाधीन तीन ए0पी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 के कार्य को अधूरा छोड़ने वाली एजेंसी बी0एम0एस0सी0आई0एल0 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्य पूर्ण करवाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री सुनील मणि तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहां के छात्र/छात्राओं को ग्रेजुएट की पढ़ाई करने हेतु अन्यत्र दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाईयॉ होती है।

अतः सरकार से शीघ्र ही पहाड़पुर में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ ।

टर्न–8/पुलकित/19.03.2025

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत नगर थाना, मधुबनी के अंतर्गत रॉड से हमला एवं गोली चलाकर घायल करने से संबंधित कांड सं0–5129028250091, दिनांक–06.03.2025 दर्ज है । परंतु अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार भयभीत है ।

अतः अविलम्ब नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा प्रखण्ड के लखनदेई मृतप्राय नदी धुम्हा जीरो प्वाइंट से लेकर बाजपट्टी तक जाती है, पूर्णतः बंद है । उक्त नहर के उड़ाही होने से किसान के हित में सैकड़ों ग्राम के हजारों एकड़ खेत सिंचित होगा ।

सरकार से उक्त नहर के अविलम्ब उड़ाही की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के पुरैना पंचायत के अवगिल ग्राम में टाटी नदी पर पुल एवं चेकडैम निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन के अलावे हजारों एकड़ में लगी फसल पटवन के अभाव में बर्बाद हो रही है ।

अतः उक्त स्थान पर पुल एवं चेकडैम निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड में फलका बाजार में एस0एच0–77 एवं भंगहा नालों की स्थिति जर्जर है । जो वर्षों के समय जलमग्न हो जाता है ।

अतएव मैं उक्त जर्जर नालों का जीर्णोद्धार कराने हेतु सरकार से मांग करती हूँ ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत रोहिया से आजमनगर प्रखण्ड के बीच लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए आजमनगर प्रखण्ड को जोड़ने वाली, महानंदा नदी पर रोहिया पुल निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का 80 प्रतिशत मखाना बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में उत्पादन होता है, लेकिन मखाना किसानों को बाजार में उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है ।

मखाने की खेती करने वाले छोटे–छोटे किसानों को भी अन्य फसलों की तरह बाजारों में उचित मूल्य प्राप्त हो, सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज चौक, हॉस्पिटल चौक एवं नीम चौक पर निरंतर जाम की समस्या से आमजन, दुकानदारों को काफी समस्या होती है ।

अतः जनहित में ताजपुर बाजार में दिन में भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बिहार के सरकारी विद्यालयों में बिना किसी अवकाश के नियमित रूप से कार्य कर रहे रात्रि प्रहरी को मात्र 5000/– रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, जो सरकार के न्यूनतम मजदूरी से कम है ।

अतः मैं सरकार से रात्रि प्रहरी को 15,000/– रुपये मासिक मानदेय देने एवं सेवा नियमित करने की मांग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, सभी जॉबकार्ड धारी श्रमिकों की 200 यूनिट बिजली फ्री तथा बकाया बिजली माफ करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा नगर परिषद् के कालीघाट से पुअर हाउस तक वर्ष–2015 में गंडक नदी के किनारे बांध निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कुछ ही जमीन मालिकों को मुआवजा मिला था ।

अतः बाकी लोगों को मुआवजा दिलाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े चौरानवे लाख महागरीबों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित दो लाख रूपया देने के लिए कोई योजना या शर्त की बात नहीं की गयी थी ।

अतः आर्थिक सर्वे की सूची में नामित गरीबों को उनके खाता में एक मुश्त राशि भेजने की मांग करता हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के वित्त विभाग के संकल्प संख्या–310, दिनांक–21.05.1987 द्वारा फिटमेंट सह रिप्लेसमेंट स्केल कमिटी (1986–89) से जिला परिषद के कर्मचारियों के पेंशन देने हेतु अनुशंसा की गयी है, जिसे कमिटी द्वारा समर्पित कर दी गयी है ।

जिला परिषद कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह पेंशन देने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत हमारे 27, बाजपट्टी विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड– बाजपट्टी, नानपुर, बोखड़ा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अस्तु जनहित में प्रखण्ड बाजपट्टी, नानपुर एवं बोखड़ा में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखण्ड के भेडिहारी पंचायत के भेडिहारी ग्राम में गुजरने वाली कड़िया नदी के कटाव से जन जीवन प्रभावित हो रही है । खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उक्त स्थान पर अतिशीघ्र कटाव रोधक कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

श्री उमाकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ताओं को बहुत कम मानदेय मिलता है । जिससे उन्हें जीवनयापन में परेशानी होती है।

अतः सरकार से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय को बढ़ाने की मांग करता हूँ ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड के ग्राम जोगिया से रहमानकिता तक लगभग तीन किलोमीटर सड़क कच्ची है । ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय जाने की एक मात्र सड़क है । बरसात के दिनों में आवागमन अवरूद्ध हो जाता है ।

अतः प्राथमिकता के आधार पर सड़क के पक्कीकरण करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 मार्च को सिवान–मैरवा मार्ग पर ठेपहाँ के पास दो बाईक सवार अज्ञात वाहन के टक्कर से दुर्घटना ग्रस्त हो गए । जिसमें तीन

युवकों की मौत और दो गंभीर रूप से घायल है । मृत परिजनों को दस–दस लाख मुआवजा तथा घायलों को सरकारी खर्च पर इलाज कराने की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में आवास विहीन गरीबों के पक्का मकान बनाने की योजना चल रही है उसकी शर्त के अनुसार जिन गरीबों के आवास भूमि की बंदोबस्ती नहीं हुई है, उसको बंदोबस्त करने और पंचायतवार शिविर लगाकर जॉबकार्ड बनवाने की मांग करता हूँ ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती आजीवन गरीब और वंचित वर्ग के समग्र विकास हेतु अभियान चलाया, इनका आश्रम और कार्य क्षेत्र पटना जिला का बिहटा रहा ।

अतः सरकार से बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर कराने की मांग करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला में आवास योजना अंतर्गत प्रखंडों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के माह दिसम्बर, 2024 से फरवरी, 2025 तक निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अरवल द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है ।

सरकार से वेतन भुगतान करने की मांग करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लौरिया नगर पंचायत स्थित लौरिया के बीचोबीच खाली पड़ी पी0डब्लू0डी0 की जमीन नगर पंचायत विभाग को विभागीय रूप से स्थानांतरित कर उक्त भूखंड पर सम्राट अशोक की आदमकद प्रतिमा लगाते हुए दुकान के साथ सौंदर्यीकरण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जायेंगी ।

(सदन की सहमति हुई)

सभी माननीय सदस्यण को ध्यान रहे कि आज 62 शून्यकाल की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 31 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी जा चुकी है । अब पहले ध्यानाकर्षण सूचनाएँ हो जाए ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, मुकेश कुमार रौशन एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से <u>वक्तव्य ।</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत साधारण मिट्टी क्योंकि उसमें कुछ गलती टाईपिंग मिस्टेक में हो गयी थी । इसमें उजला बालू लिखना चाहिए था, धूस मिट्टी लिखा गया है ।

अध्यक्ष : यह गलती कैसे हो सकती है ? धूस और उजला में बड़ा अंतर है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इसमें दिया हुआ है । राज्य सरकार द्वारा मात्र एक बख्तियारपुर में घाट चालू किया गया है । जबकि दानापुर, मनेर में भी पूर्व में बालू घाटों की बंदोबस्ती की जाती थी । शहर में आम लोगों द्वारा हजारों की संख्या में भवन निर्माण एवं संवेदकों द्वारा सैकड़ों लोक निर्माण कार्यों को किया जा रहा है । जिससे साधारण मिट्टी और उजला बालू बिचौलियों के द्वारा मनमाने दामों में बेचा जा रहा है । जिसके कारण आम लोगों सहित संवेदकों को काफी अधिक राशि का भुगतान से निर्माण कार्य का व्यय भार बढ़ रहा है ।

अतः पटना जिला के दानापुर एवं मनेर में भी साधारण मिट्टी मतलब उजला बालू के अन्य घाटों की बंदोबस्ती करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

टर्न–9 / अभिनीत / 19.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री सत्यदेव राम, सतीश कुमार एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) तथा जनजाति उप योजना (TSP) अंतर्गत सरकार SC/ST की जनसंख्या के अनुपात में उनके कल्याण के लिए बजट में प्रावधान करती है जिसका व्यय उनके सीधे लाभ पहुंचने वाली योजनाओं पर ही करना है परंतु ऐसा नहीं होकर और फंड को डायवर्ट कर दिया गया है ।

CAG रिपोर्ट Finance Account Vol-II 2021–22 के अनुसार उक्त वर्ष तक सरकार ने 17445 करोड़ रुपये गैर SC/ST योजनाओं पर डायवर्ट किया है ।

बिहार बजट 2023–24 के अनुसार 16 विभागों में वर्ष 2021–22 में 10799 करोड़, वर्ष 2022–23 में 18450 करोड़ और वर्ष 2023–24 में 11796 करोड़ रुपये गैर SC/ST योजनाओं पर डायवर्ट किया है ।

भारत सरकार के SCSP पोर्टल के अनुसार 2018–19 से 2020–21 तीन वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण में केन्द्रांश 2143.80 करोड़ तथा राज्यांश 40 प्रतिशत सहित लगभग 3000 करोड़ रुपये गैर SC एवं अन्य योजनाओं में भी इस मद की राशि को डायवर्ट किया जाता है ।

अतः SCSP एवं TSP फंड के डायवर्सन पर रोक लगाने तथा आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की तर्ज पर SCSP एवं TSP कानून बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

डॉ0 सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य जैव–विविधता पर्षद से संबंधित वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल की शेष सूचनाएं ली जायेंगी ।
माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सरकार द्वारा सदन में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की घोषणा के बावजूद हाल में शिक्षा विभाग ने मौजूदा शिक्षकों को ही ट्रेनिंग देकर कंप्यूटर शिक्षक बनाने का निर्णय लिया है । इससे शिक्षक अभ्यर्थियों में हताशा है ।

पूर्व की घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बखरी विधान सभा मुख्यतः कृषि पर आधारित है । किसानों द्वारा उत्पादित आलू एवं फलों के रख–रखाव के लिए एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है ।

अतः किसानों के हित में कोल्ड स्टोरेज निर्माण करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत सदर अस्पताल में शिशु ICU वार्ड में मात्र 12 बेड हैं जिससे बच्चों को उचित चिकित्सा नहीं मिलने के अभाव में मृत्यु होने की प्रबल संभावना बनी रहती है । उक्त अस्पताल के शिशु ICU वार्ड में बेड की संख्या 25 करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत अनादीपुर स्थित एन0एच0–80 से कासड़ी, ओरियफ, एकडारा, किशनदासपुर, टोपरा होते हुए पीरपैंती तक जाने वाली 27 कि0मी0 लंबी (एम0डी0आर0) सड़क का चौड़ीकरण कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बक्सर जिला के बसदेवा थाना अंतर्गत कुकुरभुका ग्राम के एक नाबालिग लड़की को रात में घर से अगवा कर गैंग रेप कर जान से मार देने की कोशिश की गई । पीड़िता के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था करने तथा बलाकारियों को सख्त–से–सख्त सजा देने की मांग करता हूं ।

श्री शिवप्रकाश रंजन : महोदय, सरकार चांदी छात्रावास, आरा को 1990 में ही परित्यक्त घोषित कर चुकी है बावजूद इसके आज तक नए छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका । 200 दलित छात्र जर्जर एवं जानलेवा हो चुके भवन में रहने को मजबूर हैं । अविलंब नए छात्रावास के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मुंगेर जिलांतर्गत बरियापुर प्रखंड कार्यालय स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर चल रहा है । वर्ष 2012–13 में प्रखंड कार्यालय की जमीन चयनित की गयी है । मुआवजा वर्तमान समय के अनुसार नहीं दिये जाने के कारण किसान नाराज हैं ।

अतः चयनित जमीन का मुआवजा वर्तमान समय पर निर्धारित करने की मांग करता हूं ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, बिहर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसकी समय–सीमा 31 मार्च तक निर्धारित है ।

इसकी समय–सीमा को बढ़ाकर 31 अप्रैल किया जाय ताकि आवास से वंचित सभी परिवारों को आवास का लाभ मिल सके ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत के0के0एम0 कॉलेज में वर्षों से उपेक्षित पड़े कन्या छात्रावास का भवन अब खंडहर हो चुका है और अब गिरने के कगार पर है ।

अतः के0के0एम0 कॉलेज में कन्या छात्रावास के भवन का निर्माण कराने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, बिहार राज्य में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं । जन शिक्षा निदेशक के पत्रांक–2819, दिनांक–06.11.2017 द्वारा दो महीने के अंदर समायोजन करने का शपथ पत्र माननीय

सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था पर आज तक समायोजन नहीं हुआ । बिहार राज्य में छूटे हुए अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समायोजन करने की मांग करता हूं ।

टर्न–10 / हेमन्त / 19.03.2025

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधानसभा के सैफगंज पंचायत स्थित दशकों पुराना शंकरपुर शिवमंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु मंडन, विवाह, जनेऊ एवं दर्शन पूजन हेतु आते हैं, मंदिर के पास लगभग 07 एकड़ भूमि उपलब्ध है। शंकरपुर शिवमंदिर को पर्यटक स्थल घोषित कर जीर्णोद्धार एवं विकसित करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत रैयाम थाना के मौजा पचाढ़ी, समैला एवं छाछा रामपुर के चौकीदार की मृत्यु होने तथा रिटायर होनके बाद भी उनके स्थान पर चौकीदार बहाल नहीं हुआ ।

अतः उक्त स्थान पर चौकीदार की बहाली करने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सासाराम में थाना नम्बर–118, मौजा–भदोखरा लगभग 66 डीसमिल में कब्रिस्तान अवस्थित है । लंबे समय से दफनाने का कार्य होता चला आ रहा है । घेराबंदी नहीं रहने के कारण मवेशियों द्वारा कब्र को छिन–बिन एवं रास्ता को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है । उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सासाराम में शक्तिपीठ मां ताराचंडी धाम एवं तिलौथू में तुतला भवानी धाम को वैष्णों देवी के तर्ज पर विकसित करने तथा दोनों जगहों पर 100 बेड वाले आधुनिक गेस्ट हाऊस निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अन्तर्गत नगर परिषद तेघड़ा के वार्ड नं0–16 तेघड़ा बाजार में अवस्थित कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, देसरी प्रखण्ड, वैशाली के आवास सहायक श्री प्रभात कुमार को भ्रष्टाचार के कारण राघवोपुर प्रखण्ड में स्थानांतरित किया गया, किन्तु 15–20 दिनों के अन्दर वह पुनः देसरी में पदस्थापित होकर भ्रष्टाचार में लिप्त है । मैं श्री कुमार को अपने क्षेत्र के प्रखण्डों से हटाने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ एवं सुखाड़ की तरह फसल की कीटाणुओं द्वारा बर्बादी को भी आपदा की श्रेणी में लाकर किसानों को समुचित अनुदान देने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखण्ड भगवानगंज के ग्राम इंदो के पास पुनपुन नदी में बराज का निर्माण कार्य कराने की मांग सदन के माध्यम से करती हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के नरहट प्रखण्ड के पाली गांव में काव्या नामक एक लड़की का अपहरण हुआ और 15 दिनों बाद गांव के ही आहर में उसकी लाश बरामद हुई जिसकी निष्पक्ष जांच सी0बी0आई0 से कराने की मांग सरकार से करती हूं, जिसमें दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जयनगर से निःसृत पश्चिमी कमला मुख्य नहर के दक्षिण किनारे पर उसराही N.H.-227 से लेकर छतौनी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क तक वैकल्पिक यातायात हेतु पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग जनहित में सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, विश्व प्रसिद्ध न्याय विधान के दार्शनिक, शंकराचार्य के समकालीन का जन्म समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर प्रखण्ड करियन गांव में हुआ था । विगत कई वर्षों से गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर जन्म जयंती मनायी जा रही है ।

जन्म जयंती को राजकीय पर्व का दर्जा देने की मांग करता हूं ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के रेलवे स्टेशन से जानपुल चौक की तरफ जाने वाली सड़क में इडियन ऑयल से रेलवे गुमटी होते हुए लक्ष्मण चौक तक सड़क एवं नाला जीर्णशीर्ण अवस्था में है ।

आमजन हित में इस सड़क को ऊंचा एवं दोनों तरफ नाला बनाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अन्तर्गत जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में बिहियां, कटैया, लहठान सिकरिया एवं ज्ञानपुर राजवाहा का अंतिम छोर है । उपर्युक्त नहरों की सफाई नहीं होने के कारण किसानों को खरीफ में नहर का पानी नहीं मिलता है ।

अतः मैं उक्त नहरों की सफाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं0–29 कारगिल चौक से बारा वाया मदारपुर, बरबिगहा, देवरिया पथ है जिसमें नगर परिषद प्रखण्ड अंचल कोषागार जैसे आधा दर्जन कार्यालय है । हजारों लोग प्रतिदिन जाते आते हैं । पथ की हालत पैदल चलने लायक नहीं है । अविलंब मरम्मति की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में पानीफल कहे जाने वाले सिंघाड़ा की खेती काफी बहुतायत में होती है । राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने हेतु मखाना की तरह पानीफल (सिंघाड़ा) को भी जीआई टैग दिलाने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर में गौशाला के नजदीक राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पूर्णिया के द्वारा निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य संवेदक ने बंद कर दिया है । जिससे नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है । निर्माण कार्य के दौरान जमा धूल उड़ने के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है ।

अतः निर्माण कार्य जल्द शुरू करावें ।

अध्यक्ष : श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय,..

अध्यक्ष : यह शून्यकाल, चाहे तारकिशोर जी हों या सत्यदेव जी हों, केवल इसलिए आते हैं कि मैं सब पढ़ा देता हूं । अगर मैं सब पढ़ाना बंद कर दूं, तो इन लोगों का नहीं आने वाला है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह आपकी कृपा है । इससे खुश हैं हम लोग ।

अध्यक्ष : पढ़िये, आप पढ़िये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अन्तर्गत दरौली, आन्दर, गुठनी में बड़ी अग्निशामन नहीं है । आग लगने पर आपदा से निपटने के लिए 50 किलोमीटर दूर अवस्थित मुख्यालय से अग्निशमन दस्ता को आते–आते फसल या बस्ती जल कर राख हो जाती है । उपर्युक्त प्रखंडों में बड़ी अग्निशमन वाहन की मांग करता हूं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के सोनपुर प्रखंड के दूधैला पंचायतान्तर्गत ग्राम फकराबाद दलित बस्ती से मुख्य सड़क के आड़े निजी भूमि होने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है ।

अतएव उक्त दलित बस्ती के लोगों को आवागमन हेतु भूमि अधिग्रहण कराकर सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जनवरी, 2023 से एरियर बकाया है । जिसका भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

अतः पश्चिम चम्पारण के सभी शिक्षकों का बकाया एरियर शीघ्र भुगतान करने की मांग सरकार से करती हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11 / धिरेन्द्र / 19.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज ऊर्जा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर देने के लिए भी समय दिया जायेगाः–

भारतीय जनता पार्टी	– 59 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 57 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)	– 08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 02 मिनट
सी0पी0आई0	– 02 मिनट
ए0आई0एमआई0एम0	– 01 मिनट
निर्दलीय	– 01 मिनट

.....

कुल = 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 13484,35,17,000 / – (तेरह हजार चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप उस पर भी बोल लीजियेगा ।

श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री महबूब आलम से ऊर्जा विभाग के संपूर्ण मांग पर कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से ....

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

अनुदान मांग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं....

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

इन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

संपूर्ण मांग पर प्राप्त प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–173(6) के प्रथम परन्तुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दिये गये कटौती प्रस्ताव को पूर्वता दी जाती है ।

अतः माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2045, उप मुख्य शीर्ष–00 के लिए 1,18,36,000/– रुपये की माँग 5,00,000/– रुपये से घटाई जाय ।''

मितव्ययिता पर विचार–विमर्श करने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि दूरभाष, विधि प्रभार आदि मदों में कटौती किये जा सकने की गुंजाईश है । महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष : आपको पार्टी ने समय नहीं दिया । इसलिए माननीय सदस्या श्रीमती नीतु कुमारी अपना पक्ष रखें । आपका समय 14 मिनट है ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटन 13,484.35 करोड़ रुपया कुल बजट का 4.26

परसेंट, पिछली बार 2024–25 में आवंटन 11,422.68 करोड़ 01 अप्रील, 2024 से सरकार बिजली बिल में 02 परसेंट की कमी की है किन्तु आज स्थिति भयावह है । अक्षय योजना केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार बिजली उत्पादन का 17 ऊर्जा होना जरूरी है । पहले नीति में तय लक्ष्य निर्धारित ससमय पूरा नहीं हुआ है । स्मार्ट मीटर लगाने में बिहार को गोल्ड अवॉर्ड मिला है लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं के पास क्या परेशानी है यह जानने की सरकार कभी कोशिश नहीं करती है । बिहार जैसे कलहकारणी राज्य में इस सरकार के द्वारा 01 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं होता है । बड़ी चर्चाएं होती हैं कि काँग्रेस पार्टी अपने लंबे शासनकाल में कुछ नहीं की है । ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में काँग्रेस के शासनकाल में जो थर्मल पॉवर संयंत्र लगे इसके बाद आज तक किसी सरकार द्वारा एक भी संयंत्र नहीं लगाया गया । बिहार के वासियों को खरीदी हुई बिजली अधिक दाम पर मिलती है । डबल इंजन की सरकार बिजली दर बिहार जैसे गरीब राज्य को सस्ते दर पर क्यों नहीं उपलब्ध कराती है । बिहार को मिलने वाली बिजली के पीछे भी काँग्रेस सरकार का परमाणु संचालित ऊर्जा ही है । स्वर्गीय मनमोहन जी की....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने सदस्य का क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं । क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, स्वर्गीय मनमोहन जी की सरकार द्वारा पूरे देश को केन्द्रीय जोन से जोड़ने के बाद बिजली बिहार को मिल पाती है । पनबिजली योजना भी बिहार में नगण्य है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहिये ।

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, पिछले सत्र में मेरे दल के सदस्य द्वारा, डॉ॰ अजय कुमार सिंह के द्वारा तेलंगना के पनबिजली योजना की चर्चा की तथा सरकार से आग्रह किया कि इस पनबिजली योजना का अवलोकन कर बिहार में भी ऐसी योजना बनायी जाय । मैं सरकार को सुझाव देना चाहती हूँ कि बिहार में पूर्व में 11,000 एवं 33,000 वोल्ट वाले तार लगाये गये हैं जबकि बढ़ती जनसंख्या द्वारा नये घर निर्मित होने की स्थिति में सरकार ऐसे तार–पोल को सरकारी खर्चे पर हटाने का प्रबंध करे ।

सरकार हर घर बिजली की बात करती है लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो बिजली के कर्मचारियों के द्वारा कितना अत्याचार गरीब जनता, किसान और दलित महिलाओं पर किया जाता है, उनका शोषण हो रहा है । मैं पूरे बिहार की बात तो नहीं करूंगी लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में यह बताने की जरूर कोशिश करूंगी कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर,

कभी बिजली बाईपास के नाम पर जाकर छापामारी करते हैं और भारी जुर्माना, जिसका बकाया बिल अगर 2,000 रुपये है उसको 80,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाता है, उस पर एफ॰आई॰आर॰ किया जाता है । आज जमीनी स्तर पर पता किया जाय तो ऐसे–ऐसे लोगों का बिहार से पलायन हो गया है । हमारे क्षेत्र में, पूरे बिहार में ऐसी घटना घट रही है, इसकी जाँच करा कर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए । बिजली विभाग का तो इतना मनमानी है कि कोई गरीब जनता अगर फोन करेगी कि यहाँ तार खराब है, इसको बदल दीजिये तो वे लोग गरीब जनता की बात नहीं सुनते हैं और ट्रांसफार्मर जहाँ जलता है तो ट्रांसफार्मर चेंज करने में इन लोगों को 15 दिन लग जाते हैं लेकिन इन लोगों के पास कोई शिकायत यह आ जाती है कि फंलाने जगह बाईपास बिजली जलायी जा रही है.....

(व्यवधान)

बैठिये–बैठिये । ये लोग तुरंत छापामारी करते हैं और भारी जुर्माना करते हैं और जब उनलोगों से बात की जाती है तो वे लोग बोलते हैं कि सरकार का फरमान है कि बिजली बिल समय पर चुकता करना है, बिजली बिल देना है । मैं यह नहीं कहती हूँ कि कोई मुफ्त में बिजली जलाये लेकिन उसके लिए गरीब आदमी को समय देना चाहिए, किसान आदमी को समय देना चाहिए, यह कहाँ का न्याय है, गरीबों का क्या न्याय हो रहा है ? 2,000 रुपये का बिजली बिल बकाया है और उसको 80,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाता है । इसी सदन में पिछली बार मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पूरे भारतवर्ष में बिहार में बिजली बिल बहुत महंगी मिलती है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि अब तो डबल इंजन की सरकार बन गयी है तो अब बिहार में आम आदमी को कब सस्ती बिजली मिलेगी ? मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाय और विधान सभा में मैं यह बात बताउंगी कि कमेटी का गठन कर लाखों ऐसे लोग हैं जिनपर भारी जुर्माना किया गया है, वे लोग पलायन कर गए हैं, अपना घर–द्वार छोड़ कर भाग गए हैं, वैसे लोगों को बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कैम्प लगाकर सरकार को उनलोगों को राहत देनी चाहिए, जीने का अधिकार देना चाहिए । आजकल तो बिजली जो है यह हर आदमी के लिए लाइफ लाईन बन गयी है, बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है । सरकार बड़ी–बड़ी दावा करती है लेकिन जमीनी स्तर पर बिजली की क्या स्थिति है बिजली विभाग के कर्मचारियों को, उपभोक्ताओं के द्वारा क्या किया जाता है ? सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए ।

स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लगाया गया, बिहार को ईनाम मिला है लेकिन स्मार्ट मीटर का तो कहीं ऑफिस ही नहीं है, अगर स्मार्ट मीटर में कोई शिकायत हो

तो कहाँ उसकी शिकायत की जाएगी ? कोई उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? शिकायत का समाधान कहाँ होगा ? इस पर सरकार को सोचना चाहिए ।

....क्रमशः....

टर्न–12 / संगीता / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, मद्य निषेध के बारे में भी मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी । बिहार में तो शराबबंदी है, कागज पर शराबबंदी है लेकिन ऑनलाइन हर जगह उपलब्ध है । अगर आपको भी चाहिए तो 1200 के जगह पर 1400 रुपया में आपके घर में शराब पहुंच जाएगा । यह कैसी शराबबंदी है, शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है । हर जगह छापामारी होती है, शराब पीने वाले बड़े लोग नहीं पकड़ाते हैं और छोटे–छोटे जो मजदूर किसान हैं उनलोगों को पकड़ कर जेल में भेज दिया गया है । बार–बार इसमें सरकार सुझाव लाती है, बदलाव लाती है लेकिन जुर्माने की राशि 3 हजार–4 हजार कर दिया गया है । लाखों लोग बिहार के जेल में सड़ रहे हैं जिनको जुर्माना का राशि नहीं उपलब्ध है, उनको बेलर नहीं मिल रहा है कि वे लोग जेल से निकलें, इसकी भी जांच सरकार को करानी चाहिए । शराबबंदी तो जनता के पक्ष में हुआ था और 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और 2016 में शराबबंदी हुई थी, सभी लोगों के समर्थन से शराब बंद हुआ था, महिलाओं के मांग पर शराब बंद हुआ था लेकिन आज शराबबंदी की क्या स्थिति है, खुद आपलोग देखिए और सोचिए, इससे तो अच्छा है कि शराब को जो, बिहार सरकार को टैक्स की कमी हो रही है उसको पूरा कर दिया जाय और मद्य निषेध मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे आग्रह कर रही हूं कि आप ही के जाति–बिरादरी के लोग ज्यादा जेल में बंद हैं । उन लोगों को जुर्माने की राशि नहीं है, जमानतदार नहीं मिलता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अपनी बात जारी रखिए नीतु जी ।

(व्यवधान)

श्रीमती नीतु कुमारी : बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए । बोलने दीजिए । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि बिहार पूरे प्रदेश में ऐसे जो मामले हैं और जिन लोगों का बेल हो गया है, जमानत नहीं मिल रहा है, जमानतदार नहीं मिल रहा है उनलोगों को जुर्माने की राशि नहीं है उसको उपलब्ध कराकर सरकार उन्हें जेल से छुड़वाने का काम करें यह भी मैं मांग कर रही हूं । विधि विभाग के बारे में भी मैं कुछ बोलूंगी । इस बार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं ? इन्हीं के लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, इनको करने दीजिए ।

(व्यवधान)

बोलिए नीतु जी, आप बोलिए ।

श्रीमती नीतु कुमारी : विधि विभाग तो हमेशा दावा करती है कि सुशासन की सरकार है लेकिन इस बार जो खून की होली हुई है बिहार में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है । कितने लोगों का मर्डर हुआ, कितने लोगों का अपहरण हुआ, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कितना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, गृह विभाग तो दावा बहुत बड़ा–बड़ा करती है लेकिन काम नहीं हो पाता है । गृह विभाग के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि ये जो मर्डर हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, मेरे ही क्षेत्र में काव्या नाम की एक लड़की का फर्स्ट जनवरी को अपहरण होता है और 15 जनवरी को उसकी लाश उसके घर के बगल में ही रख दिया जाता है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ...

अध्यक्ष : आपका 2 मिनट बचा है ।

श्रीमती नीतु कुमारी : उसके बाद नारदीगंज पड़रिया गांव में भी एक ब्राह्मण महिला के साथ, कितना विडियो वायरल हुआ आपलोग भी देखे होंगे, उस मामले में भी आजतक कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए मैं सरकार से चाहूंगी कि सिर्फ यहां बैठकर महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के हक की बात होती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात होती है लेकिन महिलाओं को क्या न्याय मिलता है, महिलाओं का खुलेआम शोषण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए । बहुत–बहुत धन्यवाद आप लोगों का ।

अध्यक्ष : श्री कुमार सर्वजीत । माननीय सदस्य अपना पक्ष रखें, 18 मिनट का समय आपके पास है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं । महोदय, चूंकि ऊर्जा मंत्री हम सबों के अभिभावक हैं लेकिन एक समस्या यह है कि अभिभावक जो हैं बात ही नहीं सुनते हैं किसी का, हम सिर्फ ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं हम कोई आंकड़ा आपको नहीं कहेंगे । हमको बहुत खुशी है कि आपके मंत्रालय में आपके रीजन में, आपके मेहनत से गांव में बिजली आयी लेकिन गरीबों का अगर खून चूसने की बिजली हो, मुझे लगता है कि आप इतने पुराने सदस्य हैं जरूर समीक्षा आपको करनी चाहिए थी कि गांवों में किसान का बेटा, गरीब का बेटा एक सौ के बदले उसको 1 हजार बिजली बिल आ गया, 10 हजार बिजली बिल आ गया, 20 हजार बिजली बिल आ गया, आवेदन दिया, जिला में उसकी समीक्षा अधिकारियों ने किया कि नहीं किया और अगर किया तो निष्पादन उसका हुआ कि

नहीं हुआ यह हम आपसे आग्रह करेंगे महोदय । राजीव गांधी विद्युतीकरण हुई, मीटर नहीं लगा, 90 प्रतिशत गांव के गरीब–गुरबा के घर में आज भी 1–1 लाख का बिजली बिल जा रहा है यह कहते हुए कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के समय आपको 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफर्मर लगा था, आप बिजली जला रहे थे, हमने उस समय से अभी तक जोड़कर दिया है । अब आप कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, हम सब जानते हैं उसकी इन्कम 500 रुपया अगर वह रोज कमाता है तो वह अपने परिवार का भरण–पोषण करता है । अब आप बताइए कि जो व्यक्ति का आय 500 रुपया है पर–डे, उसको आपने 50 हजार का बिजली बिल दिया है, वह कहां से लाएगा, कैसे जमा करेगा ? अध्यक्ष महोदय, हमलोग एम0एल0ए0 हैं लेकिन हमलोग मानते हैं एक तो विनय बिहारी जी ने उपाधि दिया ही है हमलोग पूछताछ काउंटर हैं कोई एम0एल0ए0 का नहीं है, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हुजूर, विधायक जी फ्यूज उड़ गया, बिजली मिस्त्री, जे0ई0, आपका एग्जीक्यूटिव कोई टेलीफोन नहीं उठाता है, हमलोग परेशान हैं इतना मतलब ह्रास हो गए हैं महोदय, एक जे0ई0 कोई टेलीफोन नहीं उठाता है ग्रामीण जनता का । भाई, हमने देखा है जब प्रत्यय अमृत थे, प्रमंडलीय जाकर बैठक करते थे और हड़काते थे । मैं जो सत्य है हम उनको बधाई देना चाहते हैं लेकिन अभिभावक का उम्र हो गया है हम यह नहीं कहते हैं कि आप प्रमंडलीय दौड़िए, आप देखिए गरीबों की क्या समस्या है लेकिन आपसे आशा तो जरूर है । आखिर गरीब जो किसान है, गरीब व्यक्ति जो बिजली जला रहा है वह परेशान है किस पर आशा रखेगा, आपके अधिकारी तो कोई सुनते नहीं हैं । एक ट्रांसफर्मर बदलने के लिए एक एम0एल0ए0 को 45 बार 45 दिन टेलीफोन करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के...

(व्यवधान)

भाई, अगर हम गलत बोल रहे हैं, अच्छी बात है आपका जब टाइम आएगा तब आप सही बोल लेना । हमने जो झेला है, हमने जो देखा है, आप जेडीयू, भाजपा में हो सकता है आपकी बात मान ली जाती है, हमलोग जंगलराज वाले हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं हमलोग की बात कौन मानता है तो...

अध्यक्ष : इधर देखकर के बोलिए सर्वजीत जी ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : कम से कम सदन में तो अपनी बात को रखने दीजिएगा, यहां भी रोकिएगा? अध्यक्ष महोदय, हमने सिर्फ सुझाव दिया है । जब हमलोग मंत्री थे, पूर्णिया गए, पूर्णिया में कम से कम 50 कंपनियां आयीं, हमने कहा कि भाई चाय का इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हो, कहा कि आपका इंडस्ट्रीयल फीडर नहीं है, हम जहां से आते हैं महोदय, बोधगया से, एक हजार होटल है सिर्फ नाम का इंडस्ट्रीयल फीडर है पूरी

की पूरी इंडस्ट्रीयल फीडर से ग्रामीण का कनेक्शन जुड़ा हुआ है । एस0ई0 को बुलाया, एग्जीक्यूटिव को बुलाया, जे0ई0 को बुलाया, सबको हमलोगों ने कहा कि भाई होटल इंडस्ट्री सरकार को इतना टैक्स देती है जरा सा उसमें संशोधन कर दीजिए ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / सुरज / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्री कुमार सर्वजीत : इंडस्ट्रीयल लाईन को ठीक–ठाक रखिये, उससे बिजली जाने दीजिये । एक होटल मालिक ने एक महीने में 9 लाख रुपया डीजल का खर्चा दिया । हमने आपके प्रधान सचिव को बताया कि एक होटल इंडस्ट्री आज भी अगर 9 लाख रुपया डीजल खपत करता हो तो यह विद्युतीकरण का डिंढोरा पीटने से क्या फायदा है । हमारा बिजली बिल के भुगतान में जो परेशानी है, जो बिल ज्यादा दिया जा रहा है, गरीब लोग परेशान हैं । हम तो सिर्फ आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि जरूर इसकी समीक्षा बैठक करिये और अगर इसमें सत्यता है तो इसकी जांच होनी चाहिये और दोषी अधिकारी दंडित हों । हम यही कहना चाहते हैं ।

महोदय, मद्य निषेध की जहां तक बात है, हमलोगों ने शराबबंदी का समर्थन दिया था । हमलोगों को यह नहीं पता था कि जिस चीज का हम समर्थन देने जा रहे हैं, उस समर्थन से बड़े लोग शराब का सेवन करेंगे और गरीब–दलित का बेटा जेल जायेगा, मौत किसकी होगी गरीबों की होगी । महोदय हम दो–चार लाईन सिर्फ आपको बता देना चाहते हैं कि शराबबंदी जो मौतें हुईं, कौन लोग हैं। महोदय, अभी तक बिहार में मुझे लगता है कि जब से यह शराबबंदी लागू हुई । 2024 में 200 लोग मरे, 2023 में 200 से 250 लोग मरे, 2022 में 200 से 300 लोग मरे, 2021 में 150 से 200 लोग मरे, 2019 में 50 से 70 लोग मरे, 2018 में 20 से 30 लोग मरे मतलब लगातार मौतें होती रहीं । लेकिन हमने जो देखा इस बार के होली में, हमारे गांव में पटना से शराबबंदी की टीम आयी । 60 बोरा महुआ प्राप्त हुआ, कहीं से नहीं हमारे ही गांव से, महादलितों का गांव है । एक व्यक्ति जेल चला गया हमने पूछा कि भाई आप रिहा कैसे हो गये । उसने कहा कि 60 बोरा जिसका पकड़ाया वह 3 लाख रुपया देकर के अपना नाम हमको कर दिया और हमारा नाम उसको कर दिया । भागलपुर एक गांव है बोधगया में उसके बाद वह टीम वहां छापेमारी की । छापेमारी करना किसके यहां था, गरीब के यहां गया उसको इतना मारा–पीटा अंत में बोधगया थाना को आना पड़ा, आकर बोधगया थाना हाथ जोड़कर माफी मांगा कि यह गलत किये और जब हमलोगों ने जांच किया कि यह मद्य निषेध वाले कौन हैं, जब हिसाब–किताब हमलोगों ने बैठाया तो सिर्फ गया जिला से कम से कम 3 से 4

करोड़ रुपये का कलेक्शन होकर पटना आया । जो देने वाले उनलोगों ने कहा कि हम कैसे छूटे हैं । अब चूंकि हमारे ही विधान सभा में 7–8 ऐसे जगह थे जहां पर इस तरह की घटना हुई । शराब बिक ही रहा है, पैसा कलेक्शन हो ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है । मुख्यमंत्री जी कहेंगे कानून बना है लेकिन जांच हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय, हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार हमारे साथ मद्य निषेध मंत्री जी चले मोटरसाईकिल से और खाली खड़ा रहिये, एक मकान के पास हम खड़ा कर देंगे । अपनी आंख से आप देख लीजियेगा कि अगर शाम के 6 बजे के बाद एक–एक हजार मोटरसाईकिल का लाईन आपको नहीं दिखेगा तो मैं इस सदन में आना छोड़ दूंगा । एक बार चलकर देखिये । शराब के नाम पर गरीबों का शोषण राष्ट्रीय जनता दल, हमलोगों ने इसलिये समर्थन नहीं दिया था कि शराब के नाम पर आप सिर्फ दलितों को जेल भेज दो, गरीबों को जेल भेज दो । हमने इसलिये समर्थन नहीं दिया था कि बिहार के सभी थानों का 5 लाख से 10 लाख महीना कलेक्शन होगा इसलिये समर्थन नहीं दी गयी थी । समर्थन दिया गया था बिहार के उन महिलाओं की आवाज पर जिन्होंने कहा कि शराब पीने से हमारा घर उजड़ रहा है, हमने इसलिये समर्थन दिया था न आपको । हमने यह नहीं कहा था कि बेवजह गरीबों को, दलितों को आप जेल भेज दीजिये और उसका परिवार सड़क पर भूखा लोटे इसके लिये समर्थन नहीं दिया गया था और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिये हुये हैं, वापस ले लीजिये । जब रोक ही नहीं सकते हैं, 187 मौतें हुईं । 187 में अगर आप इन्क्वायरी करियेगा सब लोग कहीं न कहीं शराब पीकर एक्सीडेंट हुआ, मरा और मैं यह भी चुनौती देता हूं सदन के माध्यम से कि बिहार का कोई एक थानेदार बता दीजिये जिनको यह मालूम नहीं है कि कौन–कौन व्यक्ति शराब बेच रहा है, सबको पता है, सबको मालूम है । हमारा सिर्फ सुझाव होगा कि बहुत दिल की गहराईयों से, बहुत सोच–समझकर हमलोगों ने समर्थन आपको दिया था शराबबंदी के नाम पर । यह पाप के भागी हमलोगों को नहीं बनने दीजिये । अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है तो समाप्त करके कोई दूसरा कानून ले आइये । गुजरात में हैं आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे । वहां भी तो कानून बना है शराब का, लाइये । छोटे–छोटे बच्चे, नौजवान, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र–छात्राएं बैग के पीछे शराब टांगकर घर–घर डिलीवरी कर रहे हैं इसलिये नहीं मिला था आपको समर्थन । अब टी0वी0 में, चैनलों में हमलोग देखते हैं, बहुत सारे माननीय सदस्य कहते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था, आपलोग जंगलराज वाले हैं । जब मेरा जन्म हुआ था, जब हमलोगों ने होश संभाला था तो हमारे पूर्वजों ने, पिता ने कहा था

कि जिस समाज में तुम जन्म लिये हो, जहां तुम पैदा लिये हो बहुत सारे अत्याचार तुमको झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा । दलितों को आवाज मिली तो जंगलराज हो गया, पिछड़ों को आवाज मिली तो जंगलराज हो गया । महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सबका एक समय होता है । हमारे नेता लालू जी को जब राजगद्दी मिली था...

अध्यक्ष : आपका समय अब 4 मिनट है

श्री कुमार सर्वजीत : उसी समय था, वह जो समय था, वह समय ही था कि गरीबों के आवाज को बुलंद करना है । दूसरा फेज आया तो डेवलपमेंट का काम हो रहा है । कोई भी आयेगा तो डेवलपमेंट का ही काम करेगा । महोदय, हमारे नेता ने एक प्रेस–कांफ्रेस करके कहा कि एन0सी0आर0बी0 का आंकड़ा यह कहता है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते भर में बिहार में 60 हजार हत्याएं हुईं । महिला बलात्कार का मुकदमा 25 हजार हुये । पुलिस बल पिटाये, दरोगा की हत्या हुई । हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह करेंगे माननीय गृह विभाग के मंत्री महोदय को कि ये पुलिस पर हमला जो हो रहा है, इसका कारण क्या है । यह सबसे बड़ी बात है कि आखिर रक्षक के ऊपर हमला क्यों हो रहा है ? मतलब कि आपके पुलिस स्टेशन के जो दरोगा हैं, जो अधिकारी हैं उसके आचरण में कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ है तभी आम जनता आपके ऊपर गुस्सा उतार रही है ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / राहुल / 19.03.2025

श्री कुमार सर्वजीत : (क्रमशः) आपको अपने आचरण में सुधार लाना होगा । आचरण में सुधार नहीं लाइयेगा तो गांव में आप जाओगे तो हमला होगा ही । महोदय, हम लोग एम0एल0ए0 हैं, थानेदार को फोन करते हैं, लगता है जैसे किसी की हमने हत्या कर दी है और अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की भी अगर आप पैरवी कर दीजियेगा तो बिहार के थानेदार पैरवी कराने वाले को थप्पड़ मारता है ये कहकर के कि तुमने एम0एल0ए0 से पैरवी करायी है । महोदय, इस तरह का बिहेव हो रहा है और कोई ऐसा थानेदार नहीं है । मैं अकेले जात–पात, महोदय, अगर रक्षक में भी, थानेदारों में, जिला में अगर जात–पात की समस्या लाइयेगा तो कानून अपना काम कैसे करेगा ? मैं चुनौती देता हूं सदन के माध्यम से पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिये 90 प्रतिशत दलित और पिछड़ा दारोगा लाईन में बैठकर के जी–हुजूरी कर रहा है और एक ही जाति विशेष के लोग थानेदार बनकर के शराब बिकवा रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं । समीक्षा करा लीजिये, गया में 60 थाने हैं, हम अपने ही जिले की आपकी चुनौती

देते हैं । गया जिले में 60 थाना हैं, 60 में से 55 थाने के अफसर एक ही जाति विशेष के हैं, बाकी सब थानेदार बैठे हैं पुलिस लाईन में । महोदय, बिहार में कितने दलित डी0एस0पी0 बने हैं, किसकी पोस्टिंग हो रही है, समीक्षा करा लीजिये । महोदय, हम लोग इस सरकार में दलित उत्पीड़न बड़ा है । महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : जो विषय है थ्रू दी प्वाइंट बोलिये दो मिनट और हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, देश में 2012–16 तक 1 लाख 92 हजार अत्याचार हुए दलितों पर जिसमें बिहार में 5700 हैं । जब इनकी सुशासन की सरकार बहुत अच्छे से काम करने लगी 2018–20 में तो बिहार में दलितों का मुकदमा 20973 हो गये, यह दलित अत्याचार बढ़ा है कि घटा है यह हमारी समझ में नहीं है । 5 हजार से 20 हजार हो गया आप कह रहे हैं कि बिहार में दलित सुरक्षित हैं । महोदय, हम मंत्री थे, हमने एक थानेदार को फोन किया कि एक दलित व्यक्ति आया है, इसका आवेदन आप क्यों नहीं ले रहे, थानेदार ने मुझसे कहा कि आप मंत्री हैं कि संत्री हैं यह हम कैसे जानेंगे और गया के एस0पी0 को, भारती जी एस0पी0 थे मैंने फोन किया कि यह कौन दारोगा है जो इस तरह की भाषा यूज करता है, कहा कि सर उसको दंडित करेंगे । आप एस0सी0/एस0टी0 मुकदमा लेने के लिए उसको 15 दिन चक्कर काटना पड़ता है, आप बिहार का सर्वे करके हमको बता दीजिये कि पूरे बिहार में एस0सी0/एस0टी0 थाने में कितने दलित दारोगा को आपने बैठाया है, जरा हमको आंकड़ा, माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि...

अध्यक्ष : सर्वजीत जी समाप्त करिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : इतना सिर्फ बता दीजियेगा कि बिहार के एस0सी0/एस0टी0 थानों में कितने दलित दारोगा अफसर इंचार्ज हैं इतना हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : समय हो गया आपका ।

श्री कुमार सर्वजीत : ठीक है महोदय । मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं चूंकि समय हो गया है और मैं जानता हूं ज्यादा बोलेंगे तो आप डाटबे करियेगा ।

अध्यक्ष : डाटेंगे नहीं, आपकी पार्टी ने ही आपको 18 मिनट दिया है । मैने आपको पूरा बोलने का अवसर दिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह अपना पक्ष रखें । 17 मिनट का टाइम है आपके पास ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय,...

श्री सत्यदेव राम : अब तो उम्र भी हो गयी, सही बोलियेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू शुरू हो जाइये, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : सही बोले । महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जो डिमांड प्रस्तुत की गयी है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूं, बिहार की उस दारूण अवस्था का भी स्मरण कराना चाहता हूं और मैं वही से बात शुरू कर रहा हूं कि 2005 में एन0डी0ए0 जब सत्ता में आई थी, नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें हम लोग थे, उस समय कैसा बिहार था, कैसा बिहार मिला था । उस समय सड़कें कैसी थी, उस समय बिजली का उत्पादन क्या था, उस समय विद्यालय के हालात क्या थे, उस समय तमाम जो संस्थाएं थीं, चाहे शिक्षा की हों, चाहे कृषि क्षेत्र की या सहकारिता क्षेत्र की हों, उन संस्थाओं के हालात क्या थे ? महोदय, उसका हम विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहते हैं लेकिन जब भी चर्चा होती है, हम तो नहीं कभी कहते और न ही कभी कहे हैं कि जंगलराज था, हमने नहीं कहा था और कहता भी नहीं हूं और मैं जानता हूं...

(व्यवधान)

सुन लीजिये । मैं जानता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा था कि जंगलराज था । यह कहा था सत्यदेव बाबू, यह कहा था न्यायालय ने । हमने नहीं कहा था, हमने कभी नहीं कहा लेकिन न्यायालय ने कहा कि यहां तो जंगल कानून है, जंगलराज है यह उनकी जो टिप्पणी थी और उन्होंने आपके बारे में, उस समय के शासन के बारे में जो ऑब्जर्व किया था उसकी चर्चा समय–समय पर होती है । महोदय, कहां हम लोग चर्चा करते हैं लेकिन...

(व्यवधान)

सुन लीजिये । आयेंगे उस पर । आयेंगे ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू इधर देखकर बोलिये । उधर मत देखिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : हम आयेंगे उस पर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये लोग आपका समय किल कर रहे हैं आप बोलते रहिये । अपनी बात कहिये।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अब आपकी बात सुने हैं हम लोग शांत होकर, आप भी सुनिये न, कृपा करिये । विपक्ष का काम केवल खामियों को ढूंढना नहीं है, विपक्ष खूबियों की ओर भी इशारा करता है और जो सकारात्मक विपक्ष होता है उसकी यह जो भूमिका होती है तो लोकतंत्र में उसके फायदे भी नजर आते हैं ।

अध्यक्ष : जिनको टेलीफोन नहीं चलाने आता है, क्यों लेकर आते हैं, घंटी बज रही है मोबाइल की, आप ही में से किसी का होगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : लोकतंत्र मजबूत होता है और दोनों पक्ष के लोग मिलकर यदि लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो उसका जो परिणाम आयेगा वह परिणाम कितना सुखद होगा ।

दोनों पक्ष प्रसन्न होंगे । महोदय, मैं तो यह चाहता हूं और सरकार भी यह चाहती है कि आप आलोचना करें, हमारी कमियों को भी दर्शायें, लेकिन हमने कुछ अच्छा किया है तो उसको भी नजर अंदाज न करें, उसके लिए भी पीठ थपथपाएं । इसका संदेश जनता के बीच में अच्छा जायेगा । मैं आपके लिए कह रहा हूं आप शायद इस बात को नहीं समझते, आप यही समझते हैं कि हम सत्ता पक्ष को, कितनी गाली दें, कितनी उसकी आलोचना करें, कितनी शिकायत करें, जनता इसको अच्छा समझेगी, ऐसा नहीं है...

(व्यवधान)

बार–बार आप जीतते–जीतते रह जाते हैं, बार–बार प्रयास करने के बाद आप हार जाते हैं तो इन्हीं सब कारणों से ऐसा होता है । महोदय, उस समय बिहार की जो स्थिति थी, मैंने बतायी । महोदय, राज्य विभाजन के बाद जो दंश हमें झेलना पड़ा, हमारा माइंस, मिनरल, हमारी वन संपदा, हमारे सब बड़े–मझोले उद्योग–धंधे । सब कुछ झारखण्ड राज्य में चला गया । महोदय, हमारे पास बचा क्या था...

(व्यवधान)

अब बंटवारा कौन किया, बंटवारा कैसे हुआ कहेंगे तो फिर आप लोग वही बात कहेंगे...

(व्यवधान)

बंटवारा में आगे आप ही थे, आप तैयार नहीं होते तो शायद बंटवारा नहीं होता लेकिन...

(व्यवधान)

टर्न–15 / मुकुल / 19.03.2025

क्रमशः

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, बंटवारे की बात है, जिन परिस्थितियों में हुई थी, उसका मैं अवध विहारी बाबू स्मरण दिलाना चाहता हूं, आप स्मरण कीजिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, किन परिस्थितियों में राज्य बांटने के लिए आप तैयार हो गये, जल्दबाजी में बताइये आपलोग ।

(व्यवधान)

हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, आगे बढ़िए वह तो अवध विहारी बाबू गवाह हैं और हम भी गवाह हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जिस अवस्था में राज्य था, आज प्रत्येक क्षेत्र में राज्य, आप ऊर्जा की बात करते हैं । महोदय, ऊर्जा में राज्य के पूर्ण विद्युतीकरण के उपरांत उपभोक्ताओं की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है, यह तो सही है न । वर्तमान में 2 करोड़ 12 लाख से अधिक उपभोक्ता हो गये हैं, वर्ष–2005

में महोदय सिर्फ 70 लाख उपभोक्ता थे और आपका तेनुघाट चला गया उस राज्य में, दामोदर वैली चला गया उस राज्य, डी0वी0सी0 कॉरपोरेशन से जो बिजली होती थी, बिजली के सारे उत्पादन केन्द्र दूसरे राज्य में चले गये, हमारे पास क्या बचा था कांटी और बरौनी, विद्युत उत्पादन केन्द्र के क्या हालात थे ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, बर्दाश्त कीजिए आर0जे0डी0 की नई टीम है, इनके स्वभाव को बर्दाश्त कर लीजिए और आप अपनी बात को बोलते रहिए । जनता फैसला करेगी नई टीम के स्वभाव के अनुसार कितना महत्व देना चाहिए, आप बोलते रहिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वहां पर आज उत्पादन हो रहा है, उस समय महोदय, हजार, डेढ़ हजार बिजली का उत्पादन बिहार में नहीं हो पाता था । बिहार के पास हजार मेगावाट भी बिजली उपलब्ध नहीं थी, महोदय, हमें सब कुछ याद है, यहां पर अनेक ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने 2000, 2005 का वहां के नेतृत्व 1990 के समय से और देखा है सबकुछ । महोदय, पटना में बिजली की क्या स्थिति थी, यह राजधानी है, यह कैपिटल है, यहां भी 10 घंटा, 8 घंटा और 9 घंटा से अधिक बिजली नहीं मिलती थी, सीढ़ी लेकर के बिजली का मिस्त्री घूम रहा है और आप उसके पीछे आधी रात को दौड़ रहे हैं। उस समय बिजली में राज्य मंत्री थे श्याम रजक जी, रात को बिजली खत्म हो गयी, गर्मी का दिन, हमने उनको फोन किया लेकिन श्याम रजक जी ने तुरंत फोन उठाया, आधी रात को फोन उठाया, हम उनकी प्रशंसा करेंगे और उन्होंने कहा कि अमरेन्द्र बाबू हम आपको बताते हैं, उन्होंने फोन करके फिर बताया हमको कि वह मिस्त्री सीढ़ी लेकर के बोरिंग रोड की तरफ चला गया है, एक ही सीढ़ी है और उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वह सीढ़ी लेकर के आयेगा तो उसको बना देगा, दो, ढाई, तीन घंटा आप सब्र कीजिए, अब तो लाइन कट ही गया है तो क्या कीजिएगा तो ये हालात थे महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : सत्यदेव बाबू.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी कहां नौजवान के चक्कर में आप पड़ गये हैं । बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, बिजली के तीन कम्पोनेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसपर । पहला है उत्पादन/प्रोडक्शन, दूसरा है संचरण....

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, आपका केवल छः मिनट का समय बचा हुआ है, आपका 17 मिनट का आपका टाइम था बाकी हो गया ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, ठीक है । अब मैं संक्षिप्त कर रहा हूं । महोदय, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और सप्लाई, ये तीन हैं । ये तीन मुख्य कारक हैं और इन्हीं तीनों से

बिजली का उत्पादन, बिजली का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना । महोदय, आज बिहार उस हालत में पहुंच गया है कि आज साढ़े 10 हजार मेगावाट से अधिक बिजली बिहार पास है, यह गर्व करने की बात है, कहां से हुआ । इन वर्षों में बिहार बिजली के और ये हालात कैसे हुए महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास बिजली का उत्पादन है और ट्रांसमिशन का हमारा आधारभूत संरचना नहीं है, तो हम उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में असमर्थ होते तो हमने ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन और उसके लिए जगह–जगह इतने ग्रिड बनाये कि आज जितनी बिजली भी हमें मिले, जितना बिजली भी हम उत्पादन कर पाये तो उसको उपभोक्ता तक पहुंचा देंगे और महोदय, उस समय हालात क्या थे, 40 परसेंट बिजली उपभोक्ता के यहां तक नष्ट हो जाती थी, आज बहुत कम बिजली नुकसान हो रही है।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

और उपभोक्ता को पूरी बिजली पहुंचाने में हम सफल हो रहे हैं तो ये कारण है, ये इन्फ्रास्ट्रक्चर हो है, बिजली के उत्पादन के लिए, बिजली के ट्रांसमिशन के लिए, बिजली की सप्लाई के लिए हमने खड़ा किया है, इससे फायदा हुआ है । महोदय, स्मार्ट मीटर के बारे में ये इतना हल्ला करते हैं, शोर करते हैं । महोदय, स्मार्ट मीटर के कारण और इन्सुलेटेड वायर के कारण आज कितना फायदा हुआ है उस फायदे का आकलन भी आप सभी लोगों को करना चाहिए । स्मार्ट मीटर में आप कहते हैं कि शिकायत करने कहां जायेंगे, आपके हाथ में है, आप को स्वयं चेक करने का सिस्टम भी सरकार ने उपलब्ध कराया है, उसका उपयोग कीजिए । सर्वजीत बाबू, आप तो उपयोग करते हैं, आप उसका उपयोग कीजिए और आज जो नई पीढ़ी है वह नई पीढ़ी जो नहीं जानती है उनको भी सिखा रही है और वह सिस्टम है, हमारे पास समय नहीं है सिस्टम बता देंगे आपको । महोदय, सोलर प्लांट, हम बिजली की बात करते हैं, हम मद्य निषेध की बात करते हैं । बिजली की बात अब अधिक नहीं करेंगे, बहुत लम्बी है, भारी उपलब्धियां हैं, समय नहीं है कि उन उपलब्धियों को गिनाया जा सके। महोदय, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो है, केन्द्र सरकार ने भी और यह किया है, सोलर एनर्जी का भी बिहार में तेजी से उत्पादन बढ़ा है तो हम चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से यह आग्रह भी करेंगे, आरा की बात कर रहे हैं तो आरा में और उस जिले में और आसपास के भी जिले में शाहाबाद, सोन नहर प्रणाली है और उन नहरों के किनारे आप सोलर प्लेट लगवाकर के सोलर एनर्जी पैदा करने की योजना बना सकते हैं और मैं तो चाहूंगा कि आरा शहर के अंदर जो है वह डेट कैनाल है महोदय, सुन लीजिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, को बोलने दिया जाय, टोका–टोकी नहीं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : आपके यहां भी होगा, सुन लीजिए । महोदय, जो डेट कैनाल है उस डेट कैनाल पर आप उसको बना सकते हैं, करीब–करीब चार, पांच किलोमीटर का वह डेट कैनाल है, जिसका उपयोग सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए किया जा सकता है । महोदय, यही नहीं हम बिजली के क्षेत्र में सम्मानित भी हुए हैं, एकनॉमिक टाइम्स में और उसके बारे में हम विशेष नहीं कह सकते हैं । अभी बिजली विभाग के सचिव गये थे और वे अवॉर्ड लेकर के आये हैं । इस प्रकार से जो प्रशंसा हो रही है बिजली के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में जितना काम बढ़ा है उसके कारण ।

क्रमशः

टर्न–16 / यानपति / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मद्य निषेध की बात करते हैं आप, जब मद्य निषेध का कानून बनाने की घोषणा हुई थी उस समय हम सरकार में नहीं थे, हम सरकार से बाहर थे ।

उपाध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, एक मिनट का वक्त है आपके पास ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : और उस समय सरकार से बाहर रहते हुए भी हमलोगों ने मद्य निषेध कानून का मजबूती के साथ समर्थन किया और आज भी उसी मजबूती के साथ उस कानून के साथ खड़े हैं । इस कानून में जो फायदा हुआ है उसके कारण हम बता देते हैं, आपने उसका दूसरा पक्ष ज्यादा बताया है । 80 प्रतिशत लोगों ने मद्य निषेध कानून का समर्थन किया है, साढ़े 64 प्रतिशत लोगों का मानना है कि शराबबंदी से मजदूर वर्ग लाभान्वित हुआ है, साढ़े 34 प्रतिशत लोगों का मानना है कि मद्य निषेध से हजार रुपया प्रतिमाह तक की बचत हुई है । महोदय, बंदी के प्रभाव का सर्वेक्षण और यह मई 2022 में प्रतिवेदन सौंपा गया है, यह उसी का है । 62.4 प्रतिशत लोगों का मानना है कि शराब से बचत का व्यय बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है, साढ़े 67 प्रतिशत लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य पर व्यय की क्षमता में वृद्धि हुई है, 51.4 प्रतिशत लोगों ने सड़क यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित माना है, 70 प्रतिशत लोगों का मानना है कि महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है और 40 प्रतिशत लोगों का है कि पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, 80 प्रतिशत लोगों का मत है कि महिला को बाजार में भ्रमण करने में पहले से ज्यादा स्वतंत्रता है। महोदय, इन बातों को आप कहते हैं...

उपाध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, अपराध नियंत्रण में 2024 के नवंबर माह तक कुल 3 लाख 526 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, 92 नियोजित हथियार, 4861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22632 कारतूस, 604 डेटोनेटर की बरामदगी की गई है ।

उपाध्यक्ष : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है । साथ ही...

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जायं । अमरेन्द्र बाबू, आपका समय हो गया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : साथ में 122 नक्सली, महोदय, यह नक्सल फ्री प्रदेश अब बन गया है । महोदय, अवध विहारी बाबू, आप जो इशारा कर रहे हैं हम समझ रहे हैं लेकिन आप भी शिकार थे उस जमाने के । हम आपको भी स्मरण दिलाना चाहेंगे। आप हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं और मैं इतना ही अंत में कहना चाहूंगा महोदय कि बिहार ने जिस हालात से बढ़कर आज जो तरक्की की है, दुनिया इसको देख रही है, पूरा भारत देख रहा है और बिहार एक लंबी छलांग लगाकर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है और वह छलांग लगाने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है । इसका श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार के मंत्रियों को और पक्ष को मैं देता हूं और मैं अंत में अपनी बात जो माननीय मंत्री के द्वारा डिमांड प्रस्तुत किया गया है...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : उसको समर्थन देते हुए और आग्रह करता हूं कि सदन के सभी लोग और सभी सदस्य उसका समर्थन करें और सर्वसम्मति से यह डिमांड प्रस्ताव पारित करें । धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : श्री रामविलास कामत जी, आपके पास में 10 मिनट का समय है ।

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा बजट में जो ऊर्जा विभाग का मांग लाया गया है उसके समर्थन में मैं कुछ बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे समय दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, ऊर्जा विभाग के माननीय मंत्री बिजेन्द्र बाबू जो हमारे अभिभावक भी हैं उनके प्रति, श्रवण जी जो मुख्य सचेतक हैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यह बहुमूल्य समय मुझे दिया गया है, ऊर्जा विभाग की मांग के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए ।

महोदय, 2005 का वह जो वक्त था, उस समय सरकार के लिए यह उर्जा विभाग एक चुनौती हुआ करता था, चुनौती अध्यक्ष महोदय, मैं 2005 से पहले की बात नहीं करना चाहता क्योंकि 2005 के पहले की बात अगर हमलोग छेड़ते हैं, उठाते हैं तो हमारे विरोधी दल के साथियों को उसमें कठिनाई महसूस होती है, उनको

कठिनाई लगती है इसलिए मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता । महोदय, 2005 में जब नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ था तो मुझे आज भी याद है कि माननीय उर्जा मंत्री के रूप में आदरणीय बिजेन्द्र बाबू को यह जवाबदेही दी गई थी उर्जा मंत्रालय की, उपाध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला से हम आते हैं, माननीय मंत्री जी भी सुपौल से आते हैं और हमलोग माननीय मंत्री जी की देखरेख में संगठन में बहुत पहले से काम करते रहे हैं । उस समय जब बिहार में नई सरकार बनी थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए थे तो हमलोग हजारों, लाखों या जो बिहार के पूरे के पूरे लोग हैं, खुशियां मना रहे थे, उसी क्रम में सुपौल से भी सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर आए थे और माननीय मंत्री जी के आवास पर हमलोग इकट्ठा हुए थे । जब विभाग का बंटवारा हुआ और माननीय ऊर्जा मंत्री के रूप में बिजेन्द्र बाबू का नाम घोषित हुआ था तो हमलोग काफी दुखी हुए थे, हमारे जितने कार्यकर्ता साथी आए थे, सभी दुखी हो गए थे और माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे, सभी लोग अपनी भावना को बता रहे थे कि यह विभाग कौन सा विभाग है जिसमें हमेशा समस्याएं ही रहती हैं । बिजली के लिए सड़क जाम होना आम बात था, बिजली के लिए प्रदर्शन होना आम बात था, बिजली के नाम पर बिहार में कोई चीज नहीं थी, उस समय में लोगों की अवधारणा बनी हुई थी, उसी क्रम में जब कार्यकर्ता साथियों ने माननीय मंत्री बिजेन्द्र बाबू से इन बातों को रखा था तो आज भी मुझे वह दिन याद है, वह बात याद है जो माननीय मंत्री जी उस समय में कहा करते थे, कहते थे कि अगर यह जवाबदेही हमको मिली है तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और बिहार में बिजली की हालत को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं और उसको करेंगे, यह इन्होंने संकल्प लिया था । महोदय, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कहा करते थे कि कोई काम नहीं है मुश्किल, अगर किया इरादा पक्का, महोदय, मंत्री जी उस समय में भी कहते थे कि कोई काम नहीं है मुश्किल, अगर किया इरादा पक्का लेकिन पक्का इरादा तभी संभव है जब ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप काम करने में लगेंगे । कहने का मतलब उपाध्यक्ष महोदय कि ईमानदारी से अगर आप काम करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि आप विभाग में टेंडर निकालेंगे और ठेकेदार को खोजना शुरू करेंगे तो वह काम कभी पूरा नहीं हो सकता है । माननीय मंत्री जी कहा करते थे, वह कहा करते थे कि नौकरी के बदले अगर आप जमीन लिखवाना शुरू करेंगे तो वह काम कभी पूरा नहीं हो सकेगा । ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और निष्ठापूर्वक अगर लगेंगे तो बड़े से बड़े काम को भी किया जा सकता है । महोदय, मैंने इन बातों की चर्चा सिर्फ इसलिए की कि उस समय में जो बिजली की

स्थिति थी, ऊर्जा विभाग की जो सरकार में स्थिति थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं थी ।

(क्रमशः)

टर्न–17 / अंजली / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्री रामविलास कामत : पूरे बिहार में अगर देख लिया जाय तो उस समय में मात्र 700 मेगावाट बिजली बिहार को प्राप्त होता था । 700 मेगावाट बिजली में हमारा पटना क्षेत्र और पूरा बिहार 700 मेगावाट बिजली में चलता था जिसका परिणाम होता था कि 6 घंटे से 7 घंटे भी बिजली बिहार में नहीं मिलती थी। इन सारे कामों को, बिजली के सभी आयामों को दुरुस्त करने के लिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने उस समय में जो संकल्प लिया था और उस पर जो काम शुरू किया गया था उसकी चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं, सदन में करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बिहार में जो बिजली का उत्पादन था मात्र 700 मेगावाट था लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी की देखरेख में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़संकल्प ने बिहार में बिजली उत्पादन का जो संयंत्र था उसको मजबूती प्रदान किया गया, चाहे वह कॉंटी का थर्मल पावर हो, बरौनी का पॉवर स्टेशन हो या बाढ़ हो, कहलगॉंव हो सभी जगह क्षमता को बढ़ाया गया और उस पर दिन रात काम किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बिहार में बिजली की मजबूती के लिए जेनरेशन का काम, दूसरा, संचरण का काम, तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, चौथा, बिल वसूली का काम इन चार भागों में बिहार में बिजली के संयंत्रों को बांटा गया । माननीय ऊर्जा मंत्री जी की देखरेख में जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन इन चार भागों को बांटकर विभाग के पदाधिकारियों को अलग–अलग जिम्मेवारी दी गई, जवाबदेही दी गई कि आपको जेनरेशन को बढ़ाना है, आपको संचरण के काम को आगे बढ़ाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाना है और कलेक्शन को भी मजबूती से करना है इन कामों को बंटवारा करके जवाबदेही दी गई तो हम समझते हैं कि बिहार की बिजली काफी तेजी से प्रगति की और आज के समय में बिहार में 8 हजार मेगावाट से अधिक बिजली की खपत हो रही है। इसमें संकल्प सरकार का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का जो संकल्प था वह दिखाई पड़ता है और उन्होंने जो कहा था कि कोई काम मुश्किल नहीं है उसको करके दिखाया है उपाध्यक्ष महोदय । उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में बिहार आज आत्मनिर्भर हुआ है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है चाहे दिन रात बिजली के खपत का मामला हो अगर 700 मेगावाट से शुरू हुआ था तो आज 8 हजार मेगावाट पर पहुंच गया है, अगर उस समय में

बिहार में उपभोक्ता की संख्या को देखना चाहते हैं तो 67 हजार से आज 2 करोड़ 12 लाख तक उपभोक्ता की संख्या बिहार में आज पहुंची है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग के माध्यम से बिहार में जो प्रगति हुई है वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । आज बिजली नहीं तो बिहार में हर काम बंद हो जाता है, चाहे किसानों की खेती की बात हो, चाहे छोटे–छोटे उद्यमियों की बात हो ।

उपाध्यक्ष : आपके पास में मात्र 1 मिनट का वक्त है ।

श्री रामविलास कामत : सभी क्षेत्र में बिजली के माध्यम से क्रांति लायी गयी है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिजली के माध्यम से रोजगार का भी सृजन हुआ है छोटे–छोटे रोजगार हो, बड़े–बड़े रोजगार हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, या अन्य जो कुटीर उद्योग हैं बिजली के अभाव में संभव नहीं था आज बिजली की ही देन है कि लाखों लोग आज उससे रोजगार पा रहे हैं और अपना जीवनयापन कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में आज जो ई–रिक्शा है, मात्र ई–रिक्शा का अगर आकलन किया जाय तो लाखों ई–रिक्शा बिहार में दौड़ता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब अपना आसन ग्रहण करें । आपका समय हो गया है ।

श्री रामविलास कामत : जिसका स्रोत बिजली है, अगर बिजली नहीं हो तो वह बंद पड़ जाता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग का जो काम रहा है वह सराहनीय है और...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन जी । आपके पास में 12 मिनट का वक्त है । आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी तथा इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र की महान जनता को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जिनके सहयोग और आशीर्वाद से आज हम इस सदन में बोलने के लिए खड़ा हैं । महोदय, मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मैं आपके माध्यम से सरकार का कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और आपसे संरक्षण चाहूंगा कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं निश्चित रूप से सरकार अपने वक्तव्य में हमारे उठाये गये सवालों का जवाब दें और जब तक वह जवाब नहीं देती है तो संसदीय लोकतंत्र में इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, हमलोगों को बताया गया है इसी सदन में, आपके ही द्वारा और आसन के द्वारा कई बार बताया जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में जो विरोधी दल हैं

वह सरकार के ही अंग माने जाते हैं तो जब हम सरकार को सुझाव देते हैं, उनकी नीतियों में जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए हमलोग जब अपनी बात रखते हैं तो हमलोगों के द्वारा उठाये गये सवालों का भी जवाब मिलना चाहिए तभी कोई सार्थक संवाद हो सकता है । ऐसे हमारे दल के साथी पहले बोल चुके हैं, जिन बातों को उन्होंने रखा मैं उसकी चर्चा न करके मुख्य रूप से गृह विभाग और विधि विभाग जो है उसी के संबंध में हम अपनी बात रखना चाहेंगे और मैं तो उम्मीद करता था कि आज गृह विभाग का बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमलोगों की बात को सुनने का काम करेंगे । महोदय, आज हम आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर अपराध एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है और चाहे वह सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष के लोग हों सब लोग इस बात को एकाग्रचित भूमिका से स्वीकार करते हैं और बिहार की जनता आज अपराध से त्रस्त है इसमें कहीं भी इफ बट की कोई बात नहीं है और इसका जो सबसे मुख्य कारण है, बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया और बिहार में पुलिस के ऊपर आमजनों का विश्वास उठ गया है, कारण क्या है ? थाना में पुलिस के साथ जो मित्रवत व्यवहार जनता और पुलिस के सहयोग की बात कही जाती है, धरातल पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है, आम लोग आज थाना में जाने से डरते हैं, इंसान थाना के अंदर कदम रखने से डरता है और जो घटनाएं घट रही हैं पुलिस उसकी रपट तक नहीं लिखती है और रपट लिखने में भी नजराना का मांग किया जाता है, यह बिहार की पुलिस की तस्वीर है और इसी कारण आज बिहार के अंदर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी के शिकार पुलिस के लोग भी अपने गलत मनोवृत्ति के कारण, गलत आचरण के कारण आज जनता के विरोध का शिकार उनको भी होना पड़ रहा है और उनके ऊपर भी लगातार हमलाएं हो रही हैं । महोदय, आज बिहार में अपराध बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है न्यायिक व्यवस्था की धीमी गति और बढ़ते लंबित मामले, इस बात को समझना होगा सरकार को । आज पूरे बिहार में न्यायालयों की संख्या 1 हजार 682 है और उसमें मात्र 1255 वर्किंग कोर्ट हैं, 427 कोर्ट वेकंट हैं और सरकार इन कोर्टों में नियुक्ति की प्रक्रिया को बाधित करके अभी तक जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है । महोदय, उच्च न्यायालय जो हमारा है पटना हाईकोर्ट, वहां टोटल स्ट्रेंथ 55 जज का है और जिसमें मात्र 38 जज कार्यरत हैं और 13 जजों की आज भी वहां पर नियुक्ति नहीं हुई है और मुकदमा का अंबार लगा हुआ है । पूरे बिहार के अंदर जो लंबित मामले हैं सिविल केसेज का 4 लाख 23 हजार 812 सिविल के केसेज लंबित हैं, क्रिमिनल केसेज 5 लाख 78 हजार 230 लंबित हैं, टोटल 10 हजार 242 केस न्यायालयों में लंबित हैं और जो केस क्लियरेंस रेट है वह 37.57 परसेंट मात्र है । महोदय, विभिन्न

तरह के न्यायालयों का गठन किया गया, अभी एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बात कही जाती है । (क्रमशः)

टर्न–18/पुलकित/19.03.2025

(क्रमशः)

श्री राकेश कुमार रौशन : एस0सी0, एस0टी0 एक्ट के प्रोडक्शन की बहुत चर्चा होती है इस सदन में लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का 34,809 मुकदमा आज भी न्यायालयों में लंबित है और उसका डिस्पोजल रेट मात्र 1.7 प्रतिशत है । फिर एक्साइज एक्ट जिसका बहुत ढोल सरकार पीटती है । एक्साइज एक्ट में 1,14,051 मामले अभी भी लंबित है । आज इसको सरकार के सामने इन बातों को सोचने की जरूरत है। महोदय, पॉक्सो एक्ट है, स्पेशल एक्ट लागू किया गया, बिहार की बच्चियों के लिए जो उसके साथ दिन–प्रतिदिन घटनाएं घट रही है । उसका टोटल केस आज 30,203 विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है और डिस्पोजल मात्र 11,798 केसेज का हुआ है । अब ये जो लंबित मामले हैं इन लंबित मामलों का कारण क्या है ? इसको यदि आप देखेंगे तो इन लंबित मामलों का जो कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि समय पर पुलिस न्यायालयों में गवाहों को उपस्थित नहीं कर रही है । जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, उसके लिए कोई व्यवस्था अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से कैसे हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है ? महोदय, आज जो सी0आर0पी0सी0 था, जिसको बी0एन0एस0एस0 एक्ट में परिवर्तित किया गया । उस बी0एन0एस0एस0 ऐक्ट में प्रोविजन है कि जहां सात साल से ज्यादा सजा है और यदि कैदी जेल के अंदर है तो 90 दिन में उसको चार्जशीट करना है । सात साल से कम उम्र की सजा में 60 दिन में चार्जशीट सब्मिट करना है। लेकिन महोदय, आज बहुत सारे कैदियों को न्यायालय से जमानत इस आधार पर मिल रही है कि पुलिस समय पर चार्जशीट समर्पित नहीं कर रही है । दूसरा, महोदय जो समर्पित किया जा रहा है, यह तो जेल के अंदर रहने वाले कैदियों के लिए यह कानून है लेकिन जेल के बाहर जो लोग हैं उनका कितने दिन में अनुसंधान पूर्ण होगा । किसी ने इसकी व्यवस्था, न पुलिस ने व्यवस्था की और न ही बिहार सरकार ने कोई समय–सीमा बांधने का काम किया कि हम इन मुकदमों को इतने दिन में निष्पादित कर देंगे और निष्पादित करके हम बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेंगे । महोदय, यह जो पुलिस का आमजन से विश्वास समाप्त हो रहा है, इसका सबसे बडा कारण यही है और पुलिस की जो तानाशाही बढ़ रही है । आज पुलिस, हमारे बी0एन0एस0एस0 एक्ट को यदि आप देखेंगे, महोदय, आप भी पेशे से वकील रहे हैं । बी0एन0एस0एस0 एक्ट कहता है

Section 35- Police may arrest the accused person without warrant and when police cannot arrest the accused without permission of the court. महोदय, हम अपने क्षेत्र का ही उदाहरण आपको देना चाहेंगे । इस्लामपुर थाना में मुकदमा हुआ 485/2024 इसमें जितनी धाराएं लगाई गई सात साल से कम की और इसके जो मुद्दई थे सांख्यिकी पदाधिकारी इस्लामपुर के थे । 11 तारीख को एफ0आई0आर0 रजिस्टर होती है और 9 तारीख को कहते हैं कि हमको टेलीफोन से इन्फॉर्मेशन मिलती है । बिना स्टेशन डायरी में इंट्री किए हुए और न घटना की सत्यता को जांच किए हुए पुलिस 9 तारीख को 1 बजे रात में दीन दयालगंज गाँव में जाकर के बब्लू यादव के घर को खट–खटाने का काम करती है और उसकी पत्नी और बच्चों को गाली देकर के कहती है कि 24 घंटा के अंदर एक्यूज्ड को सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारे पति को हम बाजार में घूमने नहीं देंगे, उस पर गुंडा एक्ट लगा देंगे । अब बताइए महोदय, पुलिस का इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है ? सात साल की उसकी सजा है और उसको आपको नोटिस देना है, आपने न नोटिस दिया और डायरेक्ट उस पर कार्रवाई के लिए चले गए । महोदय, अभी दरभंगा का मामला हमारे माननीय ललित बाबू बोल रहे थे ।

उपाध्यक्ष : आपके पास मात्र दो मिनट का वक्त है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, ललित बाबू बोल रहे थे । दरभंगा थाना कांड सं0–69/25 है, इसमें एक सितारे मुखिया जी थे इन पर हमला हुआ और हमला के बाद इन्हीं पर झूठा मुकदमा पुलिस तीन दिन के बाद करती है और उसको जेल में डाले हुए है । महोदय, यह जो पुलिस का इकबाल है, यह पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कानून की व्यवस्था है, उसका पालन पुलिस और ये अफसर लोग अपने मनमाने ढंग से कार्य करके बिहार की जनता के साथ न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं । मैं आपको बी0एन0एस0एस0 एक्ट का एक प्रोविजन बताना चाहूंगा कि सेक्शन 175 में अब एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था है । पहले सेक्शन 154 में व्यवस्था थी । अब सेक्शन 175 में यदि कोई व्यक्ति थाना में आवेदन देता है तो पुलिस को यह अधिकार आपने दे दिया है नया एक्ट में कि 15 दिन तक उसको आप अनुसंधान के लिए पेंडिंग रख सकते हैं और 15 दिन के बाद यदि आप अनुसंधान के बाद पाइयेगा कि घटना सही है । अगर घटना सही नहीं है तो आप एफ0आई0आर0 नहीं करेंगे, तब फिर वह एस0पी0 के यहां जाएगा और नहीं तो वह न्यायालय में कम्प्लेन फाईल कर सकता है । 15 दिन में पुलिस क्या करती है ? दोनों पक्ष को बुलाकर के नजराना वसूलती है और उसके साथ–साथ पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है । इतने दिन में गवाह को धमकाकर केस को समाप्त किया जाता है ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो व्यवस्था बनाई गयी है कि Without prejudice to the provisions contained in Section 175, on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence, which is made punishable for three years or more but less than seven years, the officer in charge of the police station may with the prior permission from an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, considering the nature & gravity of the offence,- और आगे इसी में लिखता है कि proceed to conduct preliminary enquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of fourteen days; or

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि यह गंभीर विषय है । आप अपराध को समाप्त करना चाहते हैं तो पुलिस को यदि इस तरह से खुलापन दीजिएगा, 14–14 दिन तक उसको जांच के नाम पर समय दीजिएगा तो अपराधी को बिहार में नहीं बचा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : इसीलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यह जो बिहार की सरकार है इनका गुड गवर्नेंस पूरे तौर पर फेल है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, महोदय, एक मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा कि...

उपाध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी । आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : लहरों का शोर नहीं, सागर का शान्त सुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम एकान्त चुनो ।

(व्यवधान)

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से नव वर्ष के प्रथम बजट सत्र में बिहार विधान मंडल में अपने विचार एवं सरकार के पक्ष में सुझाव रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ । मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे वर्ष 2010 में सदन में लाने का काम किया और मैं अपने क्षेत्र बाराचट्टी की प्रिय जनता को भी आभार व्यक्त करती हूँ । साथ ही मैं अपनी पार्टी के संरक्षक माननीय श्री जीतनराम मांझी जी, डॉ0 संतोष कुमार सुमन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

निम्नलिखित विभागों पर अपने विचार रखती हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रान्ति लायी है । वर्ष 2005 के पहले ढिबरी और लालटेन का युग था । आज कोई भी गाँव ऐसा नहीं बचा है, जहाँ बिजली नहीं पहुंची हो, घरेलू उपयोग के साथ–साथ कृषि के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर बिजली की खपत है और 20–22 घंटे बिजली उपलब्ध है । आम जनता काफी खुश है । वर्ष 2005 के पहले समाज को डराने के लिए हमारे बीच विपक्ष के लोग मशाल का जुलूस लगाकर समाज को डराने का काम करते थे । आज इन्हें विकास नहीं दिखता है । महोदय, स्मार्ट मीटर लगाने एवं उसमें कभी–कभी तकनीकी खराबी आने से उपभोक्त को अधिक बिल मिलने से परेशानी है, सही निगरानी की आवश्यकता है ।

मद्य निषेद उत्पाद एवं निबंधन विभाग – महोदय, अपने बिहार में सरकार ने 2016 से ही पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम महिलाओं की मांग पर ही इसे लागू किया । मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ । चूंकि इसकी खुलेआम बिक्री एवं सेवन से महिलाएं ही ज्यादा भुक्तभोगी थी ।

(क्रमशः)

टर्न–19 / अभिनीत / 19.03.2025

..क्रमशः..

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, आज महिलाएं काफी खुश हैं और बाल–बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं । महोदय, शराब एक ऐसी लत है जो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है । शराब पूर्णतः बंद रहे या बंद हो जाये, इसका पूरा भार पुलिस–प्रशासन को दे दिया गया बाकी जिम्मेदारी से मुक्त हैं, इसकी समीक्षा की जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हो गया है । आप बैठ जायं ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, एक चीज मैं बहुत जरूरी बात बोलना चाह रही हूं । महोदय, यह बता देना चाहते हैं गृह विभाग से संबंधित, गृह विभाग के द्वारा भी मेरे क्षेत्र में काफी थाना भवन बने हैं । सभी क्षेत्र में बन गये । जहां पुलिस–प्रशासन बहुत मुश्किल में रहते थे वहां बने हैं और बनाने के भी कुछ सुझाव हैं जहां बनाया जा सकता है लेकिन मैं यही कहना चाहती हूं कि गृह विभाग से जो भी कार्य होते हैं चाहे थाना भवन बनता हो या कुछ भी बनता हो, यहां तक कि थाना का बिल्डिंग थाना प्रभारी शिलान्यास करते हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया अब आप बैठ जायं ।

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इजहार असफी । आपके पास में 10 मिनट का वक्त है ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, मैं आज विपक्ष द्वारा लाये गये ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बहुत–बहुत आभार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और मुख्य सचेतक अख्तरूल इस्लाम साहेब का, साथ ही क्षेत्र की महान जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें जिताकर विधान सभा भेजने का काम किया । महोदय, मैं आपके सामने और सदन के सामने एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि

''दीमाग ठंडा हो, तो कभी फैसले गलत नहीं होते,
भाषा मीठी हो, तो अपने कभी दूर नहीं होते ।''

आज के आधुनिक युग में विद्युत के बिना जीवन की कल्पना करना अधूरा है, जिसके लिए सरकार को खपत के अनुरूप उत्पादन पर बल देने की जरूरत है । सरकार द्वारा हर खेत में बिजली के तहत किसानों की सिंचाई की व्यवस्था कराने की बात कही गयी थी लेकिन अभी तक कुछ ही खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो पायी है । सिंचाई की व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी जबतक डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण न हो जाये । एक तरफ सरकार मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की बात बोलती है परंतु आवेदन के महीनों बाद भी कनेक्शन नहीं मिल पाता है । महोदय, कोचाधामन विधान सभा सहित पूरे जिले में भीषण गर्मी के दिनों में लोड शेडिंग के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है । महोदय, विद्युत आपूर्ति होने से आमजनों में काफी नाराजगी होती है । महोदय, एक तरफ सरकार बोलती है कि हर घर बिजली पहुंच गयी है लेकिन अभी भी बहुत घर अंधेरे में रहने को मजबूर हैं । महोदय, कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड 24 पंचायतों का प्रखंड है जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें मात्र तीन ही पी0एच0सी0 हैं । डेरामाड़ी में पी0एच0सी0 के निर्माण हेतु स्वीकृति मिल चुकी है परंतु अभी तक पी0एच0सी0 का निर्माण कार्य नहीं हुआ है । कोचाधामन प्रखंड के बलिया, बरबट्टा, सोनथा, भवानीगंज फीडर को छोटा किया जाय । रहमतपारा में पी0एच0सी0 का निर्माण होना चाहिए । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डेरामाड़ी और रहमतपारा में पी0एच0सी0 का निर्माण जल्द कराया जाय । महोदय, बिजली विभाग में कार्यरत मानव बल जैसे लाइंस मैन, स्वीच बोर्ड ऑपरेटर का मानदेय 10 हजार से कम है जो कि बहुत ही कम है जिससे इनके परिवार का भरण–पोषण सही से नहीं हो पा रहा है । मैं मानव बलों का मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं । महोदय, सरकार कह रही थी कि सभी गांवों, सभी नंगे वायर के स्थान पर कवर वायर लगाया जायेगा परंतु अभी तक लगभग जगह नंगे वायर लगे हुए हैं । महोदय, गृह विभाग से संबंधित कुछ मुद्दों को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । गृह विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से कोचाधामन सहित पूरे किशनगंज जिले में अवस्थित एक भी

कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य नहीं कराया गया है । विधान सभा पटल में घेराबंदी की मांग रखने पर सरकार का जवाब आता है कि प्राथमिक सूची में दर्ज नहीं है और संवेदनशील भी नहीं है, तो सरकार की क्या मंशा है कि जिस कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना हो तो पहले वहां दंगे कराये जायं । पुलिस बल को तैनात कराया जाय, फिर एस0पी0, डी0एम0 मामले की जांच अपने स्तर पर करे । प्राथमिक सूची के नाम पर दर्ज कर संवेदनशीलता प्रमाण पत्र देंगे तब जाकर कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी । महोदय, कोचाधामन विधान सभा सहित पूरे जिले में नशाखोरी की तादाद दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है जिसमें 12 साल से 18 साल के बच्चें स्मैक आदि का सेवन नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है पर सरकार नशाखोरी को रोकने हेतु कोई कदम नहीं उठा रही है । धंधे में लिप्त लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश नशाखोरी का अड्डा बन जायेगा । महोदय, एक तरफ नीतीश जी सुशासन का तमगा लेकर बैठे हुए हैं पर आये दिन लूट–खसोट, चोरी–डकैती, छिनतई, मर्डर, अपहरण, दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं । क्या यही सुशासन की सरकार है ? हमें ऐसी सुशासन की सरकार नहीं चाहिए जिसमें आमजनों में डर व भय का माहौल बना रहे । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से पहले क्या था कि बात बार–बार कर रहे हैं । 2005 से पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, हाई स्पीड नेट, हाई टेक्नोलॉजी सभी के हाथों में मल्टी मीडिया मोबाईल, सी0सी0टी0वी0, जिसको तीसरी आंख बोला जाता है, पहले ये सब थे क्या ? वर्तमान में इन सब संसाधनों के बावजूद भी आप अगर अपराधी पर शिकंजा कसने में और वारदात को नियंत्रण करने में विफल हो रहे हैं तो नीतीश जी को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है । महोदय, धनपुरा और विशनपुर थाना में दमकल गाड़ी का उपलब्ध होना अति आवश्यक है । महोदय..

(व्यवधान)

कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम ही लोग आ रहे हैं । महोदय, सीमांचल में सूर्यापुरी की आबादी बहुत है जिसकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति काफी दयनीय है । आंकड़ा बताता है कि सूर्यापुरी की स्थिति एस0सी0/एस0टी0 से भी बदतर है । मैं सूर्यापुरी बिरादरी को ई0बी0सी0 की मान्यता प्रदान करने की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है । माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : महोदय, हमारी पूरखों की दी हुई जमीन को हड़पने के मकसद से वक्फ संशोधन बिल 2024 में लाया गया है ।..

टर्न–20 / हेमन्त / 19.03.2025

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा जी । आपके पास आठ मिनट का वक्त है ।

मोहम्मद इजहार असफी : इस शेर के साथ कि–

''तूफान ज्यादा हो, तो कश्तियां डूब जाती हैं,
और घमंड ज्यादा हो, तो हस्तियां डूब जाती हैं ।''

उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें माननीय सदस्य ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपको, अपने विधायक दल के नेता को और जीरादेई की ऐतिहासिक महान जनता को अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका एहसानमंद हूं। आज ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर और साथ ही साथ गृह विभाग, मद्य निषेध, विधि विभाग सहित पांच विभागों पर बहस चल रही है, लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में 20 साल की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बिजली को छोड़ कर किसी भी प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करके नया कुछ करने का काम किया हो, तो कुछ नहीं किया है । सिर्फ और सिर्फ बिजली । मैं देख रहा हूं कि इसी मांग को प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि सरकार का कहना है कि बिजली के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है । अभी अमरेन्द्र बाबू बोल रहे थे, पूरा आंकडा दे रहे थे कि बिहार में हम लोगों ने इतना बिजली का उत्पादन किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी बिहार के अंदर दूसरे प्रदेश से बिजली ली आती है और मैं चेलेंज देकर कहता हूं कि हिंदुस्तान में सभी राज्यों से महंगी बिजली बिहार के नागरिकों को मिलती है । महोदय, और उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पूरे बिहार के भीतर जो तांडव मचा हुआ है कि गरीबों के घर में बिजली का जो बिल आ रहा है और तुरंत वहां जा कर वहां बिजली काट देने का काम, गरीबों के घर में अंधेरा लाने का काम किया जा रहा है। एक तो करैला और दूसरे चढ़ा नीम । महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अमरेन्द्र बाबू कह रहे थे कि अवार्ड मिला हुआ है बिजली विभाग के अधिकारियों को, लेकिन यह अवार्ड तो उनको दिखता है, सरकार को दिखता है, लेकिन संजीव हंस को क्या मिला है, यह सरकार को नहीं दिखता है और मैं कहता हूँ कि अडानी से, अडानी ग्रुप से एग्रीमेंट करके बिहार के गरीबों का खून चूसने वाला स्मार्ट मीटर लाकर, आज पूरे बिहार के गरीबों का खून चूसने का काम यह सरकार कर रही है । सरकार को इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो संजीव हंस के मामले में श्वेत पत्र लाने का काम करे।

महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय है, वह 66000 रूपये मात्र है, जबकि पंजाब में 195621 रूपये

प्रति व्यक्ति आय है, दिल्ली में 481910 रूपये प्रति व्यक्ति आय है और हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 105274 रूपये है। इन तीनों राज्यों में वहां के नागरिकों को दो सौ यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, लेकिन सरकार को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड अगर दे सकता है, तो बिहार सरकार दो सौ यूनिट बिजली क्यों नहीं दे सकती बिहार के लोगों को ? क्योंकि बिहार में जो जातीय गणना का सर्वे आया, वह साफ–साफ बता रहा है कि बिहार की 34 प्रतिशत आबादी, जिनकी आमदनी 6000 रूपया प्रति महीना से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को हिम्मत है कि गरीबों को फ्री बिजली दे, किसानों को खेत के लिए बिजली दे । मैं समझता हूं सरकार नहीं दे सकती है । महोदय, मैं बताना चाहता हूं गृह विभाग को, अभी हम लोगों ने मांग भी उठायी थी कि बिहार के भीतर, बिहार एक तरह से कहा जाए तो अपराध के मामले में जल रहा है और बहस कराने की जरूरत थी कि गृह विभाग पर करायी जाय, लेकिन सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि गृह विभाग पर बहस कराए, क्योंकि सरकार डर गई है और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार इतनी डरी है कि बिहार में बढते अपराध पर कोई बहस नहीं करना चाहती और इस सरकार का जाने का भी वक्त मैं समझता हूँ कि आ गया है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के भीतर बड़े पैमाने पर तो अपराध की घटनाएं हुई हैं। केवल हमारे सिवान जिला में लोकसभा चुनाव के बाद 46 जगहों पर गोली चली है। 17 जगहों पर 17 लोगों की हत्याएं हुई हैं। चंदन कुशवाहा व्यवसायी स्वर्ण व्यवसायी, गोल्डन पासवान की हत्या दिनदहाड़े हुई, चंदन कुशवाहा की बरपलिया में हत्या हुई और इसी तरीके से शाहबाज खान वकील की हत्या हुई और पूरे सिवान में आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार की घटना हुई है । इस हिसाब से अगर आप देखें, तो पूरे बिहार के भीतर अपराध का तांडव मचा हुआ है, लेकिन सरकार इस सवाल पर अगर हिम्मत है, तो बहस कराये । हम लोग कटौती प्रस्ताव भी लाये थे, लेकिन सरकार तैयार नहीं हो रही है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी होली बीती है और होली में खून की होली खेली गई है। महोदय, हम आपको बता दें कि होली में पूरे बिहार के भीतर, पूरे बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, सामंती हिंसा और हमले काफी बढ़े हैं । महोदय, इसका उदाहरण नौबतपुर में...

उपाध्यक्ष : आपके पास में एक मिनट का वक्त बचा है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, तो इस तरह से हत्याएं हो रही हैं । महोदय, शराबबंदी के सवाल पर भी सरकार पूरी तरह से फेल है । बड़े–बड़े माफियाओं को छूट है । महोदय, उन्हें आज मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार के भीतर नई पीढी को इस सरकार ने शराबबंदी के माध्यम से आपराधिक गिरोह पैदा किया है, जो खुलेआम घूम कर पूरे

बिहार में हत्या भी कर रहा है, तस्करी कर रहा है और इनके अधिकारियों के साथ बैठक कर रोज–रोज खाना खा रहा है। महोदय, निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और अंत में महोदय....

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : सरकार के लिए एक पंक्ति कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक पंक्ति है, जो इस सरकार का समय हो गया है, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि–

''दशकों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह, समय के रथ का घर्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।''

धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चन्द्रहास चौपाल जी । आपके पास में सात मिनट का वक्त है । आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, वंचितों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं नेता विरोधी दल, युवाओं के प्रेरणास्रोत आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति और सिंहेश्वर विधान सभा की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर सदन में हमको भेजने का काम किया ।

अध्यक्ष महोदय, तमाम माननीय सदस्य अपना भाषण दे रहे थे । बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है और यहां सबसे अधिक गरीब मजदूर, दलित, अतिपिछड़ा निवास करते हैं और पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली बिहार में है । बिहार से जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि जगहों पर कमाने जाते हैं, वहां हर जगह गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि यहां भी बिहार में, जो 200 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं, उनको भी यहां 200 यूनिट बिजली फ्री की जाय । महोदय, जहां तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, स्मार्ट मीटर जहां भी लगा है, वहां पर बड़ी परेशानी है । स्मार्ट मीटर से काफी अधिक बिल आ रहा है और उसमें एक और कमी है । उसमें पहले राशि डाली जाती है और बिहार के गरीब–गुरबा लोग, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने जाते हैं, उसके पास यदि सामान्य मीटर रहता है, तो छः महीना, साल भर में बिजली बिल भरने का काम करते थे, लेकिन अब उनके पास राशि नहीं है । उनकी गरीब पत्नी, छोटे–छोटे बच्चे हैं और अभी केरोसिन तेल भी सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो अंधेरे में जीवन बसर करना पड़ता है ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / धिरेन्द्र / 19.03.2025

....क्रमशः....

श्री चन्द्रहास चौपाल : महोदय, इसलिए सामान्य मीटर, जिस उपभोक्ता का मन हो तो सामान्य मीटर ही लगा कर रहे, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ और मुझे मद्य–निषेध पर भी बोलना है । खासकर बिहार में जब शराबबंदी का कानून लाया गया, हमलोगों की पार्टी भी उसके पक्ष में थी । हमलोगों को बड़ा एहसास हुआ, बिहार के गरीब आम जनता, दलित महिला, अति पिछड़ा महिला, गरीब–गुरबा में एक आशा जगी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक महिला की माँग पर यह शराबबंदी का कानून लाने का काम किये लेकिन आज बिहार में जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, 12 लाख 79 हजार 387 अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हुई हैं । महोदय, हमको लग रहा है कि सबसे अधिक गरीब, दलित, अति पिछड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास न कोई राशि है, न रुपया है, न कमाई है कि अपनी तरफ से एक वकील खड़ा कर सके और पटना हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यह अनावश्यक बोझ न्यायालय पर डाला जा रहा है । पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि शराबबंदी गरीबों के लिए मुसीबत बन गयी है क्योंकि अधिकतर गरीब लोग जेल में बंद हैं और इनके लिए यदि सरकार शराबबंदी लायी है तो अलग से एक न्यायालय की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें गरीब–गुरबा का फ्री में सुना जाय और उनको निजात मिल सके । शराबबंदी से जितनी भी हत्याएं हुई हैं अधिकतर दलित लोगों की हुई है और सत्ता–संरक्षित, सत्ता–संपोषित जो भी शराब कारोबारी हैं उनपर आज तक किसी तरह का लगाम नहीं लगाया गया है तो महोदय, हम आपके माध्यम से माँग करते हैं और आज सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, बिहार के मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री श्री रत्नेश सदा जी, जो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने विवादित बयान दिया था सीतामढ़ी के एक कार्यक्रम के दौरान, उनका बयान है कि दलित समुदाय के लोग पैसे की लालच में शराब की अवैध डिलेवरी करते हैं । उन्होंने कहा है कि एस॰सी॰ / एस॰टी॰ वर्ग के लोग शराब के अवैध धंधे को लेकर बदनाम हैं, पैसे की लालच में इस समाज के जुड़े लोग शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं इनकी गरीबी का फायदा उठाकर सत्तापोषित शराब माफिया इनके शराब की डिलेवरी कराते हैं और महोदय, हर जगह होम डिलेवरी हो रही है, इससे पहले भी माननीय सदस्य ने सदन के माध्यम से अपने वक्तव्य में कहा कि जब सरकार शराबबंदी की है तो सरकार को चाहिए कि इस पर निश्चित रूप से कड़ी–से–कड़ी मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित किया जाय और शराब के चलते आज थाना में जो थानाध्यक्षों की कमाई है वह अपार

कमाई है। हर तरह से बिहार, शराबबंदी के बारे में माननीय केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हम सब मिलकर शराबबंदी का प्रस्ताव लाये थे तो हम उसे खराब कैसे कहें लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : महोदय, गरीब लोग अगर 250 एम॰एल॰ भी शराब का सेवन कर लिये तो उसे ब्रेथ एनलाइजर लगाकर जेल भेज दिया जाता है । दूसरी ओर जो हजारों–लाखों लीटर शराब की तस्करी सत्तापोषित लोग करते हैं वे छूट जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम सफेदपोश रात में शराब पीते हैं तो हम नहीं पकड़े जाते हैं ये माननीय केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के वक्तव्य हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं पूरी दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को नजीर पेश करने के लिए जाने जाते हैं । मुझे पूरा यकीन है कि यदि पलटूमार बोलने पर माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है तो महिला के लिए शराब के नशे में धुत माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने जिन महिलाओं के साथ घोर अपमानजनक होली गाना गया तो क्या उनकी सदस्यता नहीं समाप्त की जा सकती है ? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं ? सदन के माननीय सदस्य ने जिस तरह से अमन भूषण हजारी ने...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ मिलकर शराब पीया है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : और शराब में झूम कर गाना गाते हैं तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि इस पर भी कानूनी कार्रवाई हो । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव जी। आपके पास 13 मिनट का वक्त है ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा विभाग के बजट पर मुझे बोलने का आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद । साथ ही, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दल के दोनों उप मुख्यमंत्री एवं उप मुख्य सचेतक श्री जनक जी को, जिन्होंने बोलने का यह अवसर दिया है । मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विधान सभा क्षेत्र के उन महान जनता को जिन्होंने मुझे इस सदन में चुन कर भेजा है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के नेतृत्व में और माननीय ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी के दूरदर्शी सोच एवं दृढ़संकल्प के कारण लालटेन युग की समाप्ति के पश्चात् हमारा यह बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है । महोदय, आज राज्य में पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है और वर्तमान समय में बिजली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुई है और बिजली का जो पारंपरिक

उत्पादन था उसके भी अतिरिक्त जाकर अन्य स्रोतों पर भी काम हुए हैं, अनेकों काम हुए हैं । महोदय, आज के पहले जो लालटेन युग था उस वक्त की बात मैं करना चाहता हूँ कि 07 से 08 घंटे की भी बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी लेकिन आज 24 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है और यह बिजली की आपूर्ति इसी अनुपात में माँग में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । महोदय, मैं बिजली के अन्य स्रोतों में सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर बिजली के कार्य को दृढ़ता से लागू किया गया और टाईम पर, रिकॉर्ड समय में इसे पूरा किया गया जिसका स्वरूप आज हमें हरित ऊर्जा के स्रोत में जल–जीवन–हरियाली के तहत सौर पॉवर प्लांट की स्थापना सरकारी भवनों पर की गयी, 16,167 सरकारी भवनों पर अधिष्ठापन किया गया है । इसी तरह से हर क्षेत्र में जलाशय पॉवर, इसी तरह से जल से उत्पादित विद्युत की भी आपूर्ति के लिए उन पर भी व्यवस्था की गयी है । अनेक तरह के स्रोतों से फ्लोटिंग पॉवर प्लांट जो कि मत्स्य पालन भी हो और ऊपर बिजली आधारित पॉवर भी हो तो फ्लोटिंग पॉवर प्लांट की भी स्थापना हुई है । बांका में सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है तो इस प्रकार से बिजली का स्रोत और सब तरफ से बढ़कर नहर–नाले के अवस्थित भागों में भी बिजली प्लांट स्थापित किया जा रहा है तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिजली के क्षेत्र में यह सरकार आत्मनिर्भर हो रही है, बिहार आत्मनिर्भर हो रहा है । महोदय, हमारे मंत्री बिजली के अतिरिक्त गृह विभाग के भी मंत्री रहे हैं और अभी मंत्री हैं तो मैं गृह विभाग पर भी चर्चा करना चाहूँगा ।

महोदय, गृह विभाग में आज हम देखते हैं कि जंगल राज की समाप्ति के उपरांत जो कानून का राज स्थापित हुआ है, गंभीर से गंभीर अपराध और साधारण से साधारण अपराध में भी पुलिस 15 मिनट के अंदर पहुँच कर कार्रवाई करती है । महोदय, जंगल राज में तो 15 घंटा बाद भी पुलिस नहीं पहुँचती थी और आपको मैं बताऊं कि डायल 112 पर 72 हजार कॉल प्रतिदिन रिस्पाँस लेती है और रिस्पाँस टाईम 15 मिनट होता है.....

....क्रमशः....

टर्न–22 / संगीता / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्री जय प्रकाश यादव : 15 मिनट में 72 हजार कॉल को अटेंड करती है और पुलिस रिस्पांस टाइम के अंदर पहुंचती है । अभी हमारे एक साथी चर्चा कर रहे थे कि पुलिस पर क्यों वार होता है, क्यों हो रहा है इसीलिए कि पहले तो पुलिस पहुंचती नहीं थी लेकिन अब 15 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंचती है और आपस में जो लोग तकरार

करते हैं उसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ता है और आपको मैं बताना चाहूंगा मुंगेर की जो घटना है, मुंगेर की घटना में पुलिस तत्क्षण पहुंची, वहां आपस में झंझट करके पुलिस पर हथियार चला दिया तो पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने को शहीद होकर के दूसरे को बचाए तो यही कारण है कि अभी घटनाएं पुलिस पर हो रही हैं । इसी तरह से डायल–112 में आपको पुलिस का...

(व्यवधान)

महोदय, सुन लिया जाय, पुलिस का जो वर्क है...

उपाध्यक्ष : जय प्रकाश बाबू आप आसन की ओर देखें । आप उलझें नहीं ।

श्री जय प्रकाश यादव : संपूर्ण देश में आज भी हमारे बिहार का राजीव नगर थाना, पटना का सातवां रैंक आया है कार्य प्रणाली में सुधार होने का तो यह हमारे पुलिस की देन है और आप समझ सकते हैं, इ0आर0एस0एस0 (इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सपोर्ट) के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का प्रारंभ विगत वर्षों में प्रारंभ किया गया है ।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

और आपको मैं बता दूं कि 05.09.2024 को बिहार के छः जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुरक्षित सफर का अनुपालन किया गया था, चलाया गया था और उनकी सफलता को देखते हुए इन्हें पूरे राज्य में लागू किया गया, यह हमारे सरकार की संवेदनशीलता है । महोदय, मैं 2 पंक्तियां इसपर कहना चाहूंगा कि :

''अब हर बेटी बेखौफ निकलेगी, हर मां मुस्कुराएगी
अब कानून की ताकत हर जुल्म को मिटाएगी ।''

अब बिहार में महिलाओं की जो भागीदारी है, पुलिस प्रशासन में महिलाओं को काफी भागीदारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 परसेंट रिजर्वेशन इसमें दिया था महिलाओं के लिए पुलिस बल में और उसी का कारण है कि आज भारी इजाफा हुआ है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और पुलिस में, खासकर महिलाओं को अब सुरक्षा मांगने के लिए नहीं जानी जाएंगी अब सुरक्षा देने के लिए महिलाएं जानी जाती हैं तो इस तरह से महिलाएं काफी संख्या में यहां पुलिस में भर्ती हुई हैं । पहली बार महिला बटालियन का गठन हुआ है, खासकर एस0सी0/एस0टी0 महिलाओं में स्वाभिमान का गठन हुआ है । सभी पुलिस जिला सहित रेल के चारों थाना में हरेक में महिला थाना की स्थापना की गई है । महोदय, पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं । जिले में लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी बीमारियों में राशि की बढ़ोतरी करते हुए 1 लाख की जगह 2 लाख किया गया है ।

केंद्र सरकार 1 माह के अंदर एक ''माय भारत पोर्टल'' तैयार किया है जिससे राज्य के सभी साइबर थाना जुड़ेंगे ।

अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपका 3 मिनट केवल और है ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत पहले से भी एक मांग करता आया हूं, इस सदन में पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ने हेतु आरक्षी बाल विद्यालय की स्थापना करने की मांग करता आ रहा हूं जिसका पुलिस मैनुअल रूल–1196 परिशिष्ट–91 के द्वारा उल्लेखित किया गया है । यह पुलिस कर्मियों का मूल अधिकार है । मैं माननीय मंत्री जी एवं डी0जी0पी0 साहब से भी कहना चाहूंगा कि 1196 और 91 परिशिष्ट का उल्लेख इसमें विस्तृत रूप में है और जो कॉलेज का स्थापना का, समिति का जो गठन है उसका पूरा विस्तृत विवरण इसमें है । इसी प्रकार पुलिस मैनुअल रूल–1193 के तहत पुलिस क्लब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिले में एक गेस्ट हाउस पुलिस की बननी चाहिए । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक के लिए अमृतकाल घोषित किया है । यहां कानून का राज है, किसी को न डर है न खौफ है न अन्याय का ताज है, तो इस प्रकार से पुलिस यहां निडर है, पुलिस काम करती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री भीम कुमार सिंह, 4 मिनट का समय आपके पास है भीम जी ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपने नेता परम आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी और अपने गोह विधान सभा की महान जनता को धन्यवाद देता हूं । महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा विभाग की मांग पर मैंने वित्त मंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग के 5 वर्षों के प्रस्तुत बजट भाषण का अध्ययन किया है । सभी भाषणों में एक जैसी बातें हैं । जहां ग्रीड, सब–स्टेशन के निर्माण की रफ्तार चींटी की है वहीं कजरा–पीरपैंती सोलर ग्रीड, माउंटेड सोलर पावर प्लांट आदि की चर्चा तो लगभग हर बजट भाषण में है परन्तु उस पर आज तक काम नगण्य है । महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं बजट भाषण में लगातार 3–3 वर्षों तक गंडक, बूढ़ी गंडक और महानन्दा नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने की बात कही गई है परन्तु आज तक उस दिशा में कोई कारगर काम नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इंद्रपुरी जलाशय जो औरंगाबाद और रोहतास जिला के बीच में है उस पर जल विद्युत बनाने की परियोजना बहुत दिनों से लंबित है और इसको बनाने से हम समझते हैं कि रोहतास जिला के मूल जिला औरंगाबाद जिला, गया जिला पनबिजली का बहुत हब बन जाएगा और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होगी । इसके बनने से वहां के किसानों को काफी लाभ होगा । महोदय, पिछले बजट भाषण

में सुविधा–ऐप पर बड़ा जोर दिया गया कि इसके माध्यम से पेपरलेस किया गया लेकिन आप धरातल पर जाकर देखें, भले ही आवेदन ऑनलाइन लिया जाता है लेकिन बिना रिश्वत दिए हुए किसी का भी विद्युत कनेक्शन चालू नहीं किया जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करता हूं । औरंगाबाद जिला में गोह, पुनपुन बराज...

अध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात खत्म करिए ।

श्री भीम कुमार सिंह : जो सिंचाई विभाग का बराज है, मैं समझता हूं कि अगर सरकार उस पर पनबिजली परियोजना बनाएगी तो वहां के लोग बिजली पर आत्मनिर्भर हो जायेंगे इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि गोह, पुनपुन बराज पर पनबिजली परियोजना बनाया जाय ।

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, देवकुंड एवं पंचरूखिया में नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण हो, देवरा में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र 6 वर्षों से लंबित है उसका निर्माण कराया जाय । महोदय, गोह विधान सभा में कृषि फीडर का कार्य धीमी गति से हो रहा है उसको गति दिया जाय । जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर वहां पर ट्रांसफर्मर जो कृषि फीडर का है वह नहीं लगाया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–23 / सुरज / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्री भीम कुमार सिंह : और ठेकेदार जो भी हैं, संवेदक अपने मनमाने ढंग से कार्य को कर रहे हैं. ..

अध्यक्ष : समाप्त करिये भीम जी ।

श्री भीम कुमार सिंह : कृषि फीडर में 25 के0वी0ए0 का जो ट्रांसफार्मर लगाया गया था वह करीब–करीब सब जल गया है और कोई काम का नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि 63 के0वी0ए0 का और 100 के0वी0ए0 का लगाया जाय और गोह विधान सभा बिजली पर ही खेती वहां निर्भर है...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये भीम जी हो गया आपका ।

श्री भीम कुमार सिंह : इसलिये आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां बिजली की सुविधा को मजबूत किया जाय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार जी अपना पक्ष रखें । आपके पास दो मिनट का समय है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बिजली जो है लगता है कि इसको पूरे तौर पर व्यवसाय बनाकर रख दिया गया है । यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि जो टैरिफ प्लान अभी उन्होंने शुरू किया है इससे बिजली महंगी हो जायेगी और इससे बिहार का कल्याण नहीं होगा । बिजली के बारे में हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस बिजली को हर घर तक पहुंचाने की एक परिकल्पना जो सरकार ने की थी, जरूर पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन अडाणी के पॉकेट को मोटा करने के लिये आपने जो स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता कर दी, इससे बिहार के गरीबों की बिजली कट रही है और मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं कि एक–एक गरीबों के घर पर 40, 40 हजार का फर्जी बिल जा रहा है। कहां जा रहा है आप इसको देखिये । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बिजली जो है इस देश के अंदर चार राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है गरीबों को । तो डबल इंजन की सरकार है आप भी 200 यूनिट फ्री बिजली गरीबों को दीजिये और स्मार्ट मीटर को वापस लीजिये । तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहां कृषि के लिये फ्री बिजली दी जाती है आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में तो डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है तो बिहार के किसान के लिये आप फ्री बिजली दीजिये, यह हम कहना चाहते हैं । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि गृह विभाग पर भी चर्चा आज हो रही है । गृह विभाग के क्या हालात हैं....

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, एक–दो प्वाइंट कहकर हम छोड़ दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : प्वाइंट वाइज कहिये ।

श्री अजय कुमार : जी, प्वाइंट वाइज कह रहे हैं । गृह विभाग के चर्चा हमलोग कर रहे हैं । मुंगेर और अररिया में जब ए0एस0आई0 की हत्या हो जाती है अपराधियों के द्वारा तो फिर आप क्या दंभ भरते हैं कि पूरे तौर पर सुशासन का राज है । पूरा पोल खुल जाता है, जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा । एक हाईकोर्ट का मैं सुनाकर तल्ख टिप्पणी है हाईकोर्ट का । मद्य निषेध पर 16 नवम्बर, 2024 को पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की । पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में शराबबंदी बड़ा सवाल है और शराबबंदी को लेकर के उसने कहा कि कोर्ट, पुलिस, आबकारी कर और परिवहन विभाग शराब पर रोक को पसंद कर रहे हैं और वह इसलिये पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनके कारण उनकी मोटी कमाई होती है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये । श्री सूर्यकांत पासवान ।

श्री अजय कुमार : महोदय, एक प्वाइंट कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं ...

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय....

श्री अजय कुमार : बस एक प्वाइंट...

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, आज बिजली बिल में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है । कई उपभोक्ताओं का 50 हजार से लाख रुपये का बिल आ रहा है । मीटर लगाने के नाम पर गरीबों से हजारों रुपया लिया जा रहा है । महोदय, बिजली विभाग द्वारा गरीबों के खेत तक बिजली का पोल पहुंचा दिया गया है क्योंकि किसान ऑनलाइन कनेक्शन के लिये अप्लाय किया । खेत तक बिजली नहीं पहुंची लेकिन बिल उनके घर तक पहुंच गया । महोदय, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल है। शराब बहुत आसानी से मिल रहा है लेकिन माननीय मंत्री बैठे हुये हैं हम कहना चाहेंगे कि जो बड़े–बड़े शराब माफिया हैं आज जेल के अंदर एक भी नहीं हैं । अगर हैं तो दलित, अत्यंत पिछड़ा, गरीब जितने भी लोग हैं । आज सर्वे करवा लीजिये बिहार के तमाम जेलों में अगर दारू के केस में गया है तो गरीब गया है । महोदय, आज विधि विभाग की हालत यह है, आज कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो चुकी है । हत्या, लूट, डकैती, मारपीट की बात आम हो चुकी है । महोदय, बिहार में कितने बच्चे गायब हुये हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार के बच्चे जो गायब हुये हैं उसका आंकड़ा निश्चित रूप से सदन में देना चाहिये । पिछले दिनों औरंगाबाद में कोमल कुमारी की हत्या दबंगों के द्वारा कर दी गयी । किशनगंज में जयपाल दास नामक व्यावसायी की गला रेत कर हत्या कर दी गयी। मुजफ्फरपुर में मां–बेटी की निर्मम हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया । महोदय, यहां तो पुलिस पर हमला आम बात हो गयी है । पुलिस पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है । यही आपके कानून–व्यवस्था का हाल है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री सूर्यकांत पासवान : बेगूसराय जिला में एकमात्र मंडल कारा है, उसमें कैदियों को बोरी की तरह ठूंस कर रखा जाती है । मैं मांग करना चाहता हूं सदन के माध्यम से बेगूसराय जिला में उपकारा का निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । श्री विजय कुमार मंडल, पांच मिनट में अपनी बात कहिये ।

श्री विजय कुमार मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है और इसे मुखबंध में रखा गया है जबकि गृह विभाग को प्रथम में रखा जाना चाहिये था । कारण यह कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के साथ–साथ गृह मंत्री भी हैं । उनके शासन को बुद्धिजीवियों ने सुशासन की संज्ञा दी लेकिन पिछले 20 वर्षों में संज्ञेय अपराध में लगभग 300 गुणा की वृद्धि हुई । 2005 में यह संख्या 75 हजार थी जो 2023–24 में ढाई लाख हो गयी । बिहार में अब देश मर्डर कैपिटल में तब्दील हो

रहा है । पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में लगभग 60 हजार से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं । यही लगभग 25 हजार महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुये हैं, जो बेहद चिंताजनक और भयावह है । माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन इसी सरकार में मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम कांड समेत अन्य बालिका गृहों में नृशंस हत्या और बलात्कार के मामले सामने आये । प्रदेश भर में तीन लाख चोरी की घटनाएं हुई है और बिहार में अब संगठित अपराध उद्योग का केन्द्र बन चुका है । पिछले 20 वर्षों में यहां लगभग एक लाख अपहरण के मामले दर्ज किये गये हैं । सुशासन के नाम पर शासन करने वाली सरकार वास्तव में बाजार में कैपिटल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रतीक बन चुका है, जहां पैसे के बल पर कोई भी गलत काम करवाया जा सकता है । इसमें लगभग सभी दलों ने विधान सभा में समय–समय पर अपनी आपत्ति जताई है । अब हालात इससे भी खराब हो चुका है । बिहार में आने वाले सांसद भी अपनी जान बचाने के लिये अथक प्रयास कर रहे हैं । इसका ताजा उदाहरण सासाराम के माननीय सांसद मनोज राम जी पर जो जानलेवा हमला हुआ, नौकरशाही इतना निरंकुश हो चुका है कि सरकारी कार्यक्रमों में भी सांसदों का अपमान झेलना पड़ रहा है । हाल ही में आरा में एक सरकारी कार्यक्रम में सांसद सुदामा प्रसाद जी को मंच से उतार कर जिलाधिकारी को कुर्सी दी गयी । दूसरी घटना 19 फरवरी को सासाराम में हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान वहां के माननीय सांसद श्री राजा राम सिंह को एक भी फंड नहीं दिया जायेगा, इनके इलाके की सारी योजनाएं रोक दी जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा यह बहुत ही शर्मनाक है...

अध्यक्ष : एक मिनट और है आपके पास ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, लोग 2005 से पहले की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि एन0सी0 ढौंडियाल जो बिहार के सी0बी0आई0 के आई0जी0 थे, उन्होंने लालू प्रसाद के बारे में क्या कहा । मंजरी जारूहार जो धनबाद की एस0एस0पी0 थीं उन्होंने लालू प्रसाद जी के बारे में क्या कहा । उस सरकार के बारे में मंजरी जारूहार ने क्या कहा, लालू प्रसाद जी के बारे में क्या कहा । एन0सी0 ढौंडियाल ने क्या कहा लालू प्रसाद जी के बारे में, उनके शासन के बारे में क्या कहा । जो दोनों ऊंची जाति के अधिकारी और बिहार के ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने क्या टिप्पणी किया । इसलिये बिहार में जो हो रहा है, ये जो घटनाएं घट रही है इस पर चर्चा होनी चाहिये । विशेष रूप से गृह विभाग के बारे में होनी चाहिये थी जो नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, मैं...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब ।

श्री विजय कुमार मंडल : माननीय मुख्यमंत्री जी को जबावदेही से नहीं भागना चाहिये था और गृह विभाग पर चर्चा करना चाहिये था, जो नहीं हुआ...

टर्न–24 / राहुल / 19.03.2025

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये । श्री अख्तरूल ईमान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विनय कुमार चौधरी । संक्षेप में अपनी बात कहिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अपने अभिभावक और नेता, आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिनकी कृपा से मैं यहां का सदस्य बनकर के आया हूं और आपने बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं लेकिन थोड़ा समय दे दीजियेगा यह आग्रह भी साथ ही साथ आपसे करता हूं ।

अध्यक्ष : समय नहीं है, सरकार को भी उत्तर देना है न । संक्षेप में अपनी बात कहिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : जी–जी । आज प्रतिपक्ष के नेता हम लोगों को पढ़कर आने के लिए कहे थे तो हम अब पढ़कर के आते हैं । पढ़ने के लिए कहा जाता है कि पहले इतिहास की जानकारी आवश्यक है तब वर्तमान और भविष्य में जाते हैं तो जब 2025 की बात आदरणीय नीतीश बाबू चर्चा करने लगते हैं तो ये लोग अपनी देह नोचने लगते हैं क्योंकि जब तक हम इतिहास की बात नही करेंगे तो वर्तमान और भविष्य की बात क्या कर सकते हैं तो अब आज मैं इतना ही और सबसे दुखद यह है कि नोचते–नोचते ये लोग कहने लगते हैं सूरज था, चांद था, सितारा था, अरे वह तो प्रकृति की देन है उसमें आपकी क्या भूमिका है या किसी की क्या भूमिका है । मनुष्य के द्वारा निर्मित जो वस्तु है या जो कार्य है तो उस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो वह अच्छा लगता है लेकिन उसकी चर्चा नही करेंगे । कहेंगे चांद था, सितारा था, सूरज था । अरे भाई पहले इसकी चर्चा कर लो न कि आपने क्या–क्या किया था । मैं अपने प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं, जो यहां पर नहीं हैं । बिजली थी ? बिजली का पोल था ? पोल पर तार था? तार में करंट था ? बिजली कभी आती थी ? कभी गलती से सप्ताह के बाद आ जाती थी तो वोल्टेज नहीं रहता था । बताइये न इनवर्टर चार्ज होता था ? पानी की मोटर चलती थी ? कहीं ए0सी और फ्रीज था ? विपक्ष के लोग बात करते हैं, विपक्ष के लोग जरा बतावें बिहार में रोड था ? रोड पर कंक्रीट था ? रोड में ईंट थी ? यह बतावे न रोड पर बिना एक्सल टूटे और टायर पंचर गाड़ी चलती थी, पता नहीं चलता था कि रोड था या धान का खेत था । बतावें कि पहले हेल्थ का क्या हाल था ? अस्पताल था ? अस्पताल में डॉक्टर थे ? अस्पताल में पेसेंट आते थे ? दवा रहती थी ? दवा लिखने के लिए कागज या कलम

थी ? अस्पताल के अंदर पेसेंट दिखता था ? किसी सभ्य समाज के लिए शिक्षा सबसे बुनियादी चीज है, बताइये 2000 से पहले, 2005 से पहले स्कूल थी ? स्कूल का भवन था ? स्कूल में टेबल–कुर्सी थी ? स्कूल में बच्चे थे ? बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक थे ? शिक्षक के पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड और किताब थी ? गला फाड़–फाड़ करके विपक्ष के लोग कानून व्यवस्था पर हंगामा करते हैं । मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2000 से पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात किसे कहते हैं कोई जानता नहीं था, कोई गोधूली बेला से पहले निकलता नहीं था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : पुलिस की क्या स्थिति थी ? थाना था ? थाने में सिपाही था ? पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी थी ? गाड़ी में डीजल और पेट्रोल था ? थाना में एफ0आई0आर0 लिखने के लिए कागज, पेन था ? फोन काम करता था और...

(व्यवधान)

नहीं, वह तो पूरा दिन लगा, मैं विपक्ष के लोगों को चैलेंज देता हूं कि मुझसे ही पूछ सकते हैं कि आज बिहार में का बा । महोदय, बिहार में मौज है, बिहार में आज सबे कुछ बा, बिहार में नीतीश कुमार बा, जब नीतीश कुमार बा तब सोचे के का बा । यह बिहार है । महोदय, 2005 से पहले मैं बिजली विभाग पर बात करना चाहता हूं । उपभोक्ता मात्र 17 लाख थे अभी 2 करोड़ 12 लाख हैं, बिजली की आपूर्ति पहले 7–8 घंटे रहती थी अब 24x7, न्यूनतम 23 घंटे बिजली रहती है । विद्युत की मांग पहले 700 मेगावाट थी आज बढ़कर के 8005 मेगावाट है और 2025–26 में वह बढ़कर के 8880 मेगावाट का आंकलन है । पहले प्रति व्यक्ति खपत मात्र 70 यूनिट थे आज 363 यूनिट है । ग्रिड उपकेन्द्र पहले 45 थे आज 170 हैं । संचरण लाईन की लंबाई 5 हजार सर्किट किलोमीटर थी, आज बढ़कर के 20 हजार 500 सर्किट किलोमीटर है । संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी क्षमता पहले मात्र 1 हजार मेगावाट थी, आज बढ़कर के 14928 मेगावाट हो गयी । महोदय, मैं अंत में अपने क्षेत्र की एक बात बताना चाहता हूं कि उस समय में हमारे बेनीपुर के लिए 132/33 ग्रिड सबस्टेशन की स्वीकृति हुई थी लेकिन उस समय में तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, नियम–कायदा नहीं था, वह बेनीपुर के बदले में अलीनगर में निर्माण कर लिया गया था । मैं अपने मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां बेनीपुर में भी एक निर्माण कर दें, उसका एक गठन कर दें । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार अपना पक्ष रखें । संक्षेप में अपनी बात कहिये कुंदन जी ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, 10 मिनट कहा गया था लेकिन...

अध्यक्ष : 5 मिनट में कहिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने बोलने का मौका दिया, अपने सभी नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और बेगुसराय की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपनी आवाज बनाकर इस सदन में भेजा है । महोदय, मुझे गृह विभाग और ऊर्जा विभाग पर बोलने के लिए कहा गया था । पूर्व के वक्ताओं ने काफी बातों को रखा है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2005 के पहले बिहार में बिजली का उत्पादन मात्र 600 मेगावाट था और उसमें भी डोमेस्टिक यूज केवल पटना में 250 मेगावाट का कंजम्पशन हो जाता था, आप बात समझ लीजिये कि पूरे बिहार का क्या हाल रहा होगा । महोदय, 90 का दशक था, हम लोग सैनिक स्कूल में पढ़ते थे जो झारखण्ड में चला गया। गर्मी की छुट्टी में जब घर आते थे जब शाम में 5 बजता था तो छत पर पानी डालना शुरू कर देते थे कि रात में फिर बिजली नहीं रहेगी ऊपर छत पर ही सोना पड़ेगा और दुर्भाग्य और विडंबना की बात देखिये मेरा घर आई0ओ0सी0एल0 रिफाइनरी के ठीक सामने है जब छत पर सोने जाते थे तो सामने देखते थे कि 24 घंटे लाईन, बिजली जगमगा रही है और उस जंगलराज में कहीं अगर दिन में 2 घंटे भी बिजली रह जाय तो लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गयी और सही में एक बात जो छूट गयी मैं कहना चाहता हूं कि यह बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्पित है कि किसानों को सस्ती बिजली दी जाय और इसीलिए 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का काम कर रही है नीतीश जी की सरकार जहां उत्पादन की लागत 6 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट है । महोदय, आपने कहा 5 मिनट में बात खत्म करनी है तो मैं गृह विभाग पर आना चाहता हूं कि इन लोगों ने, जो प्रतिपक्ष ने बजट में कटौती का प्रस्ताव लाया है उसके विपक्ष में मैं बोल रहा हूं । महोदय, ये गृह विभाग में भी कटाव का प्रस्ताव ले आये क्योंकि इनके समय में क्या हाल था जब भी हम लोग बात करते हैं 2005 के पहले की तो ये चिल्लाने लगते हैं । मैं सिर्फ दो–तीन उदाहरण देकर इनके सामने बात रखता हूं वह 90 का दशक जब वामपंथ के बड़े नेता चंद्रशेखर थे । महोदय, मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि वह भी मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का था, जे0एन0यू0 का दो–दो बार प्रेसीडेंट रहा था, उसकी हत्या पार्टी की मीटिंग में हो गयी दिन–दिहाड़े और जिन लोगों का नाम उस हत्या में आया क्या उसको सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त था ? इसी को तो जंगलराज कहते हैं, इसी को जंगलराज, वामपंथ के नेता थे किसी ने ऊफ तक नहीं बोला । महोदय, दूसरी हत्या वामपंथ के अजीत सरकार जी की होती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी हत्या में जो लोग शामिल थे, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था कि नहीं था ? आज ये गलबहियां करके बैठे हुए हैं, चर्चा

नहीं करते हैं, ये चर्चा नहीं करते हैं उसकी । महोदय, मैं उस समय की स्थिति पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उस समय आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अफसर भी यहां पर सेफ नहीं थे, इन लोगों को याद होगा डी0एम0 कृष्णैया का हत्याकांड । क्या हुआ था, किसके राज में हुआ था और जो लोग शामिल थे इनकी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं ? महोदय, जिधर सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है उसी को अजय बाबू, जंगलराज कहते हैं । आप जंगलराज में सम्मिलित हैं । महोदय, एक और उदाहरण दे देते हैं बिहार के एस0पी0 थे बच्चू सिंह मीणा जी, उनका एनकाउंटर सीवान में एक बाहुबली नेता उस समय राजद के थे उनके साथ चलता है और 10 घंटे तक गोली चली, 4 हजार राउंड गोली चली, पाकिस्तान मेड ए0के0–47 रायफल, ग्रेनेड, 9 एम0एम0 पिस्तोल ये सब पकड़े गये, 3–3 पुलिसकर्मी मारे गये और क्या एक्सन सरकार ने लिया ? 24 घंटे के अंदर उस एस0पी0 बच्चू सिंह मीणा का ट्रांसफर हो जाता है यही तो जंगलराज है महोदय। महोदय, इनके समय में नरसंहार होता था...

(व्यवधान)

मैसकर होता था, ये कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था ? क्या 12 फरवरी, 1992 को बारा नरसंहार नहीं हुआ, क्या 1996 में बथानी नरसंहार नहीं हुआ, क्या 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार नहीं हुआ, क्या 1999 में शंकर बिगहा नरसंहार नहीं हुआ, क्या 1999 में सेनारी नरसंहार नहीं हुआ ? महोदय, हमारे एक सदस्य इधर बैठते हैं, आज नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूंगा मैं जब भी बैठता हूं तो उधर से कहते हैं रणवीर सेना, रणवीर सेना । रणवीर सेना क्या मैं नहीं जानता हूं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, विजय सिन्हा की सरकार है इसमें किसी सेना की आवश्यकता नहीं है । यह सुशासन की सरकार है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

टर्न–25 / मुकुल / 19.03.2025

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं, महिलाओं की क्या हालत थी । अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन में अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने सुना होगा, उस समय चम्पा विश्वास एक आई0ए0एस0 की पत्नी थी, उसके साथ क्या हुआ । महोदय, ये जब सरकार में थे और अभी 2022 में जब दोबारा इनको सरकार में आने का मौका मिला, भागलपुर में नीलम यादव नाम की एक महिला थी उसके साथ क्या हाल हुआ महोदय, उसके अंगों को काटा गया और वह भी सत्ता के संरक्षण में और विडंबना यह देखिए कि एक भी नेता ने चू शब्द नहीं

किया, सरकार में ये थे और आज ये हत्या की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए । महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न दल के लगभग 16 माननीय सदस्यों ने अपने दल की विचारधाराओं को समझदारी के अनुसार यहां पर अपनी बातों को रखने का काम किया है । कुछ संक्षिप्त चर्चाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दुनिया के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, एक बात पर उनकी सहमति है If you want to elevate the poverty, you must do two things, focus the power and communication. दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है वह भी 100 परसेंट लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है, कहां से यह थ्योरी आ जा रही है । दूसरी बात क्राइम के मामले में कह रहे हैं, आज से 250–300 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सी0आर0पी0सी0, आई0पी0सी0 का कानून बनाया, आज भी वहां का जेल खाली नहीं है । अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हत्या हुई और हमारे देश में प्रधानमंत्री के घर में गोली चली, दूबे जी यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन यहां पर चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्यमंत्री गृह विभाग संभाल रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, राम–रावण, कृष्ण–कंस, दुर्योधन, दुनिया में सत्य और असत्य की हजारों साल, लाखों साल से लड़ाई चल रही है लेकिन अंततोगत्वा सत्य ही स्थापित होती है । महोदय, आज मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे, 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिंदे साहब पावर मिनिस्टर थे, विजय बाबू बैठे हुए हैं । शिंदे साहब के भाषण को मैं कोट करता हूं, शिंदे साहब ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कलिग्स भी पूरे देश के यहां पर बैठे हुए हैं आज से कुछ दिन पहले जब किसी आदमी को यह ऊर्जा विभाग मिलता था तो क्षेत्र के लोग भी कहते थे कि आपने इस विभाग को क्यों लिया यह तो शहर का विभाग है और आज पुतले दहन होते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, सड़क जाम होती है और देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा आयेगा कहां से, जब बिजली हर घर होगी, महोदय, यह स्थितियां थीं, सच्चाई को कबूल करना चाहिए, बहस करना अपनी जगह पर है, अपने दल के अनुसार अपनी बातों को रखना अपनी जगह पर है । अभी एक माननीय सदस्य ने बहस में कहा कि बिहार का बंटवारा कैसे हुआ, क्यों इतना कम पावर बचा । एक बात याद रखिए, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं लेकिन जब पत्नी को मोहब्बत नहीं हुआ तो कांग्रेस के संरक्षण से घुटना टेक हो गया, बिहार

बंटवारे पर सहमति व्यक्त की, यह सब इतिहास का हिस्सा है । इसलिए इन सब बातों पर ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा ।

महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि ये बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, नहीं तो शायद बिजली में इतनी प्रगति नहीं होती अगर ये बिजली विभाग के इंजीनियरिंग पास नहीं किये होते, क्योंकि यह बड़ा ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है । अब यहां लोग ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफर बोलते हैं, यह भी एक दुर्भाग्य की बात है । महोदय, यहां पर बिजली उत्पादन की चर्चा हो रही थी । वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित, बरौनी, काँटी, बाढ़, नबीनगर, कहलगाँव में स्थित ताप विद्युत प्रतिष्ठान की कुल विद्युत क्षमता 8850 मेगावाट है । बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 660 मेगावाट क्षमता की एक नये इकाई से विद्युत उत्पादन इसी वर्ष प्रारंभ हो जाएगी । महोदय, मैं इसकी भी कहानी कहता हूं, सरकार जमीन नहीं दे रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय रेल मंत्री थे, वाजपेयी जी को लाकर के बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान का शिलान्यास करवाया था आज भी अंतिम यूनिट नहीं बन पाया है, इसलिए कि उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कम्पनियां थीं वे भागती रहीं, काम नहीं कर पाईं । बक्सर स्थित निर्माणाधीन चौसा में 1320 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत प्रतिष्ठान से वर्ष 2025–26 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगी । भागलपुर के पीरपैंती में अभी जिक्र कर रहे थे, 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है । इस परियोजना के लिए Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के तहत निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । बिहार में अब तक की सबसे बड़ी निजी निवेश वाली परियोजना होगी, 800 मेगावाट की तीन यूनिट, 2400 मेगावाट की प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आयेगा सबसे कम टैरिफ पर । जल–जीवन–हरियाली अभियान के एक अवयव सौर ऊर्जा के विकास के तहत अबतक कुल 11,383 सरकारी भवनों पर 100 मेगावाट तथा 5,683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाये जा चुके है। राज्य में अबतक 178 मेगावाट की अन्य सौर परियोजनाओं से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है । ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के तहत दरभंगा में 1.6 मेगावाट की एवं सुपौल में 525 किलोवाट की परियोजनाएँ संचालित हैं तथा फुलवरिया नवादा में 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है । राज्य में नहरों के किनारे सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में 2 मेगावाट की परियोजना निमाणाधीन है । फीडर सोलराईजेशन के तहत राज्य के किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए, इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा 1. 05 करोड़ रूपये एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 45 लाख रूपये अनुदान स्वरूप

राशि दी जाएगी । राज्य में कृषि फीडरों के सोलराईजेशन का कार्य प्रगति पर है ।

महोदय, राज्य में लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की दो परियोजनाएँ कुल 495 मेगावाट आवर बैटरी भण्डारण क्षमता के साथ निर्माण की प्रक्रिया में है । यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भण्डारण क्षमता की परियोजना होगी, इससे पीक आवर में सस्ती बिजली की उपलब्ध होगी । राज्य में इस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के नये स्रोतों विशेषकर पम्प स्टोरेज पावर प्रणाली के विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है । बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के सबसे अधिक 90000 करोड़ रुपये निवेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेत्र में करने हेतु एकरारनामा किया गया है, जल्द ही इसका परिणाम आयेगा। राज्य में संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 07 नये ग्रिड उपकेन्द्रों निर्माण किया गया है । इस प्रकार अब राज्य में कुल ग्रिड उपकेन्द्रों की संख्या 170 हो गई है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेन्द्रों के निर्माण की घोषणा की गई, जिनकी स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। राज्य के संचरण कम्पनी द्वारा इस वर्ष पहली बार जी0आई0एस0 तकनीक पर आधारित तीन ग्रिड उपकेन्द्रों को ऊर्जान्वित किया गया है । संचरण कम्पनी को इस वर्ष भारत सरकार की संस्था द्वारा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए A+ रैंकिंग का अवॉर्ड दिया गया है । मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत कुल 15,343 करोड़ रूपये अनुदान दिया गया है, 15,343 करोड़ अनुदान देकर लोगों को सस्ती बिजली दी जा रही है ।

क्रमशः

टर्न–26 / यानपति / 19.03.2025

(क्रमशः)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आप 200 मेगावाट की बात कह रहे हैं । इसके तहत सिंचाई के लिए किसानों को बिजली बिल पर 92 प्रतिशत की छूट देते हुए मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है जिससे बिजली से सिंचाई करना डीजल की तुलना में 10 गुना से अधिक सस्ता है । मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधन योजना के तहत राज्य सरकार के इच्छुक किसानों को मुफ्त विद्युत संबंधन प्रदान किया जा रहा है । कुल निर्धारित लक्ष्य 8.40 लाख के विरुद्ध अभी तक 5.81 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है । शेष सभी कनेक्शन सितम्बर 2026 तक दिये जाने का लक्ष्य है । आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत अब तक 920 कृषि फीडरों का निर्माण किया जा चुका है । पूर्व की योजना से निर्मित कृषि फीडरों के

साथ मिलाकर राज्य में अब कुल 2274 कृषि फीडरों का निर्माण हो चुका है । महोदय, बिहार स्मार्ट प्री पेड मीटर अधिष्ठापन में अग्रणी राज्य है । अब तक पूरे राज्य में 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्री पेड मीटर अधिष्ठापन किया जा चुका है । माननीय सदस्य ने कहा था संजीव हंस का मामला सुप्रीम कोर्ट से प्री पेड मीटर का टेंडर का हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में कंपनी के निर्णय को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया, इसके बाद इस कंपनी को दिया गया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए । इसीलिए इसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है । ऊर्जा विभाग एवं विद्युत कंपनियां बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा एवं सुविधा डेस्क, फ्यूज कॉल, 1912–कॉल सेंटर, विशेष कैंप तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम आदि का गठन किया गया है । आप लोग कह रहे थे कि शिकायत के लिए कोई फोरम नहीं है । महोदय, बिजली की उपलब्धता 2005 में 7–8 घंटा रहती थी, अब चौबीसों घंटे रहती है । पीक लोड 700 मेगावाट था उसमें 150 मेगावाट करीब नेपाल को जाता है । वह दिन याद है हम थे किशनगंज में मुख्यमंत्री जी ने फोन किया हमारे अफसर को, उन्होंने कहा कि नेपाल को बिजली देनी है मुख्यमंत्री जी का कहना है, हम बोले अपने भूखा और दूसरे को न्योता यह नहीं होनेवाला है, इन्होंने फोन किया कि तीन–तीन, चार–चार बार प्राइम मिनिस्टर फोन किए हैं कि दे दीजिए, एक जमाना वह भी था । उपभोक्ताओं की संख्या 2005 में थी 17 लाख और आज है 2 करोड़ 12 लाख, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 70 यूनिट था 2005 में, आज है 363 यूनिट, ग्रिड की संख्या 45, आज है 170, शक्ति उपकेंद्र की संख्या 368, अब है 1263 ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस उस समय में, 2005 में था 59.24 प्रतिशत, लगभग 60 परसेंट, आज है 19.94 प्रतिशत । महोदय, और भी मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं । आगे आनेवाले वक्त में अभी कई माननीय सदस्यों ने सब स्टेशन की बात की, करीब–करीब ढाई सौ सब स्टेशन अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग शुरू करने जा रहे हैं । कजरा फेज–2 के अंतर्गत 116 मेगावाट सौर संयंत्र 241 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं कजरा फेज–1 के अंतर्गत 185 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 254 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता से उत्पादन प्रारंभ होगा । बिहार के 16 ग्रिड सब–स्टेशन में उपलब्ध जमीन पर 500 मेगावाट आवर बैट्री इनर्जी स्टोरेज क्षमता जितने सब स्टेशन हैं उसमें भी लगेगा, अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा । बड़े पैमाने पर 11 के0वी0 कृषि एवं मिक्स्ड फीडरों के सोलराईजेशन का कार्य किया जायेगा जिससे क्रमवार ढंग से किसान अपने खेतों के पटवन का कार्य सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे । पीरपैंती में थर्मल पावर जिसका मैंने जिक्र किया, दुर्गावती में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना, 20 मेगावाट का नहरों के किनारे एवं 20 मेगावाट का तालाब/चौर के

ऊपर रेज्ड स्ट्रक्चर पर सौर ऊर्जा की परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा । संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान में कुल 10 ग्रिड उपकेन्द्र निर्माणाधीन हैं । इसे वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूरा कर लिया जायेगा । इसके द्वारा विभिन्न पावर सब–स्टेशनों के माध्यम से निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेंद्रों यथा अमवामन (पश्चिमी चंपारण), मेजरगंज (सीतामढ़ी), महुआ (वैशाली), मैरवा (सिवान), वारिसनगर (समस्तीपुर), चौसा (मधेपुरा), अमरपुर (बांका), हलसी एवं बड़हिया (लखीसराय), रोह (नवादा) के निर्माण की घोषणा की गई । इस हेतु कुल 1918.28 करोड़ रुपये की योजना पर स्वीकृति दी गई है । इन ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में मिशन मोड में कराया जायेगा । महोदय, वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही 7305.05 करोड़ की आर0डी0एस0एस0 योजना के लॉस रिडक्शन के तहत विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ नये कृषि फीडरों का निर्माण अगले साल पूर्ण कर लिया जायेगा । जिसके माध्यम से सभी खेतों तक सिंचाई का पानी डेडीकेटेड फीडर के माध्यम से पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी । अगले वर्ष में निर्माणाधीन 41 पावर सब–स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जायेगा एवं स्वीकृत 117 नये पावर सब–स्टेशन के निर्माण का कार्य मिशन मोड में कराया जायेगा । 104 नये पावर सब–स्टेशन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । इन पावर सब–स्टेशनों के निर्माण से राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी । पटना शहर के विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 296.93 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है । अगले वर्ष में इसका कार्य मिशन मोड में कराया जायेगा। राज्य के पश्चिमी चंपारण, सुपौल, कैमूर, रोहतास, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, कटिहार, पूर्णिया एवं बांका जिलान्तर्गत 219 गांवों के 42621 घरों को, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी दुर्गम हैं, इन क्षेत्रों को पूर्व में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली पहुंचाई गई थी, उसे ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त महोदय, मैं एक बात और जिक्र करना चाहूंगा पिछले वर्ष जो कंपनी प्रॉफिट में गई तो 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर उपभोक्ताओं को घटाने का निर्णय लिया गया । इतनी ही बात कह कर महोदय, मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्य से, सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बजट को पारित करने की कृपा की जाय ।

(माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग का लिखित वक्तव्य – परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2045, उप मुख्य शीर्ष–00 के लिए 1,18,36,000/– रुपये की मांग 5,00,000/– रूपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 13484,35,17,000/– (तेरह हजार चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–37 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

माननीय ऊर्जा मंत्री के लिए विधानमण्डल में सम्बोधन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु।

माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृतव एवं मार्गदर्शन में ऊर्जा विभाग ने विद्युत के तीनों प्रक्षेत्रों : उत्पादन, संचरण एवं वितरण में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

उत्पादनः–

- वर्त्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित, बरौनी, काँटी, बाढ़, नबीनगर (02 प्रतिष्ठान), कहलगाँव में स्थित ताप विद्युत प्रतिष्ठान की कुल विद्युत क्षमता 8850 मेगावाट है।
- बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 660 मेगावाट क्षमता की एक नये इकाई से विद्युत उत्पादन इसी वर्ष प्रारंभ हो जाएगी।
- बक्सर स्थित निर्माणाधीन चौसा में 1320 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत प्रतिष्ठान से वर्ष 2025–26 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगी।
- भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इस परियोजना के लिए Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के तहत निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। बिहार में अब तक की सबसे बड़ी निजी निवेश वाली परियोजना होगी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

- **जल–जीवन–हरियाली** अभियान के एक अवयव सौर ऊर्जा के विकास के तहत अबतक कुल 11383 सरकारी भवनों पर 100 मेगावाट तथा 5683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाये जा चुके है।
- राज्य में अबतक 178 मेगावाट की अन्य सौर परियोजनाओं से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।
- **'ऊपर बिजली नीचे मछली योजना'** के तहत् दरभंगा में 1.6 मेगावाट की एवं सुपौल में 525 किलोवाट की परियोजनाएँ संचालित हैं तथा फुलवरिया नवादा में 10 मेगावाट की फ्लोंटिंग सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है।
- राज्य में नहरों के किनारे सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में 2 मेगावाट की परियोजना निमाणाधीन है।
- **फीडर सोलराईजेशन** के तहत राज्य के किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा 1.05 करोड़ रूपये एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 45 लाख रूपये अनुदान स्वरूप राशि दी जाएगी। राज्य में कृषि फीडरों के सोलराईजेशन का कार्य प्रगति पर है।

- राज्य में लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की दो परियोजनाएँ कुल 495 मेगावाट आवर बैटरी भण्डारण क्षमता के साथ निर्माण की प्रक्रिया में है। यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भण्डारण क्षमता की परियोजना होगी। इससे पीक आवर में सस्ती बिजली की उपलब्ध होगी।
- राज्य में इस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के नये स्रोतों विशेषकर पम्प स्टोरेज पावर प्रणाली के विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है।
- बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के सबसे अधिक 90000 करोड़ रुपये निवेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेत्र में करने हेतु एकरारनामा किया गया।

<u>संचरण प्रक्षेत्र</u>

- राज्य में संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 07 नये ग्रिड उपकेन्द्रों निर्माण किया गया है। इस प्रकार अब राज्य में कुल ग्रिड उपकेन्द्रों की संख्या 170 हो गई है।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी **प्रगति यात्रा** के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेन्द्रों के निर्माण की घोषणा की गई, जिनकी स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।
- राज्य के संचरण कम्पनी द्वारा इस वर्ष पहली बार **जी0आई0एस** तकनीक पर आधारित तीन ग्रिड उपकेन्द्रों को ऊर्जान्वित किया गया है।
- संचरण कम्पनी को इस वर्ष भारत सरकार की संस्था द्वारा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए **A+** रैकिंग दी गई है।

<u>वितरण</u>

- **मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना** के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत कुल 15343 करोड़ रूपये अनुदान दिया गया है। इसके तहत् सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को वास्तविक बिजली दर में काफी रियायत दी जा रही है।
- इसके तहत सिंचाई के लिए किसानों को बिजली बिल पर 92% की छूट देते हुए मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, जिससे बिजली से सिंचाई करना डीजल की तुलना में 10 गुणा से भी अधिक सस्ता पड़ने लगा है।
- **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बंध योजना** के तहत राज्य सरकार इच्छुक किसानों को मुफ्त विद्युत संबंध प्रदान किया जा रहा है। कुल निर्धारित लक्ष्य 8.40 लाख के विरूद्ध अभी तक 5.81 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। शेष सभी कनेक्शन सितम्बर 2026 तक दिये जाने का लक्ष्य है।
- RDSS योजना के तहत अब तक 920 कृषि फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। पूर्व की योजना मे निर्मित कृषि फीडरों के साथ मिला कर राज्य में अब कुल 2274 कृषि फीडरों का निर्माण हो चुका है।

- बिहार स्मार्ट प्री पेड मीटर अधिष्ठापन में अग्रणी राज्य है। अब तक पूरे राज्य में 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्री पेड मीटर अधिष्ठापन किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 वितरण कम्पनियों ने रिकॉर्ड 15109 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण करते हुए 1274 करोड़ रूपये का मुनाफा दर्ज किया। इससे न केवल वितरण कम्पनियाँ आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रही है बल्कि राज्य के लोगों को बिजली दर में प्रति यूनिट 15 पैसे की कमी भी आई है।
- ऊर्जा विभाग एवं विद्युत कम्पनियाँ बिजली उपभोक्ताआ को सुविधा एवं आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत् सुविधा ऐप, सुविधा डेस्क, फ्यूज कॉल, 1912–कॉल सेन्टर, विशेष कैम्प तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम आदि का गठन किया गया है।

ऊर्जा प्रक्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के आँकड़े।

क्रम सं0		2005	2025 (अबतक)
1.	बिजली की उपलब्धता	7–8 घंटा	24X7
2.	पीक लोड	700 मेगावाट	8005 मेगावाट
3.	उपभोक्ता की संख्या	17 लाख	212 लाख
4.	प्रतिव्यक्ति ऊजा की खपत	70 यूनिट	363 यूनिट
5.	ग्रिड की संख्या	45	170
6.	शक्ति उपकेन्द्र की संख्या	368	1263
7.	ए.टी0. एण्ड सी. हानि	59.24%	19.94%

आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में ऊर्जा प्रक्षेत्र में किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की संक्षिप्त विवरणी :

उत्पादन

- कजरा फेज–2 के अंतर्गत 116 मेगावाट सौर ऊर्जा संयत्र 241 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं कजरा फेज–1 के अंतर्गत 185 मेगावाट सौर ऊर्जा संयत्र 254 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता से उत्पादन प्रारंभ होगा।
- बिहार के 16 ग्रिड सब–स्टेशन में उपलब्ध जमीन पर 500 मेगावाट आवर बैट्री इनर्जी स्टोरेज क्षमता (BESS) के अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- बड़े पैमाने पर 11 के0वी0 कृषि एवं मिक्सड फीडरों के सोलराईजेशन का कार्य किया जायेगा जिससे क्रमवार ढ़ंग से किसान अपने खेतों के पटवन का कार्य सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे।
- पीरपैंती (भागलपुर) में थर्मल पावर प्लांट (3x800) कुल 2400 मेगावाट के निर्माण हेतु एजेंसी का चुनाव कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- दुर्गावती (कैमूर) में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना, 20 मेगावाट का नहरों के किनारे एवं 20 मेगावाट का तालाब/चौर के ऊपर Raised Structure पर सौर ऊर्जा की परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा।

संचरण

- संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्त्तमान में कुल 10 ग्रिड उपकेन्द्र निर्माणधीन है। इसे वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूरा कर लिया जायेगा। इसके द्वारा विभिन्न पावर सब–स्टेशनों के माध्यम से निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेन्द्रों यथा अमवामन (पश्चिमी चम्पारण), मेजरगंज (सीतामढ़ी), महुआ (वैशाली), मैरवा (सिवान), वारिसनगर (समस्तीपुर), चौसा (मधेपुरा), अमरपुर (बाँका), हलसी एवं बड़हिया (लखीसराय), रोह (नवादा) के निर्माण की घोषणा की गई। इस हेतु कुल 1918.28 करोड़ रूपये की योजना पर स्वीकृति दी गई है। इन ग्रिड उपकेन्द्रों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में मिशन मोड में कराया जायेगा।

वितरण

- वर्त्तमान में कार्यान्वित की जा रही 7305.05 करोड़ की RDSS योजना के Loss Reduction के तहत विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ नये कृषि फीडरों का निर्माण अगले साल पूर्ण कर लिया जायेगा। जिसके माध्यम से सभी खेतों तक सिंचाई का पानी डेडीकेटेड फीडर के माध्यम से पहूँचाने में काफी मदद मिलेगी।
- अगले वर्ष में निर्माणाधीन 41 पावर सब–स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जायेगा एवं स्वीकृत 117 नये पावर सब–स्टेशन के निर्माण का कार्य मिशन मोड में कराया जायेगा। 104 नये पावर सब–स्टेशन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इन पावर सब–स्टेशनों के निर्माण से राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
- पटना शहर के विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 296.93 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गई है। अगले वर्ष इसका कार्य मिशन मोड में कराया जायेगा।
- राज्य के पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, कैमूर, राहतास, जमुई, मुंगेर लखीसराय, नवादा, कटिहार, पूर्णियाँ एवं बाँका जिलान्तर्गत 219 गाँवों के 42621 घरों को, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी दुर्गम हैं, इन क्षेत्रों को पूर्व में Off Grid माध्यम से बिजली पहूँचाई गई थी, उसे ग्रिड के माध्यम से बिजली पहूँचाने हेतु 422.90 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना को अगले वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य है।